चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

अरे! मैं नितिन गडकरी हूं

पेज 3

दो बूंद ज़िंदगी की अभियान पोलियोग्रस्त

पेज 4

क्या वे सजग प्रहरी हैं?

पेज 5

एक लगाओ तेईस पाओ

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 8 फरवरी-14 फरवरी 2010

बिहार में बन रहा नया समीकरण

अमर सिंह की रणनीति

"राजपूत, मुसलमान और यादव का त्रिभुज बनाकर अमर सिंह हिंदुस्तान की राजनीति का रुख़ अपनी ओर करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने बिहार से कर दी है. दलीय राजनीति से इतर बिहार के तमाम विक्षुब्ध नेता अमर सिंह का दामन थामने को बेक़रार हैं."

"अमर सिंह की चाल अगर अपना रंग दिखा जाती है तो अगले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अमर सिंह की पार्टी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है. बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और फिर लोकसभा चुनाव उनका निशाना होगा."

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

रूबी अरुण

ठाकुर अमर सिंह अपनी नई पार्टी बना रहे हैं. बेहद पोशीदगी से सारे काम को अंजाम दिया जा रहा है. पार्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमर सिंह का नाम चुनाव आयोग में भेजा जा चुका है. उनके अलावा जो मुख्य भूमिका में होंगे, वे हैं पूर्व राज्यसभा सांसद एवं मुसलमानों में धर्म उपदेशक के रूप में गहरी पैठ बना चुके मौलाना ओबेदुल्ला ख़ान आज़मी और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से सांसद रह चुके एवं अब कांग्रेस में शामिल एक बेहद दबंग यादव नेता. अमर सिंह की नई पार्टी मुसलमान, यादव और राजपूत जाति के समीकरण पर आधारित होगी. देश के राजनीतिक इतिहास में जातीय राजनीति का यह अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा, जिसमें राजपूत नेताओं की गोलबंदी मुसलमान और यादव नेताओं के साथ होगी. ओबेदुल्ला ख़ान आज़मी इन दिनों अपनी-अपनी पार्टियों के रवैये से नाराज़ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के तमाम यादव, मुसलमान और राजपूत नेताओं से मिलकर उन्हें अमर सिंह की पार्टी में आने का न्यौता दे रहे हैं. ये वैसे नेता हैं, जिनकी समाज में ख़ासी दख़ल है. बिहार में ऐसे नेताओं को बटोरने का ज़िम्मा उसी दबंग यादव नेता को दिया गया है. वह जब लालू यादव की पार्टी राजद में थे तो बिहार में उनका सिक्का चलता था. बिहार के इस बाहुबली यादव नेता और मौलाना ओबेदुल्ला ख़ान आज़मी के ज़ोर पर ठाकुर अमर सिंह फरवरी के आख़िरी हफ़्ते में बिहार की राजधानी पटना में एक ज़ोरदार अधिवेशन करने की तैयारी में हैं. यह अधिवेशन एक तरह से अमर सिंह का शक्ति प्रदर्शन भी होगा, ताकि जब बिहार में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हों, उसके पहले उन्हें अपनी जोड़तोड़ की राजनीति का अंदाज़ा भलीभांति हो जाए. अमर सिंह की मंशा है कि उनकी पहली प्रयोगशाला बिहार हो. और, पहले ही वार में अमर सिंह बिहार का क़िला फ़तह करने का सपना भी देख रहे हैं. ठीक उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. तब तक अमर सिंह अपनी सियासी रणनीतियों को ठोक बजा लेना चाहते हैं, ताकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बेमिसाल हो सके और वह अपने पुराने हितैषियों और चाहने वालों को क़रारा जवाब दे सकें. अगले लोकसभा चुनाव तक अमर सिंह देश की सियासत में ध्रुवतारा की माफ़िक चमकने की हसरत रखते हैं.

नई पार्टी के गठन में अमर सिंह पूरी सावधानी बरत रहे हैं. वह अपनी पार्टी के ज़रिए समाजवाद का एक नायाब उदाहरण पेश करना चाहते हैं. राजपूत, यादव और मुसलमानों की गोलबंदी की योजना तो चल ही रही है, साथ ही दलितों और पिछड़ों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं. कभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के ख़िलाफ़ आग उगलने वाले ठाकुर साहब अब उनकी तारीफ़ में कसीदे काढ़ रहे हैं. बहन जी की क़ाबिलियत के वह कायल हो चुके हैं और यह कहने लगे हैं कि उन्होंने हर मुश्किल वक़्त में ख़ुद को साबित किया है. आज सोनिया गांधी भी उनकी नज़र में महान हो चुकी हैं. मौलाना ओबेदुल्ला ख़ान आज़मी अपनी मनमोहिनी मज़हबी तक़रीर के लिए ख़ूब जाने जाते हैं. वह जब जलसों में बोलते हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग उन्हें घंटों सुनते हैं. उनके भाषणों के कैसेट बाज़ारों में बिकते हैं. पहली बार मौलाना साहब को पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कहने पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा सांसद बनाया. फिर मौलाना आज़मी कांग्रेस में शामिल हो गए. कांग्रेस ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा में भेजा. दोबारा वहां गुंज़ाइश न देख मौलाना आज़मी ने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली. लेकिन यहां उनकी दाल नहीं गली. सपा प्रमुख ने उन्हें घुमाया-टहलाया तो बहुत, पर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की. उन्हें राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया. लेकिन इस दरम्यान वह और पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह एक दूसरे के अजीज़ ज़रूर हो गए. अब जबकि दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी, ऐसी सूरत में अमर सिंह के इस्तीफ़े के बाद मौलाना साहब ने भी मुलायम सिंह का हाथ छोड़ा और अमर के साथ हो लिए. और, अब वह अमर सिंह के निर्देशों के मुताबिक़ पार्टी को शक़्ल देने में लगे हैं. वैसे भी पार्टी में उन्हें अमर सिंह ही लेकर आए थे. वह बिहार और उत्तर प्रदेश के विक्षुब्ध नेताओं के संपर्क में लगातार बने हुए हैं. चौथी दुनिया के पास जिन नेताओं के नाम आए हैं, उनमें प्रमुख हैं पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता साधु यादव, पूर्व राजद सांसद पप्पू यादव, पूर्व जदयू सांसद प्रभुनाथ सिंह, राजद नेता गिरधारी यादव, राजद नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन. राजद छोड़कर समाजवादी पार्टी में शरण लेने वाले और अब ख़ुद की पार्टी बनाकर राजनीति करने वाले बाहुबली विधायक ददन सिंह यादव, अनवारुल हक़, रमई राम इत्यादि नामों की बड़ी सूची है. इसके अलावा कांग्रेस के नाराज़ नेताओं से भी बातचीत चल रही है. लोजपा, जदयू और राजद के नेताओं से गुणा-भाग की राजनीति परवान पर है. मतलब यह कि सभी पार्टियों के चुनिंदा नेताओं को मिलाकर अमर सिंह की नई पार्टी मुक़म्मल होगी.

अमर सिंह इन नेताओं से सामंजस्य बिठाने की अहम ज़िम्मेदारी कांग्रेस नेता साधु यादव को देना चाहते हैं. हालांकि साधु यादव इस ख़बर को बिल्कुल ग़लत क़रार दे रहे हैं. वह कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा ज़ाहिर करते हैं, पर उनके मौजूदा आवास 15 जनपथ पर मौलाना ओबेदुल्ला आज़मी का आना-जाना बदस्तूर बना हुआ है. दरअसल साधु यादव बिहार में एक दबंग और जनाधार वाले यादव नेता के रूप में जाने जाते हैं. राजद अध्यक्ष लालू यादव के साले के तौर पर साधु ने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया, पर धीरे-धीरे साधु ने अपना अलग आधार बनाया. लालू के कंधे पर पैर रखकर छलांग लगाई और अनबन होने की सूरत में कांग्रेस में शामिल हो गए. लेकिन साधु का पार्टी बदलना उनके मतदाताओं को रास नहीं आया और वह लोकसभा चुनाव हार गए. हारने के बाद भी साधु यादव के साथ उनके समर्थकों की जो भीड़ है, उसमें यादव, मुसलमान, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत युवकों की तादाद ज़्यादा है. इसके अलावा साधु ने अपना आधार दक्षिण भारत में भी बनाना शुरू कर दिया. वहां के यादवों का भी समर्थन साधु को मिलने लगा है. बिहार में लालू यादव से पंगा लेने या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से दो-दो हाथ करने में साधु यादव से बेहतर विकल्प अमर सिंह को दिखाई नहीं दे रहा है. हालांकि साधु यादव की छवि एक अपराधी और बाहुबली नेता की रही है, लेकिन यह छवि जातीय कारक से कहीं दब सी जा रही है. अमर सिंह इस जुगत में हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर वह एक क्षत्रिय नेता के तौर पर स्थापित हों. मौलाना

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नई पार्टी के गठन में अमर सिंह पूरी सावधानी बरत रहे हैं. वे अपनी पार्टी के ज़रिए समाजवाद का एक नायाब उदाहरण पेश करना चाहते हैं. राजपूत, यादव और मुसलमानों की गोलबंदी की योजना तो चल ही रही है, साथ ही दलितों और पिछड़ों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं. कभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के ख़िलाफ़ आग उगलने वाले ठाकुर साहब अब उनकी तारीफ़ में कसीदे काढ़ रहे हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि इसे उस समय जोरदार तरीके से अमल में लाया गया, जब मूल रूप से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

ख़तरे की घंटी

जो होने जा रहा है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. केंद्र सरकार ने काम के प्रति लेटलतीफ बाबुओं को सबक सिखाने का निर्णय लिया है. अगर इस पवित्र मक़सद में कामयाबी मिल जाती है तो हम जिस बाबूगिरी को जानते हैं, उसका दौर समाप्त हो जाएगा. दरअसल यह फ़ैसला सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय से आया है. प्रधानमंत्री की दिली इच्छा है कि सरकार में कामकाज के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए. सूत्रों का कहना है कि सरकार सेवा के स्तर पर क़रार (सर्विस लेवल एग्रीमेंट) की परिकल्पना को वास्तव में लागू करना चाहती है. इसके बाद बाबू जिन कामों को अंजाम देंगे, उसके प्रति उनकी जवाबदेही भी तय हो जाएगी. ज़ाहिर है कि वैसे बाबू, जिनकी फाइल पर कुंडली मारकर बैठ जाने की आदत है या फिर जो अनावश्यक रूप से काम में देरी करते हैं, अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ड्यूटी के प्रति लापरवाही करने पर उन्हें जुर्माना चुकाना होगा. इससे पहले कि इस योजना को पूरे देश में कार्यान्वित किया जाए, आगामी अप्रैल माह में इसे दिल्ली में लागू किया जाएगा. केंद्र ने इसके लिए कुछ बुनियादी सेवाओं को चिन्हित किया है. राशनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना, मतदाताओं का पंजीयन तथा वेल्यू एडेड टैक्स के अधीन पंजीकरण आदि कुछ ऐसे काम हैं, जिन पर इस योजना के अंतर्गत निगरानी रखी जाएगी. इसलिए वे बाबू, जो कई दूसरे विभागों के साथ-साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कर, परिवहन, नगर निगम आदि का काम देख रहे हैं, उन पर विशेष तौर से निगरानी रखी जाएगी और उनकी तनख्वाह के रुपये की गड्डी थोड़ी पतली हो जाएगी. लेकिन जब तक यह योजना कार्यान्वित नहीं हो जाती है, हमें कम से कम यह प्रार्थना तो अवश्य ही करनी चाहिए कि यह प्रस्ताव क़ायदे क़ानून की परवाह न करने वाले बाबुओं के लिए चेतावनी की घंटी साबित हो.

शानदार योजना

पहले तो उम्मीद जगाई. फिर इस पर ख़ूब चर्चे हुए कि सरकारी क्षेत्र से अलग प्रोफेशनल्स की सेवाएं ली जाएंगी. लेकिन लगता है कि सरकार चुपके से इस योजना से पीछे हटने वाली है. जब इसके लिए प्रयास किए गए, ख़ासतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नियामक संस्थाओं के लिए प्रमुखों की तलाश शुरू हुई तो कई मामलों में यह देखा गया कि सरकार ने वहां सरकारी बाबुओं या पूर्व बाबुओं को जमा रखा है.

ग़ौर करने वाली बात यह है कि इसे उस समय ज़ोरदार तरीक़े से अमल में लाया गया, जब मूल रूप से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया. उस समय कई लोग हैरान रह गए, जब सरकार ने 1968 बैच के हरियाणा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को नियुक्ति पत्र थमा दिया. ऐसा कई दूसरी महत्वपूर्ण नियुक्तियों में भी हुआ, जबकि सरकार ने अपने चहेतों को उपकृत करने का काम किया. टेलीकॉम विभाग की निगरानी जे एस शर्मा कर रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के हैं और 1977 बैच के अधिकारी हैं. ठीक इसी तरह भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की कमान बृजेश्वर सिंह के हाथ में है. वह 1975 बैच के तमिलनाडु के अधिकारी हैं. हाल फ़िलहाल इसमें अगर कहीं कोई अपवाद नज़र आ रहा है तो वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति में. ख्यातिनाम अर्थशास्त्री कौशिक बसु वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं. उनकी शानदार अकादमिक पृष्ठभूमि रही है और सरकारी कामकाज की यह उनकी पहली ज़िम्मेदारी है. लेकिन इससे जो संदेश बाहर आया है, वह यह कि सरकार का इरादा चाहे जो भी रहे, लेकिन वह जांचा-परखा तरीक़ा ही अख्तियार करना चाहती है.

अमर सिंह की रणनीति

अमर सिंह चाहते हैं कि देश की राजनीति की मुख्यधारा में राजपूतों का वर्चस्व हो, ताकि आने वाले दिनों में एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अमर सिंह की सामयिक महत्ता बनी रहे.

अमर सिंह चाहते हैं कि देश की राजनीति की मुख्यधारा में राजपूतों का वर्चस्व हो, ताकि आने वाले दिनों में एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर अमर सिंह की सामयिक महत्ता बनी रहे. इसके लिए वह पूर्व जदयू नेता एवं निर्दलीय सांसद दिग्विजय सिंह से अपनी गांठ जोड़ना चाहते हैं. लेकिन फ़िलहाल दिग्विजय सिंह संशय की स्थिति में हैं. उन्हें इस बात का डर है कि कहीं अमर सिंह का प्रयोग असफल रहा तो उनकी राजनीतिक साख को झटका लग सकता है. लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर अमर सिंह की रणनीति बिहार में कामयाब रहती है और फरवरी के आख़िरी या मार्च के शुरुआती हफ़्ते में पटना में होने वाला उनका अधिवेशन सफल रहता है तो दिग्विजय सिंह भी अमर सिंह के साथी बन सकते हैं. लेकिन, एक बात जो तय है, वह यह कि जदयू के बागी नेता प्रभुनाथ सिंह अमर सिंह की पार्टी में महत्वपूर्ण पद संभालने जा रहे हैं. प्रभुनाथ सिंह बिहार की राजनीति में ख़ास मायने रखते हैं. वह राजपूत जाति के बेहद अहम नेता हैं. छपरा, सीवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, सासाराम सरीख़े भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रभुनाथ सिंह की पकड़ बेहद मज़बूत है. प्रभुनाथ सिंह पिछले लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री से ख़ासे ख़फा हैं. वह खुलेआम उन्हें ललकार रहे हैं. आर-पार की लड़ाई का न्यौता दे रहे हैं. अमर सिंह जानते हैं कि प्रभुनाथ सिंह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू का कितना बड़ा नुक़सान कर सकते हैं. लिहाज़ा बिहार में अपनी नई पार्टी का पैर ज़माने के लिए वह प्रभुनाथ सिंह का इस्तेमाल बख़ूबी करेंगे. साथ में रमई राम सरीखे दलित नेताओं का साथ भी अमर सिंह की पार्टी को बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा. अब यहां सवाल उठता है कि राजपूत, यादव और मुसलमान की अमर सिंह की यह तिकड़ी बिहार विधानसभा चुनाव में माई समीकरण के जनक लालू यादव या अन्य नेताओं को कितना नुक़सान पहुंचाएगी. ख़ास तौर पर मुसलमान मतदाताओं का झुकाव किस ओर ज़्यादा होगा. राजद में मुस्लिम चेहरे के रूप में सिर्फ़ अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं. सिद्दीकी कहने को तो मुसलमान नेता हैं, पर उनकी पकड़ बिहार की मुसलमान बिरादरी पर उतनी गहरी नहीं, जो लालू यादव की नैया पार करा दे. लोजपा में इन दिनों वैसे भी स्थापित नेताओं का अकाल पड़ा है. इसलिए मुसलमान के नाम पर कोई जानी पहचानी शख्सियत पार्टी में मौजूद नहीं है. कांग्रेस अभी अपनी जड़ तलाशने में ही जुटी है. जदयू में कोई बड़ा नाम है नहीं. और भाजपा का वैसे भी मुसलमान नेताओं से वास्ता नहीं रहता. ऐसी हालत में मौलाना ओबेदुल्ला ख़ान आज़मी निश्चित तौर पर मुसलमानों के बड़े नेता के तौर पर बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी अमर सिंह की पार्टी को मज़बूत करेंगे. वैसे भी धर्मगुरु और उपदेशक होने के नाते मौलाना आज़मी मुसलमान बिरादरी में एक ऊंचा स्थान रखते हैं. और, यह बात अमर सिंह की नई पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी.

मतलब यह कि राजपूत, मुसलमान, यादव समीकरण को आधार बनाकर अमर सिंह हरेक जाति में सेंध लगाएंगे और अपनी पार्टी की नींव मज़बूत करेंगे. इसकी ख़ातिर ठाकुर अमर सिंह कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहते. यही वजह है कि उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण नीचे से करने के बजाय ऊपर से करना शुरू किया है. यह बात भी दीगर है कि नई पार्टी के गठन में ख़र्च बेशुमार है. उसमें भी तब, जबकि पार्टी में जाने-माने बड़े नेताओं को शामिल होना है. अब पार्टी अध्यक्ष होने के नाते यह सारा इंतजाम करना तो ठाकुर साहब को ही है, पर उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं. वह तमाम इंतजामात बख़ूबी कर रहे हैं. उनकी हरसंभव कोशिश यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जो स्थितियां बनें, उनमें उनकी पार्टी के हाथ सरकार बनाने की चाबी हो. वह निर्णायक भूमिका में हों. बिहार में अगर उन्हें यह उपलब्धि हासिल हो गई तो अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पुराने सखा मुलायम सिंह यादव के मुकाबले चुनावी अखाड़े में उतरने का दम भर सकती है. यक़ीनन इसका नतीजा अगले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो यह देखना है कि अमर सिंह अपनी पार्टी के ज़रिए बिहार में जो नई राजनीतिक ताक़त पैदा करना चाह रहे हैं, वह किसका नुक़सान करेगी. लालू का? नीतीश का? या कांग्रेस का? इसके लिए कम से कम अमर सिंह की पार्टी के पहले अधिवेशन का इंतज़ार तो करना ही होगा.

ruby@chauthiduniya.com

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

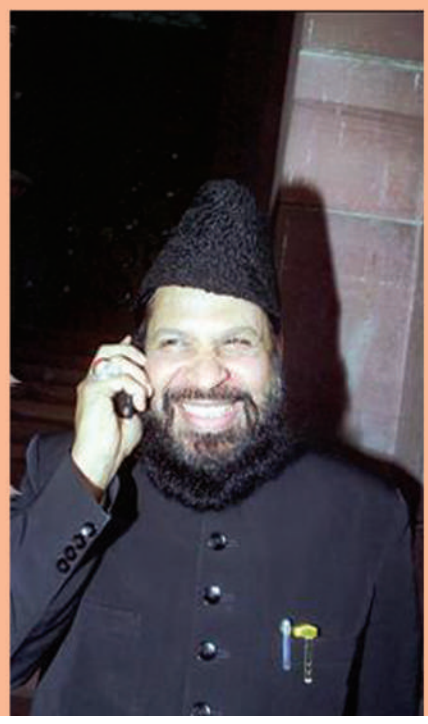

पृष्ठ एक का शेष

आजमी मुसलमान नेता और साधु यादव यादवों के नेता के रूप में अपनी धमक जगाएं. दलित वोटों को बटोरने के लिए उत्तर प्रदेश के एक बड़े दलित नेता से बातचीत अंतिम चरण में है. बिहार में राजपूत जाति का वोट लगभग 5 फीसदी, मुसलमानों का 11 फीसदी और यादवों को 18 फीसदी है. अमर की नजर इसी वोट बैंक पर है.

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 1 अंक 48,
दिल्ली, 8 फरवरी–14 फरवरी 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–47839990/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4 बिहार व झारखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

थोड़ी देर बाद उस शख़्स ने दिग्विजय सिंह से कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना? दिग्विजय सिंह ने कहा, हां, मैं आपको नहीं पहचान सका. तब उस शख़्स ने कहा, मैं आपसे चार-पांच बार मिल चुका हूं.

अरे! मैं नितिन गडकरी हूं

मनीष कुमार

भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन का मौक़ा था. जन्मदिन की बधाई देने के लिए देश के कई नेता मौजूद थे. इस खास मौक़े पर अनूप जलोटा सभी को भजन एवं ग़ज़लें सुना रहे थे. सामने सोफे पर लालकृष्ण आडवाणी और बिहार के निर्दलीय सांसद दिग्विजय सिंह बैठे थे. सोफे पर तीसरे शख़्स की जगह ख़ाली थी. उस ख़ाली जगह के बाद वाले सोफे पर अरुण जेटली बैठे थे. इसी दरम्यान अचानक एक शख़्स का आगमन हुआ. उसने पहले लालकृष्ण आडवाणी को प्रणाम किया, फिर दिग्विजय सिंह को प्रणाम करके वह ख़ाली जगह पर बैठ गया. उसके बाद बातचीत शुरू हुई. थोड़ी देर बाद उस शख़्स ने दिग्विजय सिंह से कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना? दिग्विजय सिंह ने कहा, हां, मैं आपको नहीं पहचान सका. तब उस शख़्स ने कहा, मैं आपसे चार-पांच बार मिल चुका हूं. मेरी आपसे उस वक्त मुलाक़ात हुई थी, जब आप मंत्री हुआ करते थे. इसके बाद भी जब दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि मैं आपको नहीं पहचान सका तो उस शख़्स ने कहा, अरे... मैं नितिन गडकरी हूं.

जब यह वार्तालाप हो रहा था, उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी अपने माथे पर हाथ रखकर अफ़सोस जता रहे थे. थोड़ी देर बाद नितिन गडकरी वहां से उठे और उन्होंने समारोह में मौजूद दूसरे लोगों के पास जाकर उनसे मिलना शुरू किया. तब दिग्विजय सिंह ने अरुण जेटली से कहा कि आप लोगों ने कैसा अध्यक्ष चुना है. इस बात से अरुण जेटली भी हैरान हो गए. उन्होंने दिग्विजय सिंह से कहा कि अब देखिए, जिसे आप ही नहीं पहचान सके, उसे जनता कैसे पहचानेगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं. उस पूरी भीड़ में ऐसा लग रहा था कि सारे नेता एक तरफ़ हैं और उनके बीच कोई कॉरपोरेट कल्चर में पला-बढ़ा मार्केटिंग करने वाला शख़्स घूम-घूमकर सबको नमस्ते कर रहा है. हो सकता है, कुछ लोगों को यह लगे कि नितिन गडकरी सीधे-सादे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, इसलिए वह घूम-घूमकर लोगों से मिल रहे हैं. यह एक सीधे-सादे इंसान की क्वालिटी तो हो सकती है, लेकिन एक राष्ट्रीय नेता की निशानी कतई नहीं.

नितिन गडकरी के सामने चुनौतियों का पहाड़ है. देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष होना कोई आसान काम नहीं है. उसके कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है. प्रजातंत्र में विपक्षी पार्टी के नेता की ज़िम्मेदारी सरकार चलाने वाली पार्टी से कई मायने में कहीं ज़्यादा होती है. अगर यह कंधा कमज़ोर हो तो देश की राजनीति पर इसका बुरा असर पड़ता है. ऐसे व्यक्ति के पास देश को अलग राह दिखाने की दूरदर्शिता और व्यक्तित्व का होना अनिवार्य है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सर्वसम्मति से चुना हुआ अध्यक्ष बना तो सकता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय नेताओं की कतार में खड़े होने की हैसियत नहीं दिला सकता. लगता है, नितिन गडकरी को सबसे पहले अपनी पहचान की लड़ाई लड़नी है.

भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पहचान के संकट से गुज़र रही है. वह विचारधारा, संगठन और नेतृत्व को लेकर अपनी पहचान के बारे में कुछ तय नहीं कर पा रही है. ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक ऐसे शख़्स को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जिसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है. ऐसे व्यक्तित्व को अध्यक्ष बनाने का नुक़सान भाजपा झेल रही है. विडंबना यह है कि पिछले कुछ सालों से भाजपा अपनी पहचान को लेकर ही भ्रम की स्थिति में है. अब ऐसे नाजुक मोड़ पर नया अध्यक्ष मिला है, जिसकी ख़ुद की कोई पहचान नहीं है. नए अध्यक्ष की परेशानी दोगुनी है. एक तो उन्हें पार्टी के अंदर अपनी पहचान बनानी है, ख़ुद को पार्टी का नेता साबित करना है और दूसरी यह कि उन्हें पार्टी के बाहर भी यह साबित करना होगा कि वह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं. नितिन गडकरी को ख़ुद की पहचान बनाने और राष्ट्रीय स्तर का नेता साबित करने में काफ़ी वक्त लग रहा है. अभी तक उन्होंने कोई बड़ी रैली कर अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश भी नहीं की है. नितिन गडकरी ने अब तक यह ख़ुलासा नहीं किया है कि राहुल गांधी के जवाब में उनकी क्या रणनीति है. पार्टी युवाओं को जोड़ने के लिए किस फ़ार्मूले का इस्तेमाल करेगी. ग्रामीण मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पार्टी क्या करने वाली है, इसका भी ख़ुलासा नहीं हुआ है. नितिन गडकरी जबसे अध्यक्ष बने हैं, तबसे उन्होंने टेलीविजन चैनलों के माध्यम से ही अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक पहुंचने की कोशिश की है. मीडिया के ज़रिए राजनीति करने का ख़ामियाज़ा भारतीय जनता पार्टी बहुत भुगत चुकी है. नए अध्यक्ष को यह समझना चाहिए कि देश में सफल राजनीति करने के लिए टीवी चैनलों के स्टूडियो के बजाय जनता के बीच जाने की ज़रूरत है.

फोटो : प्रभात पाण्डेय

भाजपा के वरिष्ठ नेता तमाशबीन बनकर नए अध्यक्ष के क्रियाकलापों को देख रहे हैं. नए अध्यक्ष कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए सब कुछ शांत-शांत लग रहा है, जबकि नितिन गडकरी को बतौर अध्यक्ष एक बिखर रही पार्टी को एकजुट रखना और उसे अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देने लायक बनाना है. भारतीय जनता पार्टी के कमज़ोर होने की मुख्य वजह निराश कार्यकर्ता, समर्थकों का पार्टी से टूटा हुआ विश्वास और बिना जनसमर्थन वाले नेता हैं. नितिन गडकरी ने अब तक एक भी ऐसा काम नहीं किया है, जिससे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़े या समर्थकों का विश्वास फिर से जीता जा सके. नितिन गडकरी के व्यवहार से ऐसे कोई संकेत भी नहीं मिल रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में निराशा बढ़ने लगी है. अब तो लोग यह कहने लगे हैं कि नितिन गडकरी के आने के बाद भी पार्टी के काम करने के तरीक़े में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं हुआ है. बस, पहले से चल रही गुटबाजी में एक और नया गुट पैदा हो गया है. बदलाव सिर्फ़ इतना हुआ है कि पार्टी के शीर्ष पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना नुमाइंदा बैठा दिया. पार्टी के कई पुराने कार्यकर्ता अब यह कहने लगे हैं कि अगर नितिन गडकरी इसी तरह एक-दो महीने तक शांत बैठे रहे या फिर पार्टी के सकारात्मक बदलाव के कामों को टालते रहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के लिए वह बौने साबित होंगे.

भारतीय जनता पार्टी और नितिन गडकरी इस वक्त अग्निपथ पर चल रहे हैं. यह समय उनके लिए अग्निपरीक्षा का है. गडकरी को अपने व्यक्तित्व के साथ-साथ पार्टी को मज़बूत करना है. समस्या यह है कि पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और नेताओं का धैर्य ख़त्म हो रहा है. नितिन गडकरी के पास ख़ुद को साबित करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है.

manish@chauthiduniya.com

SAVE CASH FOR YOUR BUSINESS | USE BARTER

We are one of the worlds leading Barter Exchange Company operating out of India, Australia, New Zealand and Costa Rica, servicing over 5000 member businesses worldwide

In India, BBX works with more than 600 businesses and professionals from a wide spectrum of industries, facilitating Cashless Trade and creating New Business Opportunities

BBX now invites **Franchisees** from different parts of the country to be a part of this unique business opportunity

To know more, please contact:
Sachin at 9871531759 or 40587777
or email us at info@ebbx.in

BBX

BBX India Pvt. Ltd.
E-8, 2nd Floor, Kalkaji, New Delhi 19
011 - 4058 7777 | info@ebbx.in | www.ebbx.in
INDIA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND | COSTA RICA

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से पोलियो वैक्सीन रखने के लिए आइस लैंड रेफ़्रीजरेटर (आईएलआर) की व्यवस्था की गई है, जो बिजली जाने के 48 घंटे बाद तक कोल्ड चेन बनाए रखता है.

हॉकी के सहारे राजनीति की कोशिश

संध्या पाण्डे

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में भी असामान्य राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने *मध्य प्रदेश बनाओ यात्रा* एवं भारतीय हॉकी टीम के माध्यम से राज्य स्तर पर अपनी पकड़ मज़बूत करने और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई छवि बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है. शिवराज सिंह इन दिनों सार्वजनिक मंचों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शैली में भाषण देते हुए नज़र आते हैं. नितिन गडकरी के आने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में नए नेताओं की संभावनाओं को परखते हुए शिवराज का यह क़दम स्वयं के राजनीतिक भविष्य को संरक्षित करने की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सामान्य वार्तालाप, सामान्य शैली और सहज अभिव्यक्ति की कोशिश. इसी का प्रदर्शन *मध्य प्रदेश बनाओ यात्रा* के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री द्वारा करने का प्रयास किया गया है, जिसमें वह सफल भी रहे. अपनी यात्रा के प्रथम चरण में उन्होंने अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला के आदिवासी ज़िलों में लंबा समय गुजारा. यह *मध्य प्रदेश बनाओ यात्रा* का शुभारंभ था. दूसरे चरण में अब तक घोषित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें धार, झाबुआ और अलीराजपुर अंचल में जाना है. दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के 18 सदस्यों को एक–एक लाख रुपये और खिलाड़ियों को भत्ते के रूप में 50 लाख रुपये की राशि मुख्यमंत्री ने सीधे प्रदान की. मुख्यमंत्री का यह क़दम राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी जैसे पिछड़े खेल को बढ़ावा देने वाला नज़र आता है, परंतु प्रोत्साहन की इस योजना के पीछे केंद्र सरकार की हॉकी विरोधी नीतियों का विरोध और हॉकी संघ की राजनीति पर शिवराज की राजनीति भी साफ़ नज़र आती है. शिवराज महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य को अपनी बेटी घोषित करते हैं. वह लाडली लक्ष्मी योजना की तरह महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य की हरसंभव मदद के लिए तत्पर हैं.

शिवराज की राजनीति के इन दो पहलुओं पर एक और स्पष्ट छाप नज़र आती है. सार्वजनिक मंचों पर भाषण देने की उनकी शैली बहुत हद तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलती–जुलती है. अटल जी की तरह हाथों को घुमाना, गर्दन को झटका और शब्दों पर जोर देना, एक शब्द और दूसरे शब्द के मध्य थोड़ा विराम रखना शिवराज की भाषण शैली का हिस्सा बनता जा रहा है. लगता है कि भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर हुए परिवर्तनों से शिवराज उत्साहित हैं और वह अपने भविष्य को राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षित करना चाहते हैं. उधर उन्हें लगता है कि हॉकी राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्थापित कर सकती है और शिवराज इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते.

भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में नितिन गडकरी के आगमन के बाद शिवराज ने ख़ुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. उन्होंने सुझाव दिया है कि खेलों की राजनीति से नेताओं को अलग हो जाना चाहिए. उनके इस सुझाव को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के पहले अरुण जेटली एवं नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का क़द छोटा करने की एक सुनियोजित कोशिश माना जा रहा है. शिवराज यह जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सुरेश पचौरी के रहते कांग्रेस संगठन में गुटबाजी ज़िंदा रहेगी. इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस में कांग्रेस (एस) और कांग्रेस (बी) का दबदबा है. इन स्थितियों में भाजपा सामान्य राजनीतिक अवसरों पर किसी परिवर्तन के विषय में कभी भी सोच सकती है. शिवराज सिंह ने भाजपा में स्वयं को गुटबाजी की राजनीति से इतना दूर रखा है कि दल का सामान्य नेता सामान्य राजनीतिक क्रियाकलाप के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति या अनुशंसा का मोहताज नहीं है. मुख्यमंत्री भाजपा के मौजूद गुटों में से किसी के भी साथ नहीं हैं. प्रशासनिक रूप से शिवराज सिंह अब तक के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे. पिछली दिग्विजय सिंह सरकार से कई गुना अधिक भ्रष्टाचार भाजपा के इस शासनकाल के दौरान हुआ. दिग्विजय सिंह ने भ्रष्टाचार के कॉरपोरेट कल्चर को विकसित किया था, वहीं भाजपा सरकार के दौरान इसका पंचायतीकरण कर दिया गया. शिवराज के कार्यकाल के दौरान विकास की कई योजनाओं पर कार्य हुआ, परंतु जो कार्य स्थायी रूप से होना था, उसे बार–बार करके अवैध धनार्जन की कोशिश की गई. *कांग्रेस मध्य प्रदेश बनाओ यात्रा* का व्यापक विरोध करने की कोशिश कर रही है, परन्तु उसके प्रदेश अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय निकाय चुनाव और बाद में पंचायत चुनाव तक दल को लगातार हार ही दिलवाई है. सुरेश पचौरी अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी जनांदोलन खड़ा नहीं कर सके , जिससे कांग्रेस को फ़ायदा होता.

कांग्रेस सिर्फ़ एक लाचार और कमज़ोर विपक्ष के रूप में मौजूद है. दिग्विजय सिंह अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए पचौरी के मार्ग में केवल रोड़े अटकाने का काम करते रहे. कमलनाथ के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवसायिक हितों के संरक्षण का एक माध्यम है. सिंधिया ग्वालियर से आगे बढ़ पाने की कभी हिम्मत नहीं कर सके . कांग्रेस की इसी स्थिति के चलते भाजपा को अपनी *मध्य प्रदेश बनाओ यात्रा* बिना किसी बाधा पूरा करने का अवसर मिल गया है. राष्ट्रीय राजनीति में शिवराज नरेंद्र मोदी के विपरीत एक सामाजिक छवि के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं. राज्य में चल रही तमाम राजनीतिक कोशिशें एक व्यक्ति के उत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम कर रही हैं. देखना यह है कि नितिन गडकरी की पारी समाप्त होने से पहले शिवराज राजनीति की किन ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं.

नितिन गडकरी : शिवराज के साथ हैं

सुरेश पचौरी : गुटबाजी में व्यस्त

feedback@chauthiduniya.com

दो बूंद जिंदगी की अभियान पोलियोग्रस्त

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश को लोग अक्सर उल्टा प्रदेश कहकर मज़ाक उड़ाते हैं. लेकिन, यह एक कड़वी हक़ीक़त है. आज सारी दुनिया को पोलियो जैसी महामारी से मुक्त किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में पोलियो के शिकार बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. अगर यह पोलियो मुक्ति अभियान के प्रति राज्य सरकार की लापरवाही नहीं है तो आख़िर क्या है? मालूम हो कि मुख्यमंत्री मायावती के संसदीय क्षेत्र रह चुके अंबेडकर नगर में पिछले दिनों सड़क पर एक पोलियो पैकेट पड़ा मिला, जिस पर कटुई लिखा हुआ था. ज़ाहिर है, यह दवा कटुई क्षेत्र के लिए थी. इतना ही नहीं, बागपत जनपद के बिनौली ब्लॉक के घनौरा सिल्वर नगर गांव में पोलियो दवा पिलाने के कुछ देर बाद ही अब्दुल रहीम के डेढ़ माह के बच्चे अलतमस की मौत हो गई. परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को पल्स पोलियो अभियान की समीक्षा करने की फुर्सत तक नहीं है. राजधानी लखनऊ में एक स्वयंसेवी संगठन ने जब इस अभियान के तहत ग़लत दवा पिलाने की शिक़ायत साक्ष्यों सहित की, तब चार कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई. अभियान से जुड़े लोगों की सुरक्षा भी एक मसला है. बदायूं जनपद के परमानंद गांव में शराबियों ने पोलियो की दवा पिलाने जा रहे महिला दल पर हमला बोल दिया. टीम ने किसी तरह ग्राम प्रधान के घर में छुपकर अपनी जान बचाई.

विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजी रिपोर्ट के मुताबिक़, उत्तर प्रदेश में पोलियो से प्रभावित 15 मामले सामने आए हैं. सभी पी–थ्री के मामले हैं. अलीगढ़ में तीन, गाजियाबाद, मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर एवं बुलंदशहर में दो–दो, बदायूं, गौतमबुद्ध नगर, मथुरा एवं हाथरस में पी–थ्री पोलियो के एक–एक मामले पाए गए. यह रिपोर्ट 2009 में लिए गए नमूनों की जांच पर आधारित है. कल तक यह कहा जाता था कि ऐसे ज़्यादातर मामले अशिक्षित मुस्लिम समुदाय में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो नए मामले प्रकाश में आए हैं, उनमें अधिकतर हिंदू समुदाय के हैं. परिवार कल्याण विभाग पोलियो अभियान पर हर माह औसतन 50 लाख रुपये ख़र्च कर रहा है. विभाग की कोशिश रहती है कि किस तरह आंकड़ों में बाजीगरी करके पोलियो के मामले कम दिखाए जाएं. सवा साल के इस्लाम का मामला लें. इस्लाम के पोलियोग्रस्त होने की बात पता चलते ही तीन जनपदों यानी लखनऊ, बाराबंकी और गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग इस कोशिश में जुट गया कि कैसे गेंद को दूसरे के पाले में डाला जाए. इस्लाम इस समय लखनऊ में फैजाबाद रोड पर रेलवे स्टेशन के पास झुग्गी में अपने पिता कांशीराम के साथ रहता है, जो मूल रूप से बाराबंकी के रहने वाले हैं. बच्चे का ननिहाल गाजियाबाद के लोनी इलाक़े में है.

पोलियो क्या है?

एनफेंटाइल पैरालिसिस या एक्यूट एंटीरियर पोलियोमाइलिटिस का दूसरा नाम है पोलियो. यह महामारी में होता है, लेकिन हर समय मौजूद रहता है. हालांकि यह अक्सर बच्चों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन यह किसी को भी हो सकता है. जो सबसे आम किस्म का पोलियो है, उससे एक–दो दिन तक सिरदर्द, बुख़ार, गले एवं पेट में ख़राबी आदि शिक़ायतें होती हैं. पोलियो के जिन मामलों की शिनाख्त हो जाती है, उनमें आधे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, 30 प्रतिशत पर बाद में भी हल्का प्रभाव रहता है, 14 प्रतिशत को गंभीर पैरालिसिस हो जाता है और छह प्रतिशत की मौत भी हो सकती है.

पिछले एक दशक के दौरान देश भर में पोलियो के 2000 मामले प्रकाश में आ चुके हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार तो सर्वाधिक प्रभावित प्रदेशों में शामिल हैं. लोग सवाल करते हैं कि क्या पोलियो ओरल वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और पोलियो वायरस को भगाने में कारगर है? पांच साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाना मुश्किल है. इसमें बच्चों का स्वास्थ्य आड़े आता है. बच्चा कभी बीमार होता है तो कभी कई दूसरे कारण इसमें आड़े आते हैं. इसलिए हर पल्स पोलियो अभियान में बच्चों को दवा अवश्य पिलानी चाहिए.

दो दशक पहले 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को पोलियो मुक्त कराने का सपना देखा था. अब तक 211 देशों में यह सपना पूरा हो चुका है. उनमें नेपाल एवं बांग्लादेश भी शामिल हैं. लेकिन, भारत में ज्यों–ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया वाली कहावत चरितार्थ हुई. पोलियो के नाम पर पिछले 15 वर्षों के दौरान सरकारी धन की जमकर लूटपाट हुई. 1995 से 2000 के बीच पोलियो रोकथाम अभियान में उल्लेखनीय प्रगति हुई. वर्ष 2001 में पोलियो पीड़ितों की संख्या 216 थी. जबकि 2002 में 1241, 2003 में 24 और 2004 में 05. एकबारगी लगने लगा कि अब उत्तर प्रदेश को पोलियो से मुक्ति मिलने वाली है, लेकिन 2007 में 135 मरीज मिलने के बाद सरकारी दावों की कलई खुल गई. जांच–पड़ताल में मालूम हुआ कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में पोलियो ड्राप्स की जगह पानी पिलाकर ही कर्तव्य की इतिश्री मान ली गई. सोरो ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोलियो दवा की एक वायल से 40 से अधिक बच्चों को दवा पिला दी गई. जबकि एक वायल से अधिकतम 17 बच्चों को दवा दी सकती है. अभियान से जुड़े पवन कुमार कहते हैं, वैक्सीन की कोल्ड चेन को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं. कहा जाता है कि गांव में बिजली न होने के कारण कोल्ड चेन बरकरार नहीं रह पाती और वैक्सीन प्रभावहीन हो जाती है. यह सभी बातें तार्किक नहीं हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से पोलियो वैक्सीन रखने के लिए आइस लैंड रेफ़्रीजरेटर (आईएलआर) की व्यवस्था की गई है, जो बिजली जाने के 48 घंटे बाद तक कोल्ड चेन बनाए रखता है. कम विद्युत आपूर्ति वाले क्षेत्रों में जेनरेटर की व्यवस्था है.

वर्ष 2002 में देश में जो 1600 मामले सामने आए, उनमें 1240 उत्तर प्रदेश के थे. चिकित्सा वैज्ञानिकों का मानना है कि 2002 में प्रतिरक्षण अंतराल पैदा होने से पोलियो की शिक़ायतें बढ़ीं. यह अंतराल तब होता है, जब बड़ी संख्या में बच्चों को बहुत कम बार पोलियो वैक्सीन मिलती है. मुरादाबाद मंडल की हालत सबसे अधिक चिंताजनक है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 15 सालों से चल रहे पोलियो अभियान का कोई बेहतर परिणाम नहीं निकला. उन्होंने कहा कि विभाग के ज़िम्मे सौंपे गए चेचक अभियान को शत–प्रतिशत परिणाम के बाद 1974 में बंद कर दिया गया था. लेकिन, पोलियो मुक्ति अभियान नौकरशाही के हावी होने की वजह से सफल नहीं हो पा रहा है. 15 दिनों का जेई टीकाकरण कार्यक्रम सात दिनों में पूरा कर लिया गया, क्योंकि अफ़सरों का फरमान यही था. जबकि 14 लाख बच्चों का टीकाकरण संभव नहीं है. प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. अरविंद कुमार जैन कहते हैं कि अभी तक उसी वैक्सीन से काम लिया जा रहा है, जिसकी आदत पोलियो वायरस को हो गई है. यदि पोलियो पर जड़ से काबू पाना है तो नई वैक्सीन के साथ नए सिरे से काम शुरू करना होगा. वैक्सीन पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि महोबा में तीन बार ड्राप पीने वाला बच्चा भी पोलियो का शिकार हो गया. उधर सहारनपुर में भी पोलियो का एक मामला प्रकाश में आया है. प्रशासन ने यहां के गंगोह थाना अंतर्गत कुंडालकलां, नया कुंडा, घटमपुर, ढलावली, खानपुर एवं बालू आदि इलाक़ों को इस दृष्टिकोण से संवेदनशील माना है. वहां पर पोलियो ड्राप के अलावा बीसीजी एवं डीपीटी के टीकों की भी व्यवस्था की जा रही है.

feedback@chauthiduniya.com

अख़बार अक्सर आज़ादी का राग अलापते हैं. लेकिन किसकी आज़ादी? कैसी आज़ादी? कॉरपोरेट समूहों का चेहरा चमकाने की, सरकारी धतकरमों पर परदा डालने की और भूखी-नंगी जनता के सवालों से मुंह चुराने की आज़ादी ?

क्या वे सजग प्रहरी हैं ?

आदियोग

इस बात पर बहस हो सकती है कि किसी आदमी के लिए कुत्ता किसिम का, कुत्ता कहीं का जैसा जुमला गाली है या वफ़ादारी की पदवी. गांव-गली के कुत्ते अपने इलाक़े की पहरेदारी करते हैं. कहीं भी कोई ग़ैर मामूली हरक़त हुई कि वे चौकन्ने हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ी तो भौंकने भी लगते हैं कि होशियार-ख़बरदार. इस मोर्चे पर कोई कुत्ता कभी अकेला नहीं पड़ता. एक के शुरू होते ही सभी सुर में सुर मिलाते हैं. वे अपने इलाक़े के सबसे बड़े चौकीदार होते हैं. हर घर की हिफाज़त के लिए तैनात रहते हैं. उन्हें इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि कौन उन्हें खिलाता है, कौन दुत्कारता है. वे अपनी ड्यूटी के पाबंद और ईमानदार होते हैं. घोड़ा बेच कर सोने वाले उन्हीं के भरोसे चैन की नींद सोते हैं. कुत्ते का काम है निगरानी रखना. पत्रकार का भी यही काम है. अपनी भाषा-बोली में पत्रकारिता को कुत्तागिरी से जोड़ना अशोभनीय हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में वाचडॉग ज़रूर सम्मानित संबोधन है. लेकिन किसका वाचडॉग? जनता का, सरकार और प्रशासन का या कॉरपोरेट समूहों का? हम जानते हैं कि कुत्ता अगर किसी का पालतू है तो वह केवल अपने मालिक के प्रति समर्पित होता है और अगर वह आवारा यानी आज़ाद है तो अपने इलाक़े के प्रति निष्ठावान होता है. सड़क-मोहल्ले की खाक छानने वाला ही असली कुकुर होता है और जनता का वाचडॉग कहलाने का अधिकारी भी. वरना वह मालिक के तलवे चाटने में मग्न रहता है, वाचडॉग की सामाजिक भूमिका से कट जाता है और लैपडाग हो जाता है.

झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों को चूसने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां न जाने कब से घात लगाए बैठी हैं, लेकिन राज्य सरकार के साथ किए गए सौ से अधिक करारनामे काग़ज़ी उछलकूद से आगे नहीं बढ़ सके. इसमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल की परियोजना भी शामिल है. 40 हज़ार करोड़ रुपये की लागत वाले केवल इस्पात संयंत्र के लिए कंपनी को 25 हज़ार एकड़ ज़मीन और प्रति घंटे 20 हज़ार यूनिट पानी की दरकार थी. इस विशाल संयंत्र के लिए 256 गांवों की बलि चढ़नी थी. लेकिन, राज्य सरकार का गुणा-भाग काम न आया और कंपनी ने झारखंड से पैर समेट लेने का फ़ैसला लिया. आदिवासियों के लिए यह उनके जुझारू प्रतिरोध की जीत थी, लेकिन झारखंड के ज़्यादातर अख़बारों ने इसे आंसू बहाऊ अंदाज़ में पहले पेज की पहली ख़बर बनाया. एक बड़े अख़बार का मन इससे भी नहीं अघाया तो आर्सेलर मित्तल पर उसने ख़ास पेज अलग से नत्थी कर दिया और इसका अंत कंपनी को ईश्वर का दर्जा देते हुए किया गया. चाटुकारिता की जय हो!

अब छत्तीसगढ़ चलें. रायपुर प्रेस क्लब ने तय किया है कि किसी माओवाद समर्थक एनजीओ या बुद्धिजीवी के लिए उसके फाटक नहीं खुलेंगे. हालांकि इसका खुलासा नहीं किया गया है कि माओवादी समर्थक के बतौर उनकी शिनाख्त कैसे होगी. ज़ाहिर है कि जो राज्य प्रायोजित हिंसा के विरोध में आवाज़ उठाएंगे, वे माओवादियों के हमदर्दों में गिने जाएंगे. फ़िलहाल, माओवाद समर्थक एनजीओ से मतलब पीयूसीएल, आदिवासी महासभा या वनवासी चेतना आश्रम जैसे संगठनों से है. पीयूसीएल और आदिवासी महासभा बहुत पहले से जन विरोधी सरकारी नीति और नीयत की चीरफाड़ करते रहे हैं. अब वनवासी चेतना आश्रम भी रमन सिंह सरकार की आंखों की किरकिरी है. पिछले कोई 17 वर्षों से यह संगठन ग़रीब और वंचित आदिवासियों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहा था. तब तक कोई समस्या नहीं थी, बल्कि संस्था के सचिव हिमांशु कुमार कई सरकारी समितियों के सदस्य भी थे. 2005 में टाटा का राज्य सरकार से करार हुआ और आदिवासियों पर विस्थापन की तलवार लटकने लगी. माओवादियों से लोहा लेने के नाम पर सलवाजुड़ूम की पैदाइश हुई और ग़रीब आदिवासियों पर अत्याचार का नया एवं हिंसक अध्याय खुल गया. गांधीवादी उसूलों के पक्षधर वनवासी चेतना आश्रम ने सामाजिक कार्य के मर्म को समझा और राज्य की बर्बरता के अनगिनत मामलों को सामने लाने का दुस्साहस किया. इसकी उसे तगड़ी सजा मिली. जो माओवादी हिंसा का विरोध करता रहा, उसी संगठन को माओवादियों का समर्थक करार दिया गया.

डॉ. रमन सिंहः ख़िलाफत बर्दाश्त नहीं

ख़ैर, रायपुर प्रेस क्लब का विवादास्पद फ़ैसला अघोषित रूप से न जाने कब से लागू है. कोई तीन माह पहले दंतेवाड़ा में राज्य के दमन के शिकार आदिवासी प्रेस के सामने अपनी आपबीती रखना चाह रहे थे. उन्हें वनवासी चेतना आश्रम के हिमांशु कुमार ने इसके लिए तैयार किया था. लेकिन, प्रेस क्लब चाहता था कि आयोजक पहले साबित करें कि तथाकथित पीड़ित माओवादियों के समर्थक नहीं हैं. आयोजकों में पीयूसीएल की राज्य इकाई भी शामिल थी, जिसके उपाध्यक्ष डा. विनायक सेन माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में यानी सामाजिक सुरक्षा के लिए ख़तरा बन जाने के कारण दो साल की जेल काट चुके हैं. रायपुर प्रेस क्लब के इस रवैये पर हिमांशु कुमार ने दु:ख और आक्रोश भरे स्वरों में कहा था कि नहीं चाहिए हमें मीडिया का साथ. आदिवासी हमेशा से लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, मीडिया साथ रहे या न रहे.

अख़बार अक्सर आज़ादी का राग अलापते हैं. लेकिन, किसकी आज़ादी? कैसी आज़ादी? कॉरपोरेट समूहों का चेहरा चमकाने की, सरकारी धतकरमों पर पर्दा डालने की और भूखी-नंगी जनता के सवालों से मुंह चुराने की आज़ादी? झूठ का पर्दा सरक चुका है और यह सीन सामने है कि माओवादियों के सफाए के सरकारी यज्ञ में किस तरह आदिवासियों की आहुति दी जा रही है. उन्हें उनकी ज़मीन और जंगलों से खदेड़ा जा रहा है. पुलिस, सीआरपीएफ, सलवाजुड़ूम और एसपीओज ताक़त की नंगी आज़माइश यानी लूट, आगजनी, बलात्कार और हत्याएं करने के लिए छुट्टा छोड़ दिए गए हैं. ख़ौफ़ और सितम का अश्वमेध आदिवासी गांवों को वीरान बना रहा है. लेकिन, अपने ही देश के नागरिकों के साथ किया जा रहा दुश्मन सरीखा यह सुलूक छत्तीसगढ़ के अख़बारों के लिए कोई ख़बर नहीं. सलवाजुड़ूम कठघरे में है. उसे लेकर पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की थू-थू हो रही है. बावजूद इसके उसे सरकार का संरक्षण जारी है. तो इस पर क्या चौंकना कि अगर मुख्यमंत्री रमन सिंह सलवाजुड़ूम को माओवादियों के ख़िलाफ़ आदिवासियों का स्वत: स्फूर्त आंदोलन मानते हैं और उनकी पुलिस के मुखिया विश्वरंजन उसे गांधीवाद के नए प्रयोग के तौर पर देखते हैं. ज़्यादातर अख़बारों की भी यही राय है. इसीलिए उन्हें सलवाजुड़ूम के शिविरों में बंधक ज़िंदगी की कराहें नहीं सुनाई पड़तीं. राज्य सरकार और अख़बारों के बीच तालमेल इस क़दर गहरा है.

कुत्ते का काम है निगरानी रखना. पत्रकार का भी यही काम है. अपनी भाषा-बोली में पत्रकारिता को कुत्तागिरी से जोड़ना अशोभनीय हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में वाचडॉग ज़रूर सम्मानित संबोधन है.

इस जुगलबंदी से अलग होना कमलेश पैंकरा के लिए महंगा साबित हुआ. उन्होंने सलवाजुड़ूम के हाथों हो रहे मानवाधिकारों के हनन पर रिपोर्ट लिखने की जुर्रत की थी. पुलिस अधीक्षक का आदेश था कि वह यह रिपोर्ट लिखने को अपनी ग़लती मानें और उसके लिए माफी मांगें. लेकिन, कमलेश पैंकरा दबाव में नहीं झुके और अख़बार से उनकी छुट्टी कर दी गई. हम जानते हैं कि ज़िला या ब्लॉक स्तर पर तैनात अख़बारों के प्रतिनिधि आम तौर पर वेतनभोगी नहीं होते. उनकी सेवाएं सांकेतिक मानदेय पर या मुफ़्त होती हैं. कमलेश पैंकरा बहुमत का हिस्सा नहीं बन सके. उनके लिए पत्रकारिता कोई धंधा नहीं, जज़्बे का नाम था. आजीविका का मुख्य आधार सरकारी राशन की दुकान थी, जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया. माओवादियों को शरण देने का आरोप मढ़कर उनके भाई को जेल पहुंचा दिया गया. पुलिस की योजना कमलेश पैंकरा को हमेशा के लिए ख़ामोश कर देने की थी. इसकी भनक लगते ही उन्हें सपरिवार बीजापुर ज़िले से भागना पड़ा. तबसे वह दर-बदर भटक रहे हैं. इस बीच सीआरपीएफ ने उनके घर पर बुलडोज़र चला दिया. अब वहां वर्दीधारी गुंडे वॉलीबॉल खेलते हैं.

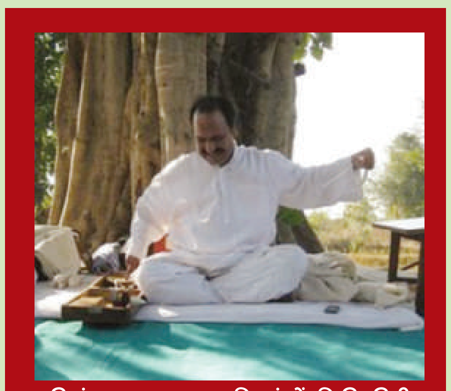
हिमांशु कुमारः सरकार की आंखों की किरकिरी

अपने पेशे के प्रति ईमानदार पत्रकार के इस हश्र पर ख़बरों की दुनिया के खिलाड़ी न जाने कहां बिला गए. मुसीबत से कौन मुठभेड़ करे और क्यों? युवा पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी ने छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के हवाले से उनकी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि किसानों की आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे आगे है. रायपुर से प्रकाशित एक अख़बार में छप रहे अपने नियमित स्तंभ में उन्होंने इसका ज़िक्र किया. इस पर ख़ासा हंगामा मचा. सरकार ने रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा करार दिया. अख़बार ने भी उसी मुस्तैदी के साथ शुभ्रांशु चौधरी की खोजपरक रिपोर्ट को धोखाधड़ी का नमूना बताया और एक दूसरी रिपोर्ट अपने पहले पन्ने पर छाप दी. इसी के साथ उनका स्तंभ भी समाप्त कर दिया गया. सरकारी विज्ञापनों की बैसाखी इतनी ताक़त रखती है कि उसके लिए सच को अपाहिज भी किया जा सकता है. बताते चलें कि एनसीआरबी राज्य सरकारों से प्राप्त अपराध के आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर केवल व्यवस्थित करने का काम करता है. शुभ्रांशु की रिपोर्ट को ख़ारिज़ करने का मतलब ख़ुद राज्य सरकार द्वारा एनसीआरबी को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर संदेह करना है. किरकिरी हुई तो राज्य सरकार यह तथ्य भूल गई और अख़बार ने भी अपनी भूल सुधारने में देरी नहीं की. लगता है कि छत्तीसगढ़ के अख़बारों ने सच को ब्लैकलिस्ट में डाल रखा है. तभी तो वे नहीं देख पाते कि सरकारी अमला किस तरह कंपनियों का कहार बनकर उनके हितों की पालकी ढोने में जुटा हुआ है. नहीं सूंघ पाते कि विकास का नारा तो मुनाफ़े के लुटेरों के लिए है और जिसका रास्ता जनता जनार्दन के सर्वनाश से होकर गुज़रता है.

दंतेवाड़ा में सात जनवरी की जन सुनवाई नहीं होने दी गई. होती तो राज्य प्रायोजित अत्याचारों की भयावह कहानियों का पिटारा खुलता. बात दूर तलक जाती और यह सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होता. इसलिए ज़िले को सील कर दिया गया. कोई 40 आदिवासी किसी तरह जन सुनवाई में अपनी आपबीती सुनाने पहुंचे. उन्हें इस तरह सुरक्षित वापस भेज दिया गया कि आइंदा वे ज़ुबान खोलने की हिम्मत न जुटा सकें. गोमपड़ गांव के उस दो साल के बच्चे को भी पुलिस संरक्षण में ले लिया गया, जिसके हाथों की अंगुलियां सुरक्षाबलों के बहादुर जवानों ने अलग कर दी थीं. उनकी गोलियों ने नौ लोगों को लाश में बदल दिया था. उस हत्याकांड की इकलौती गवाह सोडी शंबो है. वह घायल हुई और इलाज को तरसती रही. हिमांशु कुमार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उल्टे उन्हें ही शंबो के अपहरण के झूठे मामले में फंसा देने की साजिश रच दी गई. और, उन्हें दंतेवाड़ा ही छोड़ देना पड़ा. जन सुनवाई के गवाह बनने के लिए पूरे देश से लोग जुटे, उनका स्वागत सड़े अंडों और गोबर से किया गया. इन तमाम घटनाओं पर अख़बारों के कान नहीं खड़े हुए. लेकिन हां, जिद करो और दुनिया बदलो का नारा लगा रहे एक अख़बार समूह के ज़मीन हथियाओ अभियान के ख़िलाफ़ ग़रीब-गुरबे ज़रूर खड़े हो गए और सड़कों पर उतर आए. बिजली पैदा करने के कमाऊ धंधे के लिए किया जाने वाला गोरखधंधा करंट भी मार सकता है.

ख़ैर, रायपुर प्रेस क्लब का फ़ैसला दरअसल अख़बारों की दुनिया में मानवीयता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता, तथ्यपरकता और न्यायप्रियता जैसे मूल्यों के क्षरण की ओर इशारा करता है, जहां ख़बरें कच्चा माल हैं और अख़बार केवल एक उत्पाद. पाठक बस उसके उपभोक्ता. गुजरी छह अक्टूबर को रायपुर में विस्थापन के ख़िलाफ़ एक राज्यस्तरीय रैली का आयोजन हुआ था. इसमें सुदूर इलाक़ों से कोई दस हज़ार दुखियारे शामिल हुए थे. इनमें दो तिहाई से अधिक महिलाएं थीं. ज़्यादातर लोग नंगे पांव थे. रैली के बाद उसके कर्ताधर्ता आयोजन की समीक्षा के लिए बैठे. एक कार्यकर्ता को अगले दिन के सभी अख़बार (प्रतियां) ख़रीदने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई. तभी किसी दूसरे ने मुस्करा कर कहा कि ज़्यादातर अख़बारों को तो सरकार पहले ही ख़रीद चुकी है. इस पर वहां मौजूद लोग ठहाका मारकर हंस पड़े. और, सचमुच अगले दिन के अख़बारों में रैली की ख़बर नदारद थी या फिर उसे रूटीन ख़बर के तौर पर कहीं कोने में सरका दिया गया था.

यह कारनामा वॉचडॉग नहीं, लैपडॉग करते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

बचपन बचाओ आंदोलन नाम की संस्था ने बाल तस्करी और यौन पर्यटन को रोकने के संबंध में एक याचिका उच्चतम न्यायालय में डाली थी.

चौथी दुनिया

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट

सरकार नहीं, अब अदालत बचाएगी बचपन

भविष्य की बुलंद इमारत, वर्तमान की मज़बूत नींव पर ही बनती है. बच्चे देश का भविष्य हैं. दशकों से यह बात सरकार कहती और मानती रही है. लेकिन देश के बच्चों का वर्तमान कैसा है? बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल हिंसा और बाल यौन व्यापार जैसे कुचक्रों में फंस कर आज देश का भविष्य यानी बच्चों का वर्तमान तबाह हो रहा है. सरकार एक क़ानून बना कर अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर चुकी है. कार्यपालिका के बारे में कुछ लिखने या बोलने का कोई मतलब नहीं है. ऐसे में उच्चतम न्यायालय का एक हालिया आदेश निश्चित तौर पर सुकून देने वाला है.

शशि शेखर

युवाओं का देश भारत. 40 फ़ीसदी आबादी की उम्र 18 साल से कम. युवाओं के इस देश में 1 करोड़ 70 लाख बाल श्रमिक और 50 फ़ीसदी बच्चे यौन हिंसा के शिकार भी. बाल श्रम रोकने और बच्चों की देख-रेख और संरक्षण के लिए क़ानून भी हैं. लेकिन फिर भी स्थिति बेकाबू है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन एक्ट 2000) इसका सबसे सटीक उदाहरण है. इस क़ानून को लागू हुए दस साल बीतने को हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्य सरकारें अभी तक इस क़ानून को अपने यहां पूर्णरूपेण लागू नहीं कर सकी हैं.

बचपन बचाओ आंदोलन नाम की एक ग़ैर सरकारी संस्था ने बाल तस्करी और सेक्स टूरिज़्म को रोकने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका डाली थी. 22 जनवरी को इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों को छह सप्ताह के भीतर बाल अपराध न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष पुलिस बल गठित करने का निर्देश दिया. याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की खंडपीठ ने सभी राज्यों को संबंधित क़ानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति और अन्य पहलुओं पर हलफ़नामा दायर करने का भी निर्देश दिया. दरअसल, बाल संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन एक्ट 2000) लाया था. लेकिन लगभग एक दशक बीत जाने के बाद भी ज़्यादातर राज्य सरकारों ने इस पर अमल नहीं किया है. नतीजतन, जिन राज्यों में बोर्ड गठित हुए भी हैं, वहां बाल संरक्षण की दिशा में कोई कारगर क़दम नहीं उठाया जा सका है. देश में ऐसा एक भी राज्य नहीं है, जहां संबंधित क़ानून की विभिन्न धाराओं के तहत एक साथ बाल अपराध न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति की स्थापना की गई हो. इतना ही नहीं बाल तस्करी एवं सेक्स टूरिज़्म को रोकने या इससे पीड़ित लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए विशेष पुलिस बल का गठन भी नहीं किया गया है.

ज़ाहिर है, अदालत के इस क़दम से इतना तो साफ़ हो ही जाता है कि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे काफ़ी बदतर परिस्थिति में जीने को अभिशप्त हैं. बाल मज़दूरी ऐसा ही एक अभिशाप है जो देश के बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है. हालांकि सरकार ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए कई क़ानून बनाए. लेकिन एक सच यह भी है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक भारत में ही हैं. देश भर में क़रीब एक करोड़ 70 लाख बाल मज़दूर हैं. इसमें से 80 प्रतिशत खेतों और कारखानों में काम करते हैं. बाल मज़दूरों की बहुत बड़ी तादाद खदानों, चाय बगानों, दुकानों और घरेलू कामों में भी लगी हुई है. ग़ैर सरकारी संस्थानों के अनुमान के मुताबिक़, देश में बाल मज़दूरों की संख्या क़रीब छह करोड़ तक हो सकती है. चिंता की बात यह भी है कि बहुत सारे बच्चे पटाखे या अन्य रसायन बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं. ज़ाहिर है, ऐसे बच्चों को न तो ढंग की शिक्षा मिल पा रही है और न ही उनकी उचित देख-रेख हो पा रही है. ज़ाहिर है, महज़ क़ानून बना देने भर से बाल श्रम जैसी बुराई ख़त्म नहीं होने वाली है. दरअसल, सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि आख़िर कोई बच्चा क्यों बाल श्रमिक बन जाता है. निश्चित तौर पर इसके पीछे कारण आर्थिक ही होते हैं. ग़रीबी की वजह से मां-बाप बच्चों को कम उम्र में ही कामों में लगा देते हैं, ताकि कुछ कमाई हो सके और उनका गुजारा चल सके. ज़ाहिर है, बाल श्रम की एक बड़ी वजह ग़रीबी भी है.

बच्चों को मज़दूरी करनी पड़ती है इसके अलावा कई दूसरे मोर्चों पर भी उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों के साथ यौन हिंसा जैसे घिनौने अपराध हो रहे है. सेक्स टूरिज़्म के नाम पर बच्चों को पर्यटकों के सामने सेक्स के लिए परोसे जाने की बात अक्सर सामने आती रहती है. कुछ साल पहले मानवता को शर्मसार करने वाली घटना नोएडा के निठारी में सामने आई थी. वहां बच्चों का अपहरण करने के बाद हवस का शिकार बनाए जाने का खुलासा हुआ था और उन बच्चों के अंगों के तस्करी की भी आशंका जताई गई थी. बच्चों का अपहरण कर उनसे भीख मंगवाने का काम भी करवाया जाता रहा है.

भारतीय बच्चों की दुर्दशा पर एक अध्ययन, बच्चों के लिए काम करने वाली ग़ैर सरकारी संस्था चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) ने किया है. अध्ययन के मुताबिक़, भारत के लगभग 50 फ़ीसदी बच्चों को स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती है. इसके अलावा, बड़ी संख्या में बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं. इनमें भी ज़्यादातर बच्चों का यौन उत्पीड़न कार्यस्थलों पर हो रहा है. भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बाल शोषण पर केंद्रित एक अध्ययन के मुताबिक़, हिंदुस्तान के 53.22 प्रतिशत बच्चे यौन शोषण का शिकार हैं. उनमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी. भारत में 18 साल से कम उम्र वाले लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ है. इनमें भी 21 करोड़ की उम्र 14 साल से भी कम है. निश्चित तौर पर यह संख्या अपने-आप में किसी देश के लिए बहुत मायने रखती है. देश की आबादी के एक बड़े हिस्से पर ध्यान दिए और उनकी स्थिति में सुधार किए बिना देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

फोटो : प्रभात पाण्डेय

- जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू नहीं हो सका है
- भारत की 40 फ़ीसदी आबादी 18 साल से कम उम्र की
- देश भर में एक करोड़ 70 लाख बाल-मज़दूर हैं
- सिर्फ़ 15 प्रतिशत बच्चों को ही मज़दूरी से मुक्ति मिली
- 53.22 प्रतिशत बच्चे यौन शोषण के शिकार हैं

राकेश सेंगर
राष्ट्रीय महासचिव, बचपन बचाओ आंदोलन

"एक तो वैसे ही देश में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 का अनुपालन अब तक ठीक ढंग से नहीं हो पाया है, उस पर सीडब्ल्यूसी जैसी संस्थाएं, जिसे इस एक्ट में काफ़ी अधिकार दिए गए है, अपने अधिकार का उपयोग भी नहीं कर रही है."

"सभी राज्य छह सप्ताह के भीतर बाल अपराध न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष पुलिस बल गठित करे और बाल न्याय क़ानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति और अन्य पहलुओं पर हलफ़नामा दायर करे."

सुप्रीम कोर्ट

प्रमुख राज्यों में बाल अपराध न्याय बोर्ड (जेजेबी), बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)

राज्य	जिला	जेजेबी	सीडब्लूसी
बिहार	37	9	1
हरियाणा	19	4	19
हिमाचल प्रदेश	12	2	-
झारखंड	18	7	7
कर्नाटक	27	5	27
महाराष्ट्र	35	30	37
राजस्थान	32	9	9
तमिलनाडु	30	8	18
उत्तर प्रदेश	70	25	12
प. बंगाल	18	2	5

राष्ट्रसंघ की विश्व शहरीकरण रिपोर्ट के मुताबिक़ देश के मेगाशहरों में से कोलकाता का स्थान तीसरा है और 2015 तक इसकी आबादी एक करोड़ 70 लाख हो जाएगी.

हाथ रिक्शावाले धीमी मौत मर रहे हैं

बिमल राय

कोलकाता की सड़कों से हाथ रिक्शा हटाने की अब कोई हड़बड़ी नहीं दिखती. शायद अगले विधानसभा चुनाव तक सरकार को इसकी ज़रूरत नहीं लगती. कभी हावड़ा पुल के साथ-साथ हाथ रिक्शा को भी कोलकाता की पहचान के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था. गणतंत्र दिवस की झांकियों में गनेसी अपनी टुनटुनिया गाड़ी लिए राजपथ पर टहलता दिखता था. पर नहीं, काफ़ी सोचते-विचारते और नए ज़माने की नई सोच के साथ लगा कि यह अमानवीय है, इससे कोलकाता की छवि सुधरती नहीं, बल्कि बिगड़ती है, तो सरकार ने इसे बंद करने का ऐलान किया. वह समय था दिवंगत ज्योति बसु का. उन्होंने वर्ष 1996 के 15 अगस्त का दिन इस ऐलान के लिए चुना था. तीन महीने के भीतर कई चरणों में इन्हें हटाने की बात कही गई. 2005 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी इन्हें हटाने और साथ-साथ रिक्शाचालकों के पुनर्वास की बात कही. पर पहले उजाड़े गए लोगों के पुनर्वास के वायदे का हश्र देखते हुए इसे भी शायद किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. आज तक मामला लटके रहने से यह बात सच भी साबित हो गई है.

1972 में कोलकाता के सभी बड़े रास्तों में हाथ रिक्शों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई. वर्ष 1982 में सरकार ने अभियान चलाकर 12000 रिक्शे ज़ब्त किए और उन्हें तोड़ दिया गया. 1992 तक महानगर में 30 हज़ार हाथ रिक्शे चल रहे थे, जिनमें से छह हज़ार रिक्शे बिना लाइसेंसी थे. दिसंबर 2006 में विधानसभा में 1919 का कलकत्ता हैकनी कैरेज (संशोधन) बिल पारित किया गया. इसके ख़िलाफ़ यूनियन अदालत में गई. पिछले साल जुलाई में हाईकोर्ट ने भी हाथ रिक्शा हटाने की सरकारी पहल पर मुहर लगा दी, पर सरकार अपने ही हक़ में हुए फ़ैसले पर अमल नहीं कर रही है. विस्थापित रिक्शा चालकों के पुनर्वास के लिए वह अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बना पाई है. इस तरह सरकारी तौर पर एक अमानवीय काम कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है. ऐसा नहीं है कि कोलकाता को ख़ूबसूरत शहर बनाने की धुन ख़त्म हो गई है. हालांकि एक समय था, जब देशी-विदेशी पूंजी निवेशकों को एक नया आधुनिक कोलकाता दिखाना था तो इसके लिए ठेला-रिक्शा से लेकर फुटपाथों पर क़ब्ज़ा जमा कर बैठे हॉकरों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन सनसाइन चलाया गया, पर आज कोलकाता आने वाला कोई भी देख सकता है कि लोगों के चलने के लिए फुटपाथ कहां-कहां बचे हैं. पर नंदीग्राम और सिंगुर कांड के बाद सरकार का सौंदर्यीकरण का नशा भी उतर गया है. ममता के साथ-साथ माओवादियों ने बंगाल की राजनीति का एक तरह से एजेंडा ही बदलकर रख दिया है. एक बार राइटर्स के समक्ष आंदोलन कर रहे रिक्शा चालकों पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था.

इनकी ताबूत में आख़िर कील बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ठोंकी. अगस्त 2005 में सरकार ने इन पर पूरी पाबंदी लगाने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आदमी दूसरे का भार ढोए, यह अमानवीय है. साथ-साथ इसे सड़कों पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाला भी बताया. उन्होंने कहा कि जिनके पास लाइसेंस हैं, उन्हें साइकिल रिक्शा दिया जाएगा. परिवहन विभाग, कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस पुनर्वास की योजनाएं बना रही हैं. हालांकि इन्हें विकल्प के तौर पर ऑटो रिक्शा देने की भी बात कही जा रही है. पर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने चालक यह सुविधा ले सकेंगे, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर अशिक्षित, बीमार और बुढ़ापे की दहलीज पर हैं.

मालूम हो कि कोलकाता के क़रीब 20 हज़ार रिक्शा चालकों में लगभग 82 फ़ीसदी लोग बिहार के हैं, जबकि 9 फ़ीसदी पूर्वी उत्तर प्रदेश व उड़ीसा के हैं. इनमें हिंदू 68 प्रतिशत और 32 प्रतिशत मुसलमान हैं. कोलकाता नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक़ आधे हाथ रिक्शा चालकों की उम्र 25 से 40 साल के बीच है. रिक्शा चालकों की रोज़ाना की कमाई 150 से 200 रुपये तक है और अनुमान है कि इनका कुल कारोबार मासिक पांच करोड़ रुपये के आसपास है. इस संबंध में सही आंकड़े इस वजह से उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि बिना लाइसेंस वाले सैकड़ों रिक्शे पुलिस वालों के संरक्षण में चलते रहे हैं, हालांकि अब इनकी संख्या नगण्य हो गई है. निगम की ओर से बहुत पहले करवाए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि केवल लगभग 20 प्रतिशत हाथ रिक्शा चालकों ने इस पेशे को ख़ुशी से अपनाया है, जबकि बाक़ी रोज़गार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण रिक्शा चला रहे हैं. ज़्यादातर के पास अपने रहने के लिए मकान नहीं हैं और न ये किसी राजनीतिक पार्टी के वोट बैंक हैं, क्योंकि इनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं. इनके जो संगठन हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिया गया है. उनका इतना प्रभाव नहीं है कि वे सरकार को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर सकें. ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन के मुताबिक़, अभी कोलकाता में पंजीकृत रिक्शा चालकों की तादाद 5937 है. मेयर विकास रंजन भट्टाचार्य ने चौथी दुनिया को बताया कि लाइसेंस का नवीनीकरण बहुत पहले से बंद कर दिया गया है. वर्ष 2004-2005 में 3088 हाथ रिक्शों का नवीनीकरण किया गया था, जबकि 2005-2006 में यह तादाद मात्र 1450 थी. 2006 से किसी रिक्शा लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो रहा है. राहत और पुनर्वास के मामले पर मेयर ने बताया कि यह काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, हालांकि उन्होंने इसकी कोई समय-सीमा बताने से असमर्थता जताई. मालूम हो कि वर्ष 1945 के बाद से ही नए रिक्शों का लाइसेंस देने का काम बंद है.

घंटे भर की बरसात के बाद ही जब कोलकाता के कई इलाक़े तालाब में तब्दील हो जाते हैं तो हाथ रिक्शा वाले ही राहत व बचाव के काम के लिए उपलब्ध हो पाते हैं.

रोगियों, स्कूली बच्चों और बूढ़ों को बरसात के कहर से बचाने में इनकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता. बड़ा बाज़ार जैसे संकरी गलियों वाले इलाक़ों में इसके अलावा कोई दूसरी सवारी घुस ही नहीं सकती. सुबह-सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को हाथरिक्शा सबसे मुफ़ीद लगता है. बरसात के दिनों में जब पानी घुटनों से ऊपर आ जाता है, तो तारनहार के रूप में सिर्फ़ हाथ रिक्शावाले ही दिखते हैं. पेशे को अमानवीय मानने वाली एक बड़ी मध्यवर्गीय आबादी भी बरसात में मजबूरन हाथ रिक्शा की सवारी करती है. देर रात को रोगी के बीमार होने पर एंबुलेंस से ज़्यादा सुलभ होते हैं ये रिक्शा वाले. शादी-ब्याह जैसे मौक़ों पर या छोटे व्यापारियों के लिए ये माल ढोने का भी काम करते हैं. 300 साल पुराने महानगर कोलकाता में सैकड़ों ऐसी गलियां हैं, जहां हाथ रिक्शा छोड़कर कोई दूसरा वाहन जा ही नहीं सकता. ऐसे में बीमारों, बच्चों, बूढ़ों और विकलांग लोगों के लिए यातायात का कोई दूसरा सुलभ साधन नहीं है. हाथ रिक्शे के साथ चालक ही नहीं, उनके मालिक, रिपेयर करनेवाले, कारीगर व विक्रेता आदि का एक बड़ा समूह इससे अपनी जीविका चला रहा है. ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन के सचिव मुख्तार अली ने चौथी दुनिया को बताया कि 26 से 27 हज़ार परिवार सीधे तौर पर इस पेशे की कमाई पर निर्भर हैं. एक परिवार में औसतन अगर चार लोग भी हों तो आंकड़ा लाख से ऊपर जाता है.

चीन से आया हाथ रिक्शा

भारत में सबसे पहले 1980 में हाथ रिक्शा हिमाचल के शिमला में आया. 19 वीं सदी के प्रारंभ में चीनी व्यापारियों ने कोलकाता में माल ढोने के लिए इस दोपहिए का इस्तेमाल शुरू किया. अंग्रेजों ने 1980 में इसे एक पेशे के रूप में मान्यता दी और इनकी तादाद तेजी से बढ़ी. तबसे हाथ रिक्शा कोलकाता की दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है. मालूम हो कि ज़्यादातर हाथ रिक्शे किराए के ही होते हैं. सुबह छह बजे से रात के 12 बजे तक एक रिक्शे को दो या तीन चालक किराए पर लेते हैं. कोई भी चालक लगातार 30 दिनों तक काम नहीं कर पाता. सेहत ठीक रहे, इसके लिए महीने में चालकों को 10 दिन आराम करना पड़ता है. रिक्शा मालिक हर शिफ्ट के 20 से 25 रुपये किराए के रूप में लेता है. अपने परिवार को पालने के इस क्रूर संग्राम में इन्हें पुलिस वालों की लूट-खसोट का दंश भी सहना पड़ता है. यह इसलिए क्योंकि कुछ रिक्शे बिना लाइसेंस के भी चलते हैं और इनसे ट्रैफिक पुलिस को मोटी कमाई होती है. लाइसेंस और ट्रैफिक नियम की आड़ में इनका खुलकर शोषण होता है. जहां तक सरकार को राजस्व देने की बात है, हर रिक्शा मालिक को एक रिक्शे के दो लाइसेंस लेने होते हैं. नगर निगम के ट्रेड कैरेज लाइसेंस, नंबर प्लेट और रोड परमिट भी इसमें शामिल होता है. प्रत्येक रिक्शे को हर साल फिटनेश प्रमाणपत्र लेना पड़ता है, जिसके लिए प्रति रिक्शा 2000 से 3000 रुपये शुल्क के रूप में लिए जाते हैं. पूरे ख़र्च को मिलाया जाए तो एक रिक्शे की क़ीमत 10 से 12 हज़ार पड़ती है.

कैसे हो पुनर्वास?

डोमनिक ला पियरे के सिटी ऑफ जॉय का नायक अब

आख़िरी सांसें गिन रहा है. सरकार के पास अगर इच्छाशक्ति होती तो बहुत पहले ही इनका पुनर्वास हो सकता था. चेन्नई नगर निगम की फुर्ती से सरकार सबक ले सकती है. सन 1972 से पहले चेन्नई (उस समय उसका नाम मद्रास था) में हाथ रिक्शे का चलन था. तत्कालीन सरकार ने बहुत ही कम समय में हाथ रिक्शा वालों को तीन चक्के वाला रिक्शा उपलब्ध कराया. वहां एक को-ऑपरेटिव बनाई गई, जिसके सदस्य हाथ रिक्शा चालक ही थे. बंगाल अगर पहले सोचता है और देश बाद में तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन के बंगाल अध्यक्ष सुल्तान अहमद ने चौथी दुनिया को बताया कि अगर यह पेशा अमानवीय है तो सरकार को जल्दी से जल्दी पुनर्वास कर देना चाहिए. उनके मुताबिक़ क़ानूनी रूप से यह पेशा सही है और किसी को भी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कोई ठोस प्रस्ताव लेकर यूनियनों से बात नहीं शुरू करती, तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी. अभी भी यह साफ़ नहीं है कि सरकार इन्हें साइकिल रिक्शा देगी या ऑटो रिक्शा. उनके मुताबिक़ आधुनिक प्रकार का साइकिल रिक्शा सबसे अच्छा विकल्प है. सरकार के फ़ैसले के बाद टीयूवी मैनेजमेंट सर्विस ने हाथ रिक्शा की जगह बैटरी से चलने वाले रिक्शे मुहैया कराने का भी प्रस्ताव दिया था, जिसे चलाने के लिए किसी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी और यह पर्यावरण के अनुकूल भी थे. यूनियन ने प्रस्ताव रखा भी था, पर सरकार ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया. पुनर्वास में सरकार को ज़्यादा ख़र्च भी नहीं करना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा हाथ रिक्शा चालकों के पास न राशन कार्ड है और न ही मतदाता पहचान पत्र.

जहां तक इस पेशे के अमानवीय होने का सवाल है, कोलकाता में इससे भी ज़्यादा अमानवीय पेशा कर रहे लोगों का हुजूम है. राज्य सरकार के सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग के चारों तरफ़ खाने-पीने के स्टाल पर छोटे-छोटे बच्चों को सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए अपने बचपन और भविष्य को कुर्बान करते देखा जा सकता है. बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हुए जनसंख्या विस्फोट और इससे उपजी ग़रीबी और वेश्यालयों की बढ़ती आबादी भी अमानवीय ही है. ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन के मुख्तार अली ने बताया कि हम हटाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पर पहले पुनर्वास करना होगा और अगर सरकार तहे दिल से पुनर्वास चाहती है तो जल्दी से जल्दी से यूनियन को बैठक के लिए बुलाना चाहिए.

रिक्शा चालक भी अब शिक़ायत नहीं करते. उन्हें सिर्फ़ पुनर्वास का इंतज़ार है. 20 साल से रिक्शा चलाकर अपने चार सदस्यों का परिवार चला रहे हजारीबाग के कुदुस अली ने बताया कि अगर हमें जीविका का कोई साधन मिलता है तो इसे छोड़ने में कोई असुविधा नहीं है. 25 साल से इस काम में लगे मुज़फ़्फ़रपुर के बिरजू राय ने भी कहा कि रिक्शा अगर छीन लिया जाए तो हम क्या खाएंगे. उसने वैकल्पिक उपाय के रूप में तीन पहिए वाले रिक्शे को मुफ़ीद बताया. बिहार के ही बांका ज़िले के पटोरिया गांव के बोनी यादव ने बड़ाबाज़ार की गलियों में घूम रहे ऑटोवालों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सरकार तो इनके बारे में सोच रही है, हमें कौन पूछता है. मधुबनी के शंकर राय ने स्वीकार किया कि बदलते बिहार को देखकर भी उनमें कुछ हिम्मत जगी है और वहां भी धीरे-धीरे रोज़गार के अवसर पैदा हो रहे हैं. कोलकाता में बिहारवासियों के लिए काम कर रही संस्था बिहार नागरिक मंच के अध्यक्ष मणि प्रसाद सिंह ने चौथी दुनिया को बताया कि अपराध कम होने और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का ग्राफ नीचे आने से अब बिहार में भी रोज़गार के अवसर बढ़े हैं. यही वजह है कि विस्थापित हुए सैकड़ों हाथ रिक्शावाले अब बिहार में ही अपनी जीविका चला रहे हैं.

राष्ट्रसंघ की विश्व शहरीकरण रिपोर्ट के मुताबिक़ देश के मेगाशहरों में से कोलकाता का स्थान तीसरा है और 2015 तक इसकी आबादी एक करोड़ 70 लाख हो जाएगी. इस तरह 40 सालों में आबादी दोगुनी हो जाएगी. इस आबादी की परिवहन ज़रूरतों के लिए पर्यावरण के अनुकूल वाहन ही चलने चाहिए. सरकार ने कोलकाता का चेहरा चमकाने के लिए पहले ही यहां से खटालों को हटाया, पर महानगर में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप जस का तस है. इसी तरह वह वाहनों की गति बढ़ाने के लिए भी तरह-तरह के कवायद करती आ रही है, पर अभी तक नतीजे ढाक के तीन पात ही दिखे हैं.

सबकुछ सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है कि वह हाथ रिक्शा चालकों को धीमी मौत मारना चाहती है या सचमुच उनके पुनर्वास के प्रति गंभीर है. वह अगर गंभीर होती तो चुनाव जैसे मौसम का बहाना या इंतज़ार नहीं करती. बहाना इस अर्थ में कि शायद वह नए झमेले में नहीं पड़ना चाहे और इंतज़ार इस अर्थ में कि संभव है सरकार हिंदीभाषियों को लुभाने के लिए चुनावी मौसम में राहत पैकेज पेश करे. सवाल यह है कि एक अमानवीय पेशा चलते रहने की अनुमति सरकार क्यों दे रही है?

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक संबंधों से जुड़ी भारतीय दंड विधान की धारा 377 के बारे में एक महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाया. आम लोगों की नज़र में समलैंगिक संबंध भारतीय संस्कृति, मूल्यों और नीति के ख़िलाफ़ हैं.

अफ़ग़ानिस्तान, तालिबान और अमेरिका

आयशा सिद्दीका

इससे ज़्यादा स्पष्ट और कुछ नहीं हो सकता है कि अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद विदेशी सेनाओं के अपने-अपने हितों और परिस्थितियों के बीच एक चौड़ी खाई है. हालांकि अमेरिकी अधिकारी कह चुके हैं कि अफ़ग़ानिस्तान से सेना को हटाने के बारे में ओबामा प्रशासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना अभी बाक़ी है. फिर भी यह साफ़ है कि अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी यहां से निकलना चाहते हैं. जनरल मक क्रिस्टल के उस ताज़ा बयान की ओर सबका ध्यान गया है, जिसमें उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत करने की बात कही है. यह कोई नया विचार नहीं है, लेकिन इससे इस बात की संभावना बढ़ी है कि अमेरिका तालिबान के साथ समझौता कर अफगानिस्तान को भारत के समर्थन से बने मुल्ला उमर और करज़ई गठबंधन की दया पर छोड़ सकता है. तालिबान को रिझाने के लिए ओबामा प्रशासन कोई भी तरीक़ा अपना सकता है. इसमें धन का लालच और तालिबान को अच्छा एवं बुरा तालिबान में बांटने तक की योजना शामिल है. ऐसी स्थिति में अच्छा तालिबान, जो नई पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता है, पुरानी पीढ़ी के तालिबानियों के मुक़ाबले विदेशी ताक़तों से समझौता करने में ज़्यादा दिलचस्पी रख सकता है.

पाकिस्तान के कुछ हलकों में इस अमेरिकी योजना को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि सेना और रणनीतिकार हमेशा ऐसी योजनाओं का समर्थन करते रहे हैं. असल में परवेज़ मुशर्रफ भी इस योजना को हवा दे रहे हैं. यह चिंता भी ज़ाहिर की जा रही है कि अमेरिका यह बातचीत अकेले दम पर भी कर सकता है. हालांकि अमेरिका के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आईएसआई की अनदेखी कर पाना आसान नहीं है. वजह, आईएसआई के तालिबान के साथ रिश्ते काफ़ी गहरे हैं. सूत्रों का तो यह भी मानना है कि पिछले दो महीनों में पाकिस्तानी जासूसी संस्थाओं के सहयोग से आईएसआई, सीआईए और मुल्ला उमर के बीच एक बैठक भी हो चुकी है. तालिबान भी अब अमेरिका के साथ बातचीत करने के मामले में अनिच्छुक नहीं दिख रहे हैं. ख़ासकर तब, जब वाशिंगटन लादेन को ज़िंदा या मुर्दा हासिल करने के लिए मुल्ला उमर और उसके आदमियों पर दबाव न डाले. कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह बातचीत तब भी संभव हो सकती थी, यदि अमेरिका हमला करने में इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाता.

अंततः मुल्ला उमर ने ऐसे संकेत दे दिए हैं कि यदि वह अफ़ग़ानिस्तान के भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होता है तो तालिबान युद्ध में ख़ुद को नहीं झोकेगा. दिलचस्प रूप से, अन्य स्रोतों ने इस रिपोर्ट को ख़ारिज़ कर दिया है. लेकिन सवाल उठता है कि आख़िर वह क्यों बातचीत नहीं करना चाहेगा, जबकि उसके पास पाने के लिए सब कुछ है. वह न सिर्फ़ काबुल के भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाएगा, बल्कि एक ऐसे धर्म आधारित राज्य की स्थापना का भी हिस्सा बन जाएगा, जिसे पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल होगा. जैसे सउदी अरब को समर्थन मिला हुआ है. इसलिए समाधान वाली इस रिपोर्ट को ख़ारिज़ करने का मतलब कुछ अधिक सौदेबाजी हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों के लिए यह चिंता की बात नहीं है,

भारत और पाकिस्तान के बीच अफ़ग़ानिस्तान पर अपना प्रभाव क़ायम रखने की प्रतिस्पर्द्धा का नतीजा यह होगा कि दोनों तरफ़ से आतंकी संगठनों के द्वारा छद्म युद्ध को बढ़ावा मिलेगा.

क्योंकि यह उन लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए विवश कर सकता है.

भारत अच्छी और बुरी दोनों ही स्थितियों के बारे में सोच रहा है, जबकि इस्लामाबाद भविष्य में दो मोर्चों की स्थिति में भारतीय उपस्थिति की वजह से आशंकित है. पाकिस्तान ऐसी स्थिति में है, जहां दिल्ली उसे बचाव की मुद्रा में धकेल सकती है. दिल्ली पहले से ही ख़ुफ़िया गतिविधियों और विकास कार्यों की सहायता से इस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश कर चुकी है. दिल्ली के लिए सबसे बुरी स्थिति अफ़ग़ानिस्तान की राजनीतिक विफलता से जुड़ी है, जिसमें इस्लामाबाद का प्रभाव महज़ दक्षिणी प्रांतों तक ही सीमित है, जबकि भारत का उत्तरी क्षेत्र और काबुल पर गहरा प्रभाव है. इस रणनीति में स्पष्ट रूप से कुछ कमी है. अमेरिका के अफ़ग़ानिस्तान से निकलने के बाद भारत दक्षिणी क्षेत्र पर प्रभाव नहीं रख पाएगा. चूंकि भारत ने अपने क़रीबी प्रांतों, जैसे उत्तरी प्रांत में निवेश करने के बजाय दक्षिणी प्रांतों में निवेश पर पूरा ध्यान दिया है. फलस्वरूप, भारत न तो उत्तरी और न ही दक्षिणी प्रांतों पर अपनी पकड़ बनाए रख सकेगा. भारत अफ़ग़ान तालिबानियों पर पैसा ख़र्च करने की योजना भी अपना सकता है, लेकिन यह योजना काम कर सकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है. भारत के लिए तालिबानियों की ओर से बुरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अफ़ग़ानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद उपजे हालात से निपटने के लिए प्रांतीय राज्य किसी संयुक्त रणनीति के बारे में नहीं सोच रहे हैं. अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद खुला भानुमती का पिटारा अमेरिका के अफ़ग़ानिस्तान से चले जाने के बाद बंद नहीं हो सकेगा. ऐसी स्थिति में दो संभावनाएं दिमाग़ में आती हैं. पहली तो यह कि एक सुविचारित योजना के तहत वहां से गठबंधन सेना के जाने के बाद हिंसा ख़त्म हो सकती है. यह एक ऐसा वक़्त होगा, जब क्षेत्रीय ताक़तें अफ़ग़ानिस्तान में अधिक हिस्सेदारी को लेकर फिर से एकजुट होने लगेंगी. दूसरी यह कि शुरुआत में अफ़ग़ानिस्तान और बाद में पूरे क्षेत्र में हिंसा की आग भड़क जाए. क्षेत्रीय लीडर संसाधनों की लूटखसोट को बढ़ावा देंगे और दूसरी तरफ़ अव्यवस्था फैलाने का काम करेंगे. निश्चित तौर पर ऐसे में एक ख़तरनाक परिस्थिति जन्म लेगी.

इस तरह के हालात भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ख़तरनाक साबित होंगे. शायद पाकिस्तान के लिए यह स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयावह होगी, क्योंकि यहां का समाज दशकों से आतंक के ख़िलाफ़ चल रही जंग से प्रभावित है. दुःखद रूप से इस क्षेत्र और यहां के आतंकी संगठनों के बीच छद्म युद्ध ख़त्म होता नहीं दिख रहा है. दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच अफ़ग़ानिस्तान पर अपना प्रभाव क़ायम रखने की प्रतिस्पर्द्धा का नतीजा यह होगा कि दोनों तरफ़ से आतंकी संगठनों के द्वारा छद्म युद्ध को बढ़ावा मिलेगा. ऐसे पूर्वानुमानों का मतलब है कि अफ़ग़ानिस्तान में ऐसे युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, जो शिक्षा के अधिकार, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, स्वस्थ वातावरण और व्यक्तिगत सुरक्षा से महरूम रह जाएंगे. ये युवा राष्ट्रीय अस्मिता के नाम पर बलिदान कर दिए जाएंगे और विश्वास के नाम पर शहादत देने के लिए मूर्ख बनाए जाएंगे.

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार, रणनीतिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

बीते साल के न्यायिक फ़ैसले : कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी

रवि किशोर

अगर न्यायिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो बीते साल 2009 को हम मील के पत्थर के तौर पर याद कर सकते हैं. विगत वर्ष की कुछ न्यायिक प्रगतियों और फ़ैसलों की बात करें तो आने वाले वर्षों में वे न्यायपालिका की दिशा को तय करेंगे. न्यायिक संस्थाओं का अगर एक ओर सम्मान बढ़ा तो दूसरी ओर कुछ ऐसी बातें भी हुईं, जिसने आम आदमी की नज़रों में न्यायपालिका की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया.

वर्ष 2009 में न्यायपालिका के काम की शुरुआत कुछ वैसे हुई, जैसे नब्बे के दशक की शुरुआत में अर्थ व्यवस्था खुली थी. यह अलग बात है कि दोनों ही क्षेत्रों में इस ओपनिंग अप के मायने अलग हैं. न्यायिक व्यवस्था के साथ अगर ओपनिंग अप की बात करते हैं तो हमारा सीधा तात्पर्य यह है कि न्यायिक व्यवस्था का विस्तार पहले काफ़ी सीमित था. वह सूचना का अधिकार क़ानून के कारण आम आदमी की पहुंच में आ गई.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर अपनी संपत्ति का ख़ुलासा करने का दबाव पड़ा. संपत्ति की घोषणा कोई स्वैच्छिक नहीं थी और अंततः भारत के मुख्य न्यायाधीश तक को इसका विरोध करना पड़ा. इसने आम लोगों के बीच इस बहस को जन्म दिया कि आख़िर न्यायपालिका से जुड़े लोगों को अपनी संपत्ति का ख़ुलासा क्यों नहीं करना चाहिए. जबकि न्यायपालिका ही यह कहती है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन से पहले अपनी संपत्तियों का ख़ुलासा करना चाहिए. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर जो रुख़ अपनाया, वह लोगों को स्वीकार्य नहीं हुआ. यहां तक कि न्यायपालिका से जुड़े कुछ लोगों ने भी इस पर असहमति व्यक्त की. असहमति जताने वालों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुमार का नाम प्रमुख है. संपत्ति का ख़ुलासा किए जाने के मुद्दे पर किसी वर्तमान न्यायाधीश ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रुख़ का पहली बार खुला विरोध किया. इस पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वी शैलेंद्र कुमार ने कहा, यह सोचना ग़लत होगा कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी संपत्तियों की घोषणा करने को तैयार नहीं हैं. न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि लोगों के मन में जो छवि बनी है, वह सबसे ज़्यादा नुक़सानदायक है. उनके मन में यह धारणा घर कर गई है कि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें संवैधानिक संरक्षण हासिल है, अपनी संपत्ति का ख़ुलासा करने में संकोच कर रहे हैं और उसे गोपनीय रखने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. एक मामले में महत्वपूर्ण विकास यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय को नरम रवैया अपनाना पड़ा और अंततः न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कर दी. इस विकास से न्यायिक जवाबदेही में काफ़ी मदद मिलेगी.

जहां तक न्यायिक जवाबदेही की बात है तो वर्ष 2009 को हम एक निर्णायक मोड़ के तौर पर याद करेंगे. ऐसा इसलिए भी, क्योंकि जस्टिस दिनाकरन प्रकरण दरअसल न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में प्रोन्नत करने के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के प्रच्छन्न निर्णय के ख़िलाफ़ जनता की जीत के रूप में देखा जा रहा है. इसके बाद न सिर्फ़ जस्टिस दिनाकरन को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने का मामला खटाई में पड़ गया, बल्कि राज्यसभा में उनके ख़िलाफ़ महाभियोग की प्रक्रिया तक शुरू हो गई.

उपरोक्त दोनों मामलों से इस बात का साफ़ पता चलता है कि लोग अब पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हो गए हैं. वे न केवल न्यायपालिका की महत्ता को लेकर सचेत हो गए हैं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की मांग में आवाज़ भी बुलंद करने लगे हैं. आम लोग यह भी कहने लगे हैं कि न्यायाधीशों, जिनमें सर्वोच्च न्यायपालिका से जुड़े न्यायाधीश भी शामिल हैं, को अपने दायित्वों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए. बहरहाल जहां तक इस मामले की बात है, तो इसे काफ़ी गंभीरता और संतुलित तरीक़े से देखे जाने की ज़रूरत है. संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की अगर लोग इस तरह से पड़ताल करने लगेंगे तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विपरीत असर भी पड़ सकता है. ज़्यादा पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही की ज़रूरत है, लेकिन कुछ इस तरह कि यह कोई व्यवधान न डाले और न्यायपालिका की प्रभावशीलता में कोई रुकावट खड़ी न करे. न्यायाधीश जवाबदेह बन सकते हैं, लेकिन न्याय देने के मसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए.

सर्वोच्च न्यायालय ने एक और मामले में जीवन समर्थक ऐतिहासिक फ़ैसला दिया और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फ़ैसले को पलट दिया. एक 19 वर्षीय अनाथ युवती सरिता (नाम बदल दिया गया है), जो चंडीगढ़ स्थित नारी निकेतन में रहती थी और जिसकी दिमाग़ी हालत सही नहीं थी, नारी निकेतन के गार्ड की हवस का शिकार बनी और गर्भवती हो गई. वह बच्चे को जन्म दे या न दे, इस बात पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में मामला गया और न्यायालय ने उसकी दिमाग़ी हालत व गर्भ में पल रहे बच्चे के जन्म के बाद उसके लालन-पालन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए फ़ैसला सुनाया कि उसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए. उसका गर्भ 19 सप्ताह का हो चुका था. मेडिकल टर्म ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंतर्गत गर्भ 20 सप्ताह पुराना हो जाने पर गर्भपात की इजाज़त नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस पर टिप्पणी दी कि प्रकृति की अपनी शक्ति है. जीवन के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला उल्लेखनीय है.

चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाया. इस फ़ैसले को इस लिहाज़ से ऐतिहासिक माना जा सकता है, क्योंकि अदालत ने माना कि चूक के सभी मामलों को चिकित्सकीय लापरवाही नहीं माना जा सकता और सभी लापरवाही के लिए डॉक्टरों को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता है. इस फ़ैसले से उन डॉक्टरों ने चैन की सांस ली, जो अपनी योग्यता और नेक इरादों के बावजूद आपराधिक लापरवाही का आरोप झेल रहे थे. सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि अदालत और उपभोक्ता चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ नहीं हैं और उनकी राय विशेषज्ञों की राय का विकल्प नहीं हो सकती है. इस निर्णय से हज़ारों डॉक्टरों और चिकित्सा सेवा से जुड़े लोगों ने राहत महसूस की.

सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका से ही जुड़े एक शख़्स एडवोकेट आर के आनंद के ख़िलाफ़ सख़्त रवैया अपनाना पड़ा. एक निजी टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू मामले में गवाहों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हुए वरिष्ठ एडवोकेट एवं पूर्व संसद सदस्य आर के आनंद रंगे हाथ पकड़े गए थे. न्यायालय ने बाद में टिप्पणी की, लोकतांत्रिक समाज में कोई भी सामाजिक व्यवस्था संतोषप्रद तरीक़े से तभी काम कर सकती है, जब तक कि उसे वकीलों का पूरा समर्थन हासिल हो और उनके प्रति लोगों का विश्वास पुख़्ता हो. इससे लोगों के आदर्श और उम्मीदें साझा होती हैं. इससे लोगों में यह विश्वास पनपता है कि बार के सदस्य आर्थिक रूप से पहुंच के अंदर हैं और लोगों के लिए उपलब्ध हैं. इससे न्याय प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया में वकीलों की भूमिका एक बार फिर से सामने आई. ग़रीब और अशिक्षित लोग पूरी तरह से वकीलों पर निर्भर होते हैं. वकीलों को अपनी भूमिका पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और अपने मुवक्किल के हित में निभानी चाहिए. लेकिन दुःख की बात है कि कई बार वकील उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, जिस तरह उन्हें करना चाहिए.

इस मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों की करतूत को उजागर करने में मीडिया की भूमिका की सराहना की और पाया कि टीवी चैनल जनहित में महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं और न्याय की पवित्रता को बचाने का काम कर रहे हैं. वर्ष 2009 कुछ ऐसे फ़ैसलों का भी साक्षी रहा है, जिन्होंने देश की न्यायिक व्यवस्था को धूमिल करने का काम किया. चर्चित रुचिका प्रकरण में आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी राठौड़ को सख़्त सज़ा न मिल पाना काफ़ी हैरत में डालने वाला और शर्मनाक था. जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावशाली और शक्तिसंपन्न लोगों ने प्रभावित किया, उसने आम लोगों के मन पर ग़लत असर डाला और न्यायपालिका के स्वतंत्र होने पर सवालिया निशान लगाने का काम किया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक संबंधों से जुड़ी भारतीय दंड विधान की धारा 377 के बारे में एक महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाया. आम लोगों की नज़र में समलैंगिक संबंध भारतीय संस्कृति, मूल्यों और नीति के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए आम लोगों ने इस फ़ैसले के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया और इसे खुले दिल से स्वीकार नहीं किया. इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय मायावती के मूर्ति प्रेम और दो धनी भाइयों की लड़ाई से जुड़े मामलों में भी व्यस्त रहा. उम्मीद की जानी चाहिए कि इस साल न्यायपालिका कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फ़ैसले सुनाएगी और भारतीय लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान करेगी.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

नरेगा के सामने चुनौतियां

25-31 जनवरी के अंक में प्रकाशित आलेख-नरेगा के सामने नई चुनौतियां पढ़ा. नरेगा जैसी अच्छी योजनाएं भी बदइंतज़ामी के कारण अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती हैं. नरेगा का लाभ लेने के लिए पंजीकरण में धांधली हो रही है, वहीं जॉब कार्ड को किराए पर देने का धंधा भी फल-फूल रहा है. नए काम शुरू नहीं हो रहे. काम करने के बाद भी पूरे पैसे न मिलने की शिकायतें आम होती जा रही हैं. ऐसे में ग्रामीण मज़दूरों के कल्याण और गांव के विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है.

मयंक सिंह, जगदीशपुर, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश

प्रकृति के क़रीब जाएं

लेखिका कांची कोहली ने केलो नदी को बचाने की ज़रूरत पर बल दिया है. उनके विचार निस्संदेह सराहनीय हैं. दरअसल, मौजूदा समय में हर नदी और दूसरे जलीय स्रोतों को बचाने की ज़रूरत है. इसमें जनसहभागिता काफ़ी ज़रूरी है. लोगों को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें जागरूक होना ही पड़ेगा.

मीनाक्षी, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश.

शत-शत नमन

वयोवृद्ध राजनेता ज्योति बसु के देहावसान से राजनीति के एक युग का अंत हो गया. उनकी पीढ़ी के गिने-चुने राजनेता ही अब जीवित हैं. वह ताउम्र सक्रिय रहे और उन्होंने ही सही मायनों में पश्चिम बंगाल को विकास की राह पर आगे बढ़ाया. वह हमेशा गरीबों और बेसहारा लोगों के हितों के लिए लड़ते रहे. उन जैसे राजनीतिज्ञ के अवसान से हुई रिक्तता की भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती. देश उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखेगा. ज्योति दा को शत-शत नमन.

मोजाहिद उल इस्लाम सियालदह, पश्चिम बंगाल.

प्रतिस्पर्धा कर आगे बढ़ें

यह सच है कि मुसलमान कई मामलों में पीछे हैं, लेकिन यह कहना कि ऐसा किसी साज़िश के कारण है, सही नहीं है. सारा दोष शासन और सरकार पर थोपना सर्वथा अनुचित है. समाज के अंदर भी उत्थान की कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं सुनाई देती. सिर्फ़ आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिल जाए, यह कैसे मुमकिन है? देश के मुसलमान दया और याचना की राह पर क्यों चलते हैं? उन्हें स्वयं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से यह सब कुछ हासिल करना चाहिए. जब तक वे ख़ुद सामाजिक बुनियादी सुधार की पहल नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा.

शुचि जायसवाल, कटहरी बाग, छपरा, बिहार.

ज्ञानवर्द्धक जानकारियां

चौथी दुनिया का ताज़ा अंक मिला. स्तंभ-जरा हट के की रोचक जानकारियों के साथ ही पाकिस्तान में भ्रम की स्थिति जैसे गंभीर आलेख भी पढ़ने को मिले. इसके अलावा आत्मघाती हमलों को फोकस करके लिखा गया लेख संबंधित विषय की कई परतें उधेड़ता है. आशा है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से हमें यूं ही मिलती रहेंगी.

बृजेश कुमार, कोरबा, छत्तीसगढ़.

थियेटर को भी जगह मिले

मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसुआ की निवासी एवं आपके अख़बार की नियमित पाठक हूं. मेरी रुचि साहित्य, कला और थिएटर में है. पिछले दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का महत्वपूर्ण सालाना उत्सव भारंगम संपन्न हुआ. मुझे उम्मीद थी कि कला-संस्कृति को पूरा एक पन्ना देने वाले आपके अख़बार में नाटकों और थिएटर की हलचल के बारे में पढ़ने को ज़रूर मिलेगा, पर निराशा ही हाथ लगी. उम्मीद है कि आगे से थिएटर जगत की झलकियां भी पढ़ने को मिलेंगी.

रीतिका, हसुआ(नवादा), बिहार.

मां का अपमान

विडंबना देखिए कि जिस गंगा को पूरा देश गंगा मैया के नाम से पुकारता है, उसी नदी के उद्धार के लिए लेख लिखने पड़ते हैं. और तो और, समाजसेवी संस्थाओं को लोगों से गुहार लगानी पड़ती है कि इसे साफ़ रखो. पता नहीं कब सुधरेंगे हम?

प्रीति बाला, लाल चौक(गया), बिहार.

महंगाई मार गई

कभी काका हाथरसी की कविताओं में महंगाई का ज़िक्र सुना था, पहले मुट्ठी भर पैसे लेकर झोले में शक्कर लाते थे, अब झोले में पैसे जाते हैं और मुट्ठी भर शक्कर आती है. आज की महंगाई देखकर उक्त पंक्तियां बरबस ही ज़ुबान पर आ जाती हैं.

रमेश शुक्ला, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश.

समीक्षा ज्ञानप्रद

साहित्य पृष्ठ पर अनंत विजय का आलेख काफ़ी रोचक होता है. पुस्तक समीक्षा के बहाने कई जानकारियों से रूबरू होने का मौक़ा मिलता है. प्रसिद्ध कवि इलियट से जुड़ी कई बातों का पता चला. उम्मीद है कि आगे भी ऐसी सामग्री पढ़ने को मिलती रहेगी.

सुरेंद्र कुमार, छतरपुर, मध्य प्रदेश.

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

आचार्य राममूर्ति जीवित इतिहास हैं

आचार्य राममूर्ति हमारे बीच में हैं और उसी शिद्दत के साथ हैं, जैसे 1954 में थे. 1938 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए इतिहास में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया. 1954 में कॉलेज की नौकरी छोड़कर वह श्री धीरेंद्र मजूमदार के आह्वान पर श्रमभारती खादीग्राम (मुंगेर, बिहार) पहुंचे, जहां उन्होंने श्रम–साधना, जीवन–शिक्षण और सादा जीवन के अभ्यास के साथ एक नए जीवन की शुरुआत की. यहां उन्होंने गांधी जी की कल्पना की नई तालीम का अभ्यास और शिक्षण शुरू किया.

आचार्य राममूर्ति के सही जीवन की शुरुआत खादीग्राम से हुई. आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के सिलसिले में उन्होंने मुंगेर ज़िले की पदयात्रा की, जिसके द्वारा उन्होंने भूदान यज्ञ आंदोलन का विचार प्रसार तथा भूमिहीनता दूर करने के निमित्त जनजागरण किया. आचार्य श्री ने सांप्रदायिक एवं जातीय संघर्षों को कम करने या उन्हें समाप्त करने के कई प्रयोग किए, जिनमें बड़हिया (मुंगेर, बिहार) में बागियों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार करना और उनका आत्मसमर्पण कराना प्रमुख था. वह सर्वोदय आंदोलन के केंद्रीय संगठन सेवा संघ के अध्यक्ष भी बने. सर्वोदय आंदोलन की पत्रिकाओं *नई तालीम, भूदान यज्ञ, गांव की आवाज़* का संपादन भी आचार्य जी ने किया तथा उन्होंने गांव का विद्रोह, शिक्षा संस्कृति और समाज, जे पी की विरासत, भारत का अगला क़दमः लोकतंत्र समेत कई किताबें लिखी हैं.

आचार्य राममूर्ति मूलतः शिक्षक हैं और उन्होंने अपना सारा जीवन समाज को शिक्षित करने में लगा दिया. सन् 1974 में जब जयप्रकाश जी ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ छात्र आंदोलन का समर्थन किया और उसे नेतृत्व देने का फ़ैसला किया तो आचार्य जी उसमें कूद पड़े. आचार्य विनोबा भावे इस आंदोलन को सही नहीं मानते थे, पर आचार्य जी ने अपने साथियों सहित इस आंदोलन को सफल बनाने में जान लगा दी. आचार्य जी बिहार के कोने–कोने में गए और उन्होंने संघर्ष की वैचारिक नींव मज़बूत की. जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति के विचार को जब देश के सामने इस आंदोलन के माध्यम से 1975 में रखा तो आचार्य जी ने इसका वैचारिक भास्य हर जगह जाकर समझाया. आचार्य राममूर्ति की भाषा इतनी सहज, सरल और तार्किक होती थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे. आज भी आचार्य जी की भाषा उतनी ही मीठी, प्रिय, तार्किक, सीधी और सरल है कि बुद्धि बिना ना–नुकुर के उसे सहेज लेती है.

सर्वोदय आंदोलन के कई बड़े नेता चले गए, लेकिन अभी ठाकुरदास बंग, नारायण देसाई और आचार्य राममूर्ति हमारे बीच हैं. आचार्य राममूर्ति ने धीरेंद्र मजूमदार और जयप्रकाश जी के साथ आज़ाद भारत के गांवों, उनके स्वराज्य और स्वराज का सपना देखा था. इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया. सारा जीवन लोकशिक्षण के लिए वह यायावरी करते रहे. अब जब शरीर पूरा साथ नहीं दे रहा तो कभी पटना तो कभी खादीग्राम में रहते हैं. वी पी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आचार्य जी को राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन आचार्य जी ने इसे अस्वीकार कर दिया और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई. तब वी पी सिंह ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में ज़िम्मेदारी दी. उनकी रिपोर्ट शिक्षा नीति और शिक्षा में क्रांति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

आज आचार्य जी की उम्र 97 साल है. तो क्या वह अपनी वृद्धावस्था में ख़ामोश बैठे हैं और केवल समय गुज़ार रहे हैं? आम आदमी के तौर पर इसका उत्तर हां ही हो सकता है, पर यह है नहीं. आचार्य जी ने जनवरी 2010 में अपनी नई पुस्तक लिखी है, महिला शांति सेना: शांति की नई संस्कृति के लिए एक विधायक और रचनात्मक क्रांति. 97 साल की उम्र में भी समाज के लिए सोचने एवं विचार करने के लिए सामग्री और सवाल खड़े करने वाला शख्स हम सबके सलाम का अधिकारी है.

2002 में आचार्य जी ने एक नई शुरुआत की. उन्हें गांधी जी की एक बात याद आई. जब आज़ादी मिलने के कुछ दिन बाकी थे तो एक दिन पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा, "अंग्रेज़ों के जाने के बाद आप कौन सा काम सबसे पहले करना चाहेंगे?" गांधी जी का उत्तर था, "लोकतंत्र को आगे बढ़ाना (सेटिंग डेमोक्रेसी ऑन दि मार्च)." आचार्य जी ने इसी सूत्र को अपना रास्ता बनाया.

सामाजिक कार्यकर्ता, राजनैतिक दलों के नेता आचार्य जी से मिलते रहते थे. वे आचार्य जी को आदर देते थे, लेकिन साथ देने का वायदा नहीं करते थे. सर्वोदय और स्वयंसेवी संस्थाएं भी ख़ामोशी वाला उत्तर देती थीं. आचार्य जी ने एक कोशिश पंचायती राज के पंच पर की. उन्हें पंचायती राज व्यवस्था के अंदर परिवर्तन की एक संभावना नज़र आई, क्योंकि महिलाओं को एक तिहाई स्थान पंचायती राज के हर स्तर पर प्राप्त हुआ. आचार्य जी का मानना है कि महिलाओं में रचना और सृजन की अपार शक्ति छिपी हुई है. वे पंचायती राज के बहाने गांव से लेकर राज्य स्तर तक सभाओं में जाते रहे और अपनी बातें रखते रहे.

27 फरवरी 2002 को महावीर और बुद्ध की धरती वैशाली में दस हज़ार लोगों की सभा हुई, जिसे वैशाली सभा का नाम दिया गया. यहां महिला शांति सेना की घोषणा हुई. यह सभा ऐतिहासिक थी, जिसमें पांच हज़ार से ज़्यादा महिलाएं शामिल थीं. इस सभा के बाद महिला शांति सेना के शिक्षण, प्रशिक्षण और संगठन का काम शुरू हुआ. आज महिला शांति सेना बिहार के अलावा असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा और उड़ीसा तक फैल चुकी है. यह पुस्तक आचार्य जी द्वारा बोले गए, लिखे गए लेखों तथा सवालों–जवाबों का अद्भुत संग्रह है. आइए, आपको झलक दिखाते हैं.

"आज जिस तरह की वैचारिक और विधायक क्रांति की ज़रूरत है, वह उन्हीं लोगों से शुरू होगी, जो सभ्यता के धरातल पर मनुष्य जाति के विकास को कुछ दूर तक देख सकते हैं."

"स्थानीय जीवन सुखी और शांत स्थायी जीवन भारत की दुनिया को एक देन होगी और इसका श्रेय महिला शांति सेना को मिले बिना नहीं रहेगा."

"शांति की संस्कृति एक रचनात्मक आंदोलन है, जो जनमत की शक्ति पर विश्वास रखता है और प्रचलित सत्ता के साथ सम्मानपूर्ण सहयोग करके परिवर्तन की स्थिति पैदा करना चाहता है, क्योंकि उसका विश्वास है कि परिवर्तन पहले नागरिक का होना चाहिए और उसके बाद ही संस्थाओं और संगठन का."

"भावी क्रांति हितों के संघर्ष की नहीं है, बल्कि एक नई मानवीय संस्कृति के निर्माण की है. परिस्थिति की इस बारीकी को जो लोग नहीं समझेंगे, वे चाहते हुए भी क्रांति के वाहक नहीं बन सकेंगे."

"अब बंदूक़ और तलवार के भरोसे परिवर्तन का प्रयोग हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए. मनुष्य को आज तक जो सिखाया गया है, उसे भूलने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा और शिक्षण की सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी, जिन पर आदमी धीरे–धीरे चढ़ सके. हो सकता है कि कुछ सीढ़ियों पर धीरे–धीरे चढ़ने के बाद मनुष्य में छलांग लगाने की शक्ति आ जाए."

"पूंजी से जो विकास होगा, वह थोड़े लोगों के लिए होगा, पूरे समाज के लिए नहीं होगा. पूरे समाज को ध्यान में रखकर परिवर्तन लाने की बात हो तो बेशक़ बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा."

"आज की पंचायत का उद्देश्य स्थानीय जीवन को समग्र और समृद्ध करने का है. पंचायत राज्य शक्ति का अंग नहीं है, बल्कि पंचायत का क्षेत्र स्वतंत्र नागरिक शक्ति का क्षेत्र है. उसमें समता है, सहकार है और सहभागिता है."

जिनके मन में समाज बदलने की, कुछ करने की चाह है, उन्हें आचार्य राममूर्ति के पास जाना चाहिए और उनके अनुभव और ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए. 97 वर्ष की उम्र में भारत के सामाजिक एवं राजनैतिक इतिहास के जीवित और सबसे विश्वसनीय व्यक्ति के पास जाना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों सपने पूरे नहीं होते, क्यों लोग चलते तो मंजिल की तरफ़ हैं, पर क्यों भटक जाते हैं. ले सकें तो वह ताक़त भी उनसे प्राप्त करनी चाहिए कि कैसे 97 वर्ष की आयु में भी मानसिक एवं शारीरिक रूप से चेतन और सक्रिय रहा जाता है. आचार्य राममूर्ति इस समय हमारे देश में अकेले जीवित इतिहास हैं और शांतिपूर्ण बदलाव का ज़िंदा शब्दकोष हैं.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की ज़रूरत

डी आर आहूजा

वरिष्ठ भारतीय नागरिक केंद्र सरकार से परेशानी महसूस कर रहे हैं. वजह यह है कि सरकार उनके हितों के लिए कुछ नहीं कर रही है. ख़ासकर वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय, स्वास्थ्य, शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सरकार उदासीन बनी हुई है. उनका मानना है कि सरकार की सारी योजनाएं सुस्त चाल से चल रही हैं. यहां तक कि बहुचर्चित मेंटनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पैरेंट एंड डिपेंडेंट्स एक्ट अभी तक लागू नहीं किया जा सका. जबकि इस क़ानून को 2007 में ही बनाया गया था. इस अधिनियम के तहत सरकार ने यह प्रावधान किया था कि बूढ़े माता–पिता की देखभाल की ज़िम्मेदारी उन बच्चों और रिश्तेदारों पर होगी, जो उनकी ज़ायदाद के वारिस होंगे. इस अधिनियम में भी कई ख़ामियां हैं. ज़रा सोचिए उन बच्चों के बारे में, जो बेहद ग़रीब हैं. वे अपने माता–पिता की देखभाल कैसे कर सकते हैं? और वैसे लोग, जिनकी अपनी संतान नहीं है, उनकी देखभाल कौन करेगा? इसके अलावा यह क़ानून विदेशों में बसे बच्चों पर भी लागू नहीं होता है. कई माता–पिता कहते हैं कि यह क़ानून भारतीय संस्कृति और परंपरा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि यहां माता–पिता अपने बच्चे के विरुद्ध मामला दर्ज़ करने की जगह उनकी दया पर गुज़र–बसर करना पसंद करते हैं. इसलिए निश्चित तौर पर यह क़ानून असफल ही साबित होता है.

अभी तक की जानकारियों से स्पष्ट है कि यह अधिनियम संसद में पारित हो चुका है. अब इसे राज्य सरकारों को लागू करना है. लेकिन, अभी तक की स्थितियों पर नज़र डालें तो महज़ 21 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस क़ानून को अधिसूचित किया है. अभी भी देखभाल और अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. इसके अलावा कुछ ही राज्यों ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए कोई क़ानून बनाया है. इस क़ानून को बड़े ही शोरशराबे के साथ पारित किया गया था, लेकिन अभी तक इससे किसी भी वरिष्ठ नागरिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. मंत्रालय ने बेहद चालाकी से बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी को राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया है. इन राज्यों को भी बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए वृद्ध आश्रम और विशेष अस्पताल बनाने की ज़रूरत है. इन अस्पतालों में ख़ासकर बुज़ुर्गों से संबंधित बीमारियों के इलाज की व्यवस्था हो. लेकिन, राज्य सरकारें ख़ुद को बेबस और लाचार महसूस कर रही हैं. ये सरकारें पहले से ही पैसों की कमी का रोना रो रही हैं. राज्य सरकारों का कहना है कि वह पहले ही कर्ज़ में हैं और ऐसे में केंद्र की यह ज़िम्मेदारी उन्हें कंगाल बना देगी.

कई समाजशास्त्रियों और विद्वानों ने इस अधिनियम का बारीकी से अध्ययन किया है. उनके मुताबिक़, यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए महज़ खानापूर्ति है. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए एक काउंसिल का गठन किया था, लेकिन उसकी बैठकें भी लगभग न के बराबर हुईं. इस तरह वह केंद्र सरकार की हितकारी योजनाओं को लागू करने में असफल रही.

फोटो–प्रभात पाण्डेय

इन बातों से यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि ऐसे बुज़ुर्ग माता–पिता की संख्या बहुत बड़ी है, जिनकी देखभाल नहीं हो रही है अथवा संयुक्त परिवार के टूटने के कारण उनकी ज़्यादा उपेक्षा हो रही है. लेकिन इस अवधारणा को उन विद्वानों द्वारा चुनौती दी जा रही है, जो जनगणना के मुताबिक़ सूक्ष्म स्तर पर परिवारों और उनमें रहने वाले सदस्यों का आकलन कर रहे हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक़, यह बात सामने आई है कि आज परिवार अधिक तनाव झेल रहे हैं. और, साथ ही वे परिवार के बुज़ुर्ग सदस्यों की देखभाल करने में ख़ुद को लाचार महसूस कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह एक समुचित फैमिली पॉलिसी और हितकारी सेवाओं का न होना है. वे शायद ही बुज़ुर्गों की देखभाल की बात सोचते हैं. ख़ासकर उस हालात में, जब उनके पास सीमित संसाधन होते हैं. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व निदेशक आर आर सिंह और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अन्य शिक्षक कहते हैं, अधिनियम में प्रस्तावित बातें एक हितकारी योजना की अपेक्षा राजनीतिक बयानबाज़ी ज़्यादा लगती हैं. हालांकि लोकतंत्र में व्यवस्थापिका ही सामाजिक और दूसरे मुद्दों के लिए क़ानून बनाती है. लेकिन यह विधेयक पेशेवर होने के बनिस्बत नीतिसंगत अधिक है. वरिष्ठ नागरिक यह चाहते हैं कि हित का मतलब क्या है, इसे परिभाषित किया जाना चाहिए. साथ ही अंतरिम देखभाल के लिए एक प्रावधान होना चाहिए. इसके तहत राज्यों के ख़ज़ाने से सहायता दी जानी चाहिए और इसकी भरपाई उन लोगों से करनी चाहिए, जो इस क़ानून को तोड़ते हैं अथवा जो भुगतान के रखरखाव में धोखाधड़ी के लिए क़सूरवार हैं. यह राशि 10 हज़ार रुपये प्रति माह तय की जा रही है. इससे तो यह भी ज़ाहिर होता है कि जो जेल में हैं, वे नौकरी से हाथ धो सकते हैं और नतीजतन देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने में असफल हो सकते हैं. ऐसे हालात में किसी राज्य का क्या दायित्व होगा? इस विधेयक को और अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा और अक्षमता अधिकार भी इसमें निहित होने चाहिए. प्रो. सिंह के मुताबिक़, सरकार अंतरिम राहत उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए विशेष वेलफेयर फंड संबंधित बैठकें न होने के मामलों की जांच कर सकती है. सरकारी अस्पतालों में हड़ताल होने की हालत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठीक इसी तरह की समस्या सामने आती है. फिर भी यह सवाल शेष रह जाता है कि पुरानी और असाध्य बीमारियों पर होने वाले ख़र्चे का सारा भुगतान कौन करेगा? राज्य जब तक सहयोगी रुख़ नहीं अपनाएगा और इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता नहीं जताएगा, तब तक सिर्फ़ पैसे के ज़रिए भी वरिष्ठ नागरिकों की मदद नहीं हो सकती है. इसमें न्याय के सिद्धांत, अक्षमता अधिकार और विशेष सामाजिक सुरक्षा को शामिल किया जाना चाहिए.

इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें बुज़ुर्गों के लिए आवास बनाएंगी और उसकी देखभाल करेंगी. हर ज़िले में 150 लोगों की क्षमता वाले एक आवास की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, वे इसमें रह सकें. लेकिन, यह सिर्फ़ भगवान ही जानते हैं कि इस तरह के आवास कब बनेंगे और राज्य सरकारें उनकी देखभाल करेंगी. वैसी राज्य सरकारें, जो ख़ुद संसाधनों की कमी झेल रही हैं. हालांकि बुज़ुर्ग माता–पिता की देखभाल के लिए क़ानून का प्रावधान पहले से ही मौजूद है. इसके तहत माता–पिता अपने गुमराह बच्चों पर मुक़दमा दर्ज़ कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति और परंपराओं की वजह से उन्होंने इस क़ानून का उपयोग नहीं किया. कई माता–पिता अपने बच्चों को बदनाम करने में बुद्धिमानी नहीं समझते. कई माता–पिता शिक्षित नहीं हैं, ख़ासकर बुज़ुर्ग महिलाएं और विधवाएं, जो पूरी तरह अपने परिवारों पर आश्रित हैं. उनकी संवेदनशीलता उन्हें समस्याओं के ख़िलाफ़ बोलने से रोकती है. उनकी मानसिकता अपने सगे–संबंधियों को ठेस पहुंचाने की अपेक्षा ख़ुद अभाव में ज़िंदगी गुज़ारने की होती है.

एनआईएचएफडब्ल्यू के समाज विज्ञान के विभागाध्यक्ष एम एम ख़ान कहते है, ऐसा लगता है कि इस विधेयक का मसौदा संवैधानिक प्रावधानों के दायित्वों की खानापूर्ति के लिए तैयार किया गया है. और, साथ ही इसमें ज़मीनी हक़ीक़त को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया है. हमें संविधान के व्यापक परिदृश्य को समझने और क़ानूनी पचड़ों के मकड़जाल से बचने की ज़रूरत है. विधेयक को सामाजिक आधार पर तैयार किया जाना चाहिए. बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाया जाना चाहिए. बुज़ुर्गों के लिए आवास की व्यवस्था के संबंध में देखें तो यह विधेयक राष्ट्रीय नीति की नक़ल लगता है, जिसमें किसी व्यवस्था को लागू करने के पहले उस पर कोई चर्चा ही नहीं होती है. संक्षेप में कहें तो यह विधेयक बुज़ुर्गों की ज़िंदगी बेहतर बनाने की दिशा में असली समस्याओं पर ध्यान नहीं देता. यह विधेयक चलाऊ व्यवस्था जैसा लगता है. भारतीय दंड संहिता के तहत अनुच्छेद 25 में यह बात पहले ही कही गई है कि यदि माता–पिता के पास कोई संसाधन नहीं है तो उनके बच्चों को उनकी मदद करनी चाहिए. हिंदुओं में बच्चों को गोद लेने एवं पालन पोषण संबंधी अधिनियम 1956 में भी माता–पिता के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई है. वह कहते हैं कि मौजूदा स्वरूप में विधेयक बनाने से बुज़ुर्गों की सभी ज़रूरतों को हल नहीं किया जा सकेगा.

माला कपूर शंकरदास एक समाजशास्त्री हैं. वह कहती हैं कि बुज़ुर्गों की ज़रूरतों का समाधान समन्वित तौर पर होना चाहिए. सहायता विविध एजेंसियों से उपलब्ध कराई जानी चाहिए. मसलन सरकार, सभ्य समाज, ग़ैर सरकारी संगठन और स्वयं वरिष्ठ नागरिकों की ओर से. वह कहती हैं कि ट्रिब्यूनल के गठन और मामलों के समाधान के लिए अधिकारियों के पास भेजने से बुज़ुर्ग माता–पिता भावनात्मक तौर पर असुरक्षित ही महसूस करेंगे. सिर्फ़ क़ानून बनाकर वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता है. इसकी वजह यह है कि सेवा एवं सुविधाओं को मानवीय और सम्मानित तरीक़े से लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है. माला कपूर कहती हैं कि ये समाधान किस तरह ज़िंदगी को आदर और सम्मान से जीने में सहायक बनेंगे, यह अभी देखना है.

(लेखक ट्रिब्यून के ब्यूरो प्रमुख रह चुके हैं)

feedback@chauthiduniya.com

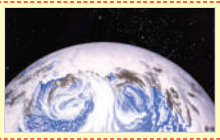

लॉर्ड रीस ने कहा कि लगभग 50 वर्षों से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जीवन का पता लगाने की कोशिश में लगे हैं.

दिल्ली, 8 फरवरी-14 फरवरी 2010 चौथी दुनिया

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

केजीबी की ख़ौफ़नाक कहानी आज भी जारी है

तारीख़ 23 नवंबर 2006. इस दिन एक शख्स, जिसे फूड प्वाइजनिंग की शिक़ायत थी, अस्पताल में भर्ती हुआ. कुछ दिनों तक यह शख्स ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा. लेकिन इस जंग में ज़िंदगी मौत से हार गई. डॉक्टरों के मुताबिक़, उसकी मौत खाने में रेडियो एक्टिव तत्व के मिले होने से हुई. सोवियत संघ के जमाने में इस तरह के मामले में दुनिया भर के अस्पतालों में अक्सर आते रहते थे. और, हर किसी का अंजाम भी वही होता था, जो इस शख्स का हुआ. यानी मौत. दरअसल यह कारनामा सोवियत संघ की शातिर ख़ुफ़िया एजेंसी केजीबी करती थी. अपने राजनीतिक दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए सोवियत संघ अक्सर इस तरह के मिशन की इजाज़त केजीबी को देता था.

लेकिन हम यहां जिस शख्स की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि एलेक्जेंडर लित्विंनेको है. एलेक्जेंडर सोवियत संघ की ख़ुफ़िया एजेंसी केजीबी का जासूस रह चुका था. इतना ही नहीं, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और रूस अपने वजूद में आया, तो इस नवोदित मुल्क में भी उसने जांच एजेंसी एफएसबी में अहम ओहदे की ज़िम्मेदारी संभाली. यानी एक तरह से देखें तो एलेक्जेंडर रूस की सभी छोटी बड़ी ख़ुफ़िया गतिविधियों और कारनामों से पूरी तरह वाक़िफ़ था. एफएसबी में अधिकारी के तौर पर काम करने के दौरान उसने रूसी राजनीति और प्रशासन एवं माफ़िया के बीच के कई दाग़दार संबंधों को उजागर किया. माफ़िया और रूसी राजनीति के बीच के काले चिट्ठों को उजागर करने वाले एलेक्जेंडर के संबंध तत्कालीन राष्ट्रपति से भी अच्छे नहीं रहे. कई लोगों का तो यहां तक मानना है कि एलेक्जेंडर को इस राष्ट्रपति के इशारे पर ही मारा गया. यानी उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई थी. यही वजह है कि उसकी मौत की साज़िश की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है. अपनी मौत के पहले ख़ुद एलेक्जेंडर ने भी उस राष्ट्रपति पर आरोप लगाए कि उसे खाने में ज़हर देकर मारने की साज़िश की गई है. इस राष्ट्रपति पर लगे इन आरोपों का खुलासा रेड हॉरिजोन नामक किताब में भी किया गया है. लेकिन यहां सवाल उठता है कि इस राष्ट्रपति ने एलेक्जेंडर लित्विंनेको की हत्या क्यों करवाई? भला इससे उसका क्या फ़ायदा होने वाला था? रेड हॉरिजोन नामक किताब के मुताबिक़, एलेक्जेंडर को इस राष्ट्रपति के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पता चल गया था. ज़रा सोचिए, यदि किसी राष्ट्रपति से जुड़ी कोई भी अहम जानकारी पूरी दुनिया के सामने आ जाए तो भला उसका अंजाम क्या हो सकता है? यहां तक भी यदि बात सिमटी रहती तो, कुछ नहीं बिगड़ता. लेकिन एलेक्जेंडर की मानें तो रूसी एजेंसी

सोवियत संघ का ख़ुफ़िया आतंक

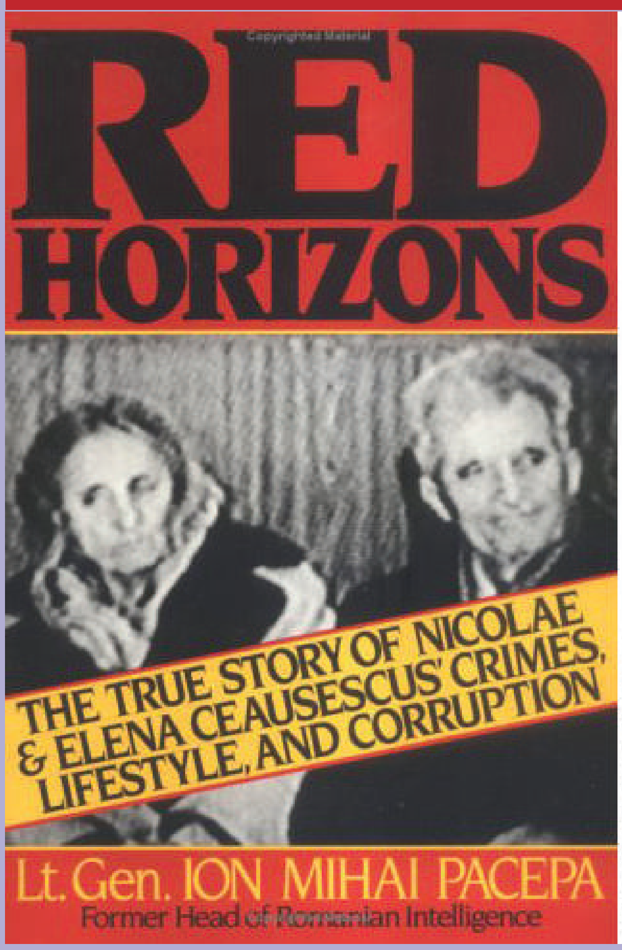

एलेक्जेंडर लित्विंनेको

एफएसबी ने अलक़ायदा के एक बहुत बड़े आतंकी को ट्रेनिंग दी थी. वह आतंकी कोई और नहीं, बल्कि अलक़ायदा में दूसरे नंबर का ओहदा संभालता है. हालांकि इस बात में सच्चाई कितनी है, इसका ख़ुलासा अब कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस राज़ को जानने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा. ऐसे कुछ और संगीन आरोप थे, जिसे एलेक्जेंडर ने रूसी राष्ट्रपति पर लगाए थे. और, जब वह फूड प्वाइजनिंग का शिकार हुआ तो उसने खुलेआम आरोप लगाया कि यह उसको मारने की साज़िश है, ताकि वह उसके राज़ को पूरी दुनिया के सामने कभी न ला सके. लेकिन रेड हॉरिजोन नामक किताब के मुताबिक़, यह पहली बार नहीं था, जब कोई फूड प्वाइजनिंग के चलते अस्पताल में दाख़िल हुआ और मौत की नींद सो गया. सोवियत संघ की ख़ुफ़िया एजेंसी केजीबी पहले भी कई ऐसे वारदातों को अंजाम दे चुकी थी. और मौजूदा रूसी एजेंसी भी राजनीति और अहम शख्सियतों की हत्या के लिए इस कारगर तरीक़ो को अपनाती हैं.

हम आपको बता दें कि वह राष्ट्रपति आज भी रूसी राजनीति में सक्रिय है. फ़िलहाल वह एक ऐसे ओहदे को संभाल रहा है, जो फ़ैसला लेने के हिसाब से ज़्यादा प्रभावशाली ओहदा नहीं है, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति से उनके संबंध काफ़ी बेहतर हैं. यदि कहा जाए कि राष्ट्रपति के ज़रिए वह रूस की सत्ता अप्रत्यक्ष तौर संभाले हुए हैं तो कतई ग़लत नहीं होगा. रूस के पूर्व राष्ट्रपति एवं फ़िलहाल रूसी राजनीति की अहम धूरी. जी हां, यही पहचान है उस शख्स की. लेकिन, वह सिर्फ़ एक राजनयिक ही नहीं हैं. उनकी जो सबसे असली पहचान है, वह बहुत ही कम लोगों को मालूम है. केजीबी के नाम से तो अब हमसभी वाक़िफ़ हो चुके हैं. शायद आप सोच रहे हैं कि केजीबी और पूर्व राष्ट्रपति के बीच क्या ताल्लुक़ हो सकते हैं? लेकिन हम आपको बता दें कि केजीबी और इस राष्ट्रपति के बीच बेहद ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं. इसी रिश्ते में छिपी है, उनकी असली पहचान. जी हां, रूस के पूर्व राष्ट्रपति के अलावा एक और पहचान है इस शख्स की. वह सोवियत संघ की ख़ुफ़िया एजेंसी केजीबी के जासूस रह चुके हैं. केजीबी में उनका ओहदा काउंटर इंटेलिजेंस के अधिकारी के तौर पर था. जहां उनका काम विदेशी ख़ुफ़िया जानकारियां जुटाना था.

दुनिया की सबसे ख़तरनाक ख़ुफ़िया एजेंसी केजीबी तो अब नहीं रही, लेकिन केजीबी में जासूसी का काम कर चुके इस पूर्व राष्ट्रपति की कार्य शैली की झलक आज भी उनके फ़ैसलों और गतिविधियों में मिलती है. लेकिन, यहां हम उनकी इन गतिविधियों के बारे में नहीं, बल्कि उनकी उस ख़ौफ़नाक करतूत की बात करेंगे, जिसे सुनकर ही होश फाख्ता हो जाता है. मुमकिन है कई लोगों को आज भी यह यक़ीन न हो, लेकिन यहां यह बात भी ज़ाहिर करना ज़रूरी है कि ख़ुफ़िया एजेंसियों की गतिविधियों को कभी क़ानूनी तौर पर अथवा दुनिया के सामने क़बूला नहीं गया है. क्योंकि पूरी दुनिया के सामने इन बातों को लाने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है और ज़रा सोचिए भला कौन सी ऐसी ख़ुफ़िया एजेंसी होगी, जो अपने कारनामे को अंजाम देने के बाद मौक़ा-ए-वारदात पर सबूत छोड़ती है. हालात तो यहां तक होते हैं कि यदि भूल से भी किसी को उनके कारनामों पर शक़ भी हो जाता है तो ये एजेंसियां, उनको भी हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए उनका काम तमाम कर देती हैं.

कुछ यही कहानी है, इस राष्ट्रपति की. रूस की ही जांच एजेंसी एफएसबी के एक बड़े अधिकारी एलेक्जेंडर लित्विंनेको ने उस पर बेहद संगीन आरोपों का ख़ुलासा करना चाहा. लेकिन उसे हमेशा के लिए उसके सबूत के साथ इस दुनिया से चलता कर दिया गया. उसे ठीक उसी तरह मारा गया, जैसे सोवियत संघ के ज़माने में केजीबी अपने दुश्मनों का सफ़ाया करती थी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना बढ़ी !

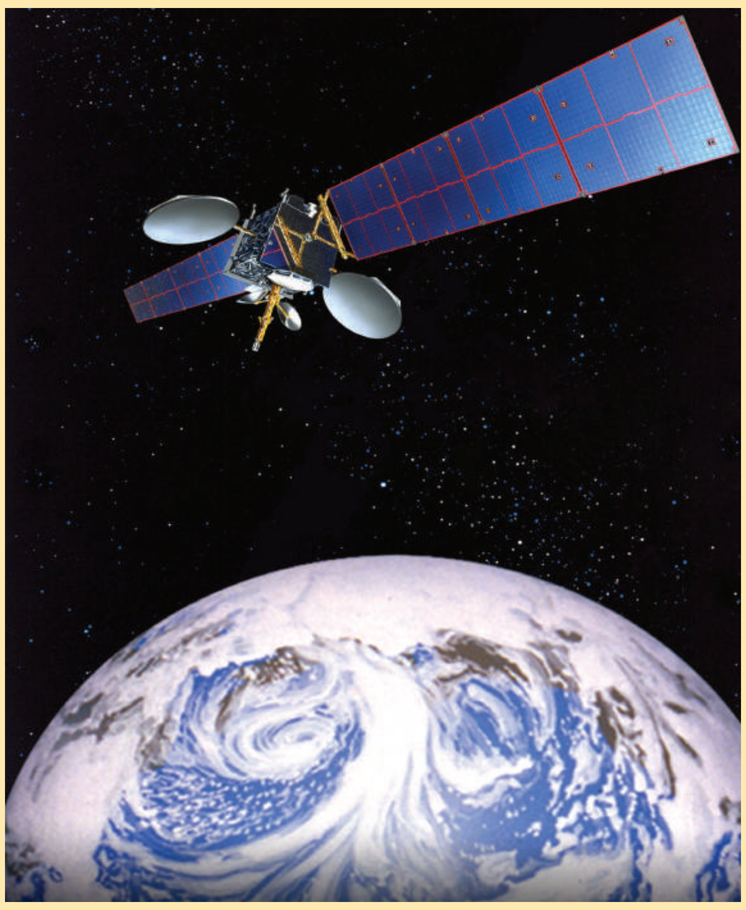

क़रीब पचास वर्षों से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जीवन का पता लगाने में जुटे हैं, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली है. हालांकि अंतरिक्ष में नए दूरबीन लगाए जाने से पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों के मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है. ब्रिटेन के खगोलशास्त्री का मानना है कि पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों पर जीवन और एलियन के मिलने की संभावना पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी है. प्रसिद्ध खगोलशास्त्री लार्ड रीस ने दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश के शीर्षक तहत लंदन में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं, जहां दुनिया भर के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री एकत्रित हुए थे. रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष और खगोलशास्त्री मार्टिन रीस ने कहा कि अंतरिक्ष में नए दूरबीन के लगाए जाने के बाद से पृथ्वी की तरह के दूसरे ग्रहों के मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है.

लॉर्ड रीस ने कहा कि लगभग 50 वर्षों से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जीवन का पता लगाने की कोशिश में लगे हैं. इतना ही नहीं, वे जीवंत आवाज़ें सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली है. उन्होंने कहा, अब यह इसलिए संभव नज़र आने लगा है क्योंकि टेक्नोलॉजी में व्यापक तरक़्क़ी हुई है और वास्तव में अब हम यह आशा कर सकते हैं कि दूसरे तारामंडल में हम पृथ्वी के आकार का ग्रह तलाश कर सकेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि जहां इससे ज़मीन जैसे ग्रहों के मिलने की संभावना बढ़ी है. वहीं जीवन के मिलने की संभावना भी बढ़ी है.

कौआ और मानव चेहरा

अगर आप किसी कौए को मारते या परेशान करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि कौआ उसे याद नहीं रखता है. वह उस व्यक्ति के चेहरे को काफ़ी लंबे समय तक याद रखता है, जो उसे तंग करता है. यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसका खुलासा एक शोध में हुआ है. शोध के मुताबिक़, बदमाश कौआ उस व्यक्ति के चेहरे को कई वर्षों तक याद रखता है, जो उसे सताता है.

हालांकि यह क्षमता -इस तरह की क्षमता अन्य जानवरों में भी होती है- इस बात को दर्शाता है कि जानवर कितनी सावधानी के साथ मानव की निगरानी करते हैं. इस अध्ययन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में जॉन मार्जलुफ और उनके सहयोगियों ने रबड़ का मुखौटा पहना और अमेरिका के जंगली कौए को अपने क़ब्ज़े में ले लिया. उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस मुखौटे को पहनकर कौए को पकड़ने जाता तो पक्षी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते. वहीं दूसरी तरफ़ वे उस व्यक्ति की तरफ़ ध्यान नहीं देते जिसने अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति का मुखौटा पहन रखा था.

मार्जलुफ के अनुसार, कभी कभी तो आप उसके बिल्कुल क़रीब पहुंच जाते हैं. फिर भी उन्हें इसकी तनिक भी चिंता नहीं होती है. इस तरह दूसरे शोध में मार्जलुफ की टीम ने छह मुखौटे तैयार किए. यह मुखौटा लोगों के चेहरे को ध्यान में रखकर तैयार किया गया. इस तरह कौए को पकड़ने के लिए उन्होंने अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह के मुखौटे पहने, लेकिन सभी मामले में कौए ने उस मुखौटे को पहचानकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. उस मुखौटे की ओर कौए ने ध्यान नहीं दिया, जिसे उसने कभी देखा नहीं था. इससे यह स्पष्ट होता है कि कौआ मानव के हर क्रिया को बड़े ही ध्यान से देखता है. इस शोध को शोध पत्रिका एनिमल बिहेवियर में प्रकाशित किया गया है.

राशिफल

8 फरवरी-14 फरवरी 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल): व्यवसाय के क्षेत्र में व्यस्तता अधिक रहेगी. कुछ विरोधियों से तनाव मिल सकता है. व्यर्थ की उलझनें व भागदौड़ रहेगी. यात्रा देशाटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि सुखद व लाभदायी साबित होगी. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई): शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जा रहा श्रम सार्थक होगा. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव में वृद्धि होगी. बच्चों पर ध्यान दें.

मिथुन (21 मई से 20 जून): निजी संबंधों में निकटता आएगी. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. रोज़गार की दिशा में आशातीत सफलता मिलेगी. ख़र्च में बढ़ोतरी हो सकती है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई): मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे. धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. संबंधों में निकटता आएगी. किसी से उलझना भारी पड़ सकता है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त): उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. किसी कार्य के पूर्ण होने की अभिलाषा पूरी होगी. व्यवसायिक मामलों में भागदौड़ रहेगी. आर्थिक क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर): जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. यात्रा देशाटन की दिशा में प्रगति होगी. पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर): आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, लेकिन व्यावसायिक तनाव रहेंगे. कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपके हित में न हो. उपहार, सम्मान के साथ कोई अप्रिय समाचार भी मिल सकता है. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर): पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी. उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा. जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी. यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी. धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर): रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. लेकिन रुपये पैसे के लेन-देन में सावधानी अपेक्षित है. निजी सुख में व्यवधान आएगा. मन अशांत हो सकता है. व्यवसायिक योजना को बल प्रदान करें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी): विरोधी सक्रिय रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी. विरोधियों के कारण आप चिंतित रहेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा. मांगलिक कार्य अथवा वंश वृद्धि की संभावना है. भौतिक उपलब्धि या व्यवसायिक प्रगति के योग बने हुए है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी): अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है. व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा. शासन सत्ता का सहयोग लेने में सफलता मिलेगी. विरोधी सक्रिय रहेंगे. भागदौड़ रहेगी. रुके कार्य संपन्न होंगे. अनावश्यक ख़र्च में कटौती करें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च): व्यवसायिक प्रगति होगी. आय के क्षेत्र में नए रास्ते बनेंगे. धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहें है तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं. उपहार, देशाटन, मनोरंजन की संभावना है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

हैती के लिए सुधार का मतलब है अमेरिकी व्यापार एवं निवेश के लिए दरवाज़े खोलना. इसे अमेरिकी लोगों के लिए अपने बाज़ार खोलने पर मजबूर किया गया.

नाज़ुक मोड़ पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध-II

मानव विकास में ऑस्ट्रेलिया दक्ष है, जबसे उसने ऑल व्हाइट पॉलिसी को प्रतिबंधित किया. ऐसा उसने बहुसंस्कृतिवाद एवं अनेकता में अपने विश्वास और भरोसे के चलते किया, न कि दूसरे देशों से किसी तरह की समानता के कारण. आगे भी ऑस्ट्रेलिया ऐसे कीर्तिमान स्थापित करता रहे, जिससे उसका तट तमाम विदेशी समुदायों के आकर्षण का केंद्र बना रहे, न कि वह दूसरे देशों की विफलता को समझने में अपनी कमज़ोरी को छिपाए.

आशुतोष मिश्र

नस्लवाद और भेदभाव की समस्या सभी मुल्कों और समाजों में आम बात है. पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता तो कम कैसे किया जा सकता है या फिर रोका कैसे जा सकता है? जहां तक सवाल ऑस्ट्रेलिया का है, समाधान को तीन स्तरों पर लागू किया जा सकता है, अल्पकालिक, मध्यम और दूरगामी. छोटे स्तर की रणनीति के तहत छात्रों को सुरक्षा दी जा सकती है और उनके अंदर के भय को दूर करने की कोशिश की जा सकती है. इसके लिए उन जगहों पर पेट्रोलिंग करने की ज़रूरत होगी, जहां इस तरह की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं. साथ ही छात्रों में विश्वास बहाली के लिए सार्वजनिक जगहों की निगरानी एवं विद्यार्थी समुदाय से जुड़ने की भी कोशिश होनी चाहिए. आमतौर पर तत्कालीन समाधान के लिए क़ानूनी प्रक्रिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत है. थोड़े अधिक समय के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय शिक्षा को चुस्त-दुरुस्त करे. साथ ही स्टूडेंट माइग्रेशन उद्योग को नियंत्रित करे. हाल के महीनों में इससे जुड़े 15 बिलियन डॉलर के व्यापक फ़र्ज़ीवाड़े और इस उद्योग से संबंधित घोटाले की तरफ़ अधिकारियों का भी ध्यान गया है, लेकिन स्टूडेंट इमिग्रेशन प्रक्रिया के जटिल एवं वृहद होने के चलते बदलाव और मनचाहा नतीजा हासिल होने में कुछ वक़्त लग सकता है. हाल के महीनों में मंत्रालयों और नौकरशाही स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि इस मक़सद के लिए एकता दिखाई जा रही है. ऑस्ट्रेलिया में विद्यार्थियों की शिक्षा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए कम से कम तीन से पांच साल लग जाएंगे. इसकी वजह यह है कि धोखेबाज़ शिक्षा एजेंट और भर्ती एजेंसियां स्टूडेंट माइग्रेशन प्रक्रिया में अपनी जड़ें जमा चुके हैं. दूरगामी रणनीति ऑस्ट्रेलिया की पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी है. साथ ही यह प्रक्रिया माता-पिता के सामाजिक दायित्वों से संबंधित है. इसके तहत माता-पिता को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और उन्हें अनुशासित करना ज़रूरी हो जाता है.

भारतीय प्रतिक्रिया पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और नीति निर्धारकों के बीच पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है. लेकिन हक़ीक़त यह है कि इस तरह की कोई व्यापक प्रतिक्रिया भारतीयों की ओर से देखने को नहीं मिली.

ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क रहा है, जहां आपराधिक, धार्मिक और नस्लवादी घृणा के ख़िलाफ़ कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं. ऑस्ट्रेलियाई क़ानूनों के तहत स्कूलों को किसी भी आधार पर नस्लवाद और भेदभाव को रोकने के लिए विशेष ज़िम्मेदारी दी गई है. किसी दूसरे लोकतांत्रिक मुल्क की तरह ऑस्ट्रेलियाई क़ानून रंग, राष्ट्रीयता, सामाजिक या जाति-धर्म के आधार पर भेदभाव रोकने में पूरी तरह सक्षम है. दूरगामी समाधान के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल एक बार फिर अपनी ज़िम्मेदारियों की अहमियत को समझें. उनकी यह ज़िम्मेदारी बच्चों को सिर्फ़ शिक्षित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बहुसांस्कृतिक समाज के बारे में शिक्षित करने से भी जुड़ी है. जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार समाज की छोटी इकाई है. यदि माता-पिता एवं बड़े घर पर अनुशासन और तहज़ीब बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं, तो ऐसे में स्कूलों की मेहनत बेकार हो जाएगी. माता-पिता अपने बच्चों के पहले रोल मॉडल होते हैं और उन्हें इसकी मिसाल पेश करनी चाहिए. आधुनिक जीवनशैली की ज़रूरतों के बावजूद उन्हें बच्चों को बुनियादी नैतिकता की जानकारी देनी चाहिए.

भारतीय प्रतिक्रिया पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और नीति निर्धारकों के बीच पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है. लेकिन हक़ीक़त यह है कि इस तरह की कोई व्यापक प्रतिक्रिया भारतीयों की ओर से देखने को नहीं मिली. भारतीय मीडिया की प्रतिक्रिया को भारतीय प्रतिक्रिया के तौर पर माना गया, जो कि सही नहीं है. आधिकारिक तौर पर भारत ने जो प्रतिक्रिया दी, वह बेहद ही संतुलित थी. भारतीय विदेश मंत्री एस एम कृष्णा ने प्रतिक्रिया दी कि इन हमलों से दोनों देशों के आपसी संबंधों पर असर पड़ेगा. लेकिन उनका यह बयान आम आदमी के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है. यहां तक कि इस तरह की प्रतिक्रिया देर से और विपक्ष की आलोचना के बाद दी गई. ऑस्ट्रेलिया के विदेशमंत्री सिमोन क्रीन ने यह प्रतिक्रिया दी कि भारत को उन्माद नहीं पैदा करना चाहिए. ऐसे संवेदनशील हालात में शायद यह आदर्श प्रतिक्रिया नहीं थी. पिछले 15 सालों में मीडिया क्रांति ने लोगों को हर घंटे जागरूक करके सरकार के काम को और भी कठिन बना दिया है. संक्षेप में कहें तो ऑस्ट्रेलिया की कोई भी ख़बर भारत में बहुत तेज़ी से फैल जाती है और चंद मिनटों में इसे सुदूर तक फैलने से कोई नहीं रोक सकता है. भारतीय मीडिया का एक तबका ख़बरों को सनसनीख़ेज़ तरीक़े से पेश करने में शामिल रहा है. लोगों को सूचित करने और मुद्दों को सनसनीख़ेज़ बनाने में काफ़ी अंतर है और इसीलिए मीडिया से समझदारी से पेश आने की अपेक्षा की जाती है तो इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है. मौजूदा सरकार ने मीडिया से कहा है कि वह मुद्दों को सनसनीख़ेज़ न बनाए और रिपोर्टिंग में संयम बरते. इस बात का ऑस्ट्रेलिया में स्वागत किया गया है.

शैक्षणिक और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में इस पर ज़ोरदार बहस हुई है कि किसी एक घटना के बारे में दर्शकों को हर पल की जानकारी दी जाए या नहीं? इस पर लोगों की राय

अलग-अलग है, लेकिन इस मसले पर आम सहमति है कि संवेदनशील मामलों में मीडिया द्वारा संयम बरतने से नुक़सान कम होगा. भारतीय मीडिया के एक तबके को इस तरफ़ ख़ास ध्यान देना होगा.

इसके अलावा धैर्य बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी है. ख़ासकर भारत की ओर से. भारत पिछले छह दशकों से जातिवाद, सांप्रदायिकता और जातीय समूहों में संघर्ष को झेल रहा है. इस तरह की समस्याएं काफ़ी अंदर तक जड़ें जमा चुकी हैं और इनका कोई तय समाधान नहीं है. यदि ऑस्ट्रेलिया यह क़बूल भी करता है कि कुछ हमले नस्लवादी थे तो भी उसे रोकने और निपटने के लिए कुछ वक़्त और धैर्य की ज़रूरत होगी. ऑस्ट्रेलिया भी यह जानता है कि यदि भारतीय छात्रों पर लगातार हमले होते रहे तो यह बातें सुर्ख़ियों में बनी रहेंगी और भारतीय लोगों के गुस्से को बढ़ाने में ईंधन का काम करेंगी. हमले के बाद तुरंत की गई कार्रवाई से भारत में शांति का माहौल बनाने में मदद मिलेगी.

लेकिन कैनबरा और मेलबोर्न ने इस प्रक्रिया में अपना योगदान देने का अवसर गंवा दिया. शायद यह सोचकर कि कुछ हमलों में नस्लवाद की बात क़बूलने से पूरे राज्य या देश पर इसका ठप्पा लग जाएगा. सिर्फ़ भारत के मामले में देखें तो कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक और जातिवाद की मौजूदगी क़बूलने का मतलब यह नहीं है कि पूरा देश और पूरी आबादी सांप्रदायिक या जातिवादी है. इसके विपरीत इस तरह के मामलों की पहचान करने से उन्हें सुलझाने में मदद मिलेगी. जबकि यह सोचकर इसे नकारना कि धीरे-धीरे यह समस्या कम हो जाएगी, नकारात्मक असर डालेगा. ऑस्ट्रेलिया के मामले में, एशियाई समुदाय ने इस मुल्क को अपना ठिकाना यह सोचकर नहीं चुना कि यह नस्लवादी है. और, इस विश्वास को बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

इस तरह कुछ हमलों के नस्लवादी होने की बात क़बूलने को ईमानदार और तर्कसंगत नीति के तौर पर देखा जाएगा. हाल में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त पीटर वर्गीज़ ने यह स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया अपने नागरिकों को सुरक्षा की सौ फ़ीसदी गारंटी नहीं दे सकता. यह किसी दूसरे मुल्क के बूते की भी बात नहीं है. विक्टोरिया के मुख्य पुलिस आयुक्त सिमोन ओवरलैंड का यह कहना कि भारतीय छात्रों को एक हद तक लूटपाट के इरादे से निशाना बनाया गया है और यह सही नहीं है. इस बात को जिस लहज़े में कहा गया, उससे भारतीय समुदाय में एक सकारात्मक संदेश गया है. इससे यह साबित होता है कि इस तरह की साहसिक और ईमानदार पहल से न केवल आलोचनाएं बंद होंगी, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों की बहाली में मदद मिलेगी और स्थानीय समुदायों में सद्भावना बढ़ेगी.

(लेखक ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट इंवेस्टिगेटर हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

हैती की बर्बादी के लिए अमेरिका ज़िम्मेदार

रूपा चिनाय

भारत की जनता के लिए हैती कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा. इसके बावजूद भारत सरकार की हैती में मौजूदगी दक्षिण देशों की एकता का एक मज़बूत उदाहरण है. 2006 से ही दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील के साथ भारत हैती में एक ऐसे कार्यक्रम में लगा है, जिसके तहत हैती के 80 फीसदी नागरिकों को आर्थिक तौर पर मज़बूत किया जा सके और वैकल्पिक रोज़गार के साधन मुहैया कराए जा सकें. इस कार्यक्रम के तहत हैती में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित किया जाना है.

भूकंप के बाद राहत का काम शुरू हो चुका है और हैती अपने ज़ख्मों से उबरने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में भारत को उसके ज़ख्म भरने में योगदान करना चाहिए. हैती एक ऐसा देश है, जिसके साहस और स्वतंत्रता का अनूठा इतिहास रहा है. 1804 में यह पहला अश्वेत मुल्क बना. यहां गुलामों की आबादी अधिक है और इन्होंने बग़ैर किसी बाहरी मदद के फ्रेंच उपनिवेश से आज़ादी हासिल की. उस समय यह द्वीप इस धरती का सबसे धनी मुल्क था. आज यह बाहरी हस्तक्षेप और आंतरिक अस्थिरता की वजह से नाज़ुक हालत में है. हालांकि समय-समय पर हैती में भोजन को लेकर दंगे की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय सुर्ख़ियों में बनती रही हैं. हैती खाद्य आत्मनिर्भरता की सुरक्षा करने में असफल रहा. और, इससे यह क़र्ज़ में डूब गया. आज यह विदेशी सहायता पर निर्भर है. अभी तक इसकी हालत दयनीय बनी हुई है. हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि इस मुल्क की संप्रभुता ही ख़तरे में नज़र आ रही है. दक्षिण के मुल्कों के लिए हैती एक सीख है.

यहां आने पर हमारी पहली नज़र हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस पर पड़ती है, जो एक युद्ध क्षेत्र बनी हुई थी. शहर के बीचोबीच गाड़ी चलाना अचंभित करता है. यहां इतनी ग़रीबी है कि पहली बार में सारा किस्सा बयां नहीं किया जा सकता है. इसलिए बाद में हमने राजधानी के कई स्थानों का मुआयना किया. उन स्थानों को भी देखा, जहां पोर्ट ओ प्रिंस का संभ्रांत तबका रहता है. यहां होटल मोंटाना और कई दूसरे रेस्टोरेंट हैं, जहां खाने और रहने के बढ़िया प्रबंध हैं. ग़रीब और अमीर के बीच की यह असमानता विरोधाभास पैदा करती है. शहरों के बीच आपको लाखों बेरोज़गार युवक फुटपाथ पर बैठे और उदासी में टकटकी लगाए मिल जाएंगे. पोर्ट ओ प्रिंस की सबसे आश्चर्यजनक बात इसकी अर्थ व्यवस्था है. सरकारी कर्मचारी और थोड़े संपन्न लोग ही यहां चीज़ों को ख़रीदते हैं. बाक़ी दूसरे लोग जो इन्हें पाने की तमन्ना रखते हैं, वे या तो जुआ या फिर लॉटरी का सहारा लेते हैं. नौजवान लड़कियां इसके लिए खुलेआम वेश्यावृत्ति करती हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जो सामान सरकार द्वारा आयात होकर यहां पहुंचता है, उससे अभिजात्य वर्ग का ही ख़ज़ाना भरता है.

हैती अमेरिका से मक्का, चावल, बीन, तेल, चीनी और आटे का आयात करता है. पोर्ट ओ प्रिंस में सिर्फ़ एक ही स्थानीय उत्पाद देखने को मिलता है, वह आम है. यह एक मौसमी फल है और बहुतायत में मिलता है. हैती आम और कॉफी का निर्यात करता है. हैती की मौजूदा समस्या उसके इतिहास के गर्त में छिपी है. हालांकि यह दुनिया का पहला अश्वेत मुल्क है, फिर भी आज़ादी के बाद का इसका इतिहास बताता है कि हैती अपने चुनौती और आज़ादी पसंद स्वभाव की क़ीमत चुका रहा है. ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक़, 1825 में हैती ने फ्रांस को 150 मिलियन डॉलर का भुगतान किया, वह भी सोने की शक्ल में. उसके बाद से विदेशियों को हर्ज़ाने के भुगतान का यह सिलसिला कभी नहीं रुका. 1991 में हैती की पहली चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ने फ्रांस से 22 बिलियन डॉलर की रक़म वापस मांगी, लेकिन तब तक सरकार का तख्तापलट हो गया और एक ही झटके में वह मांग भी निरस्त हो गई. हैती के लोग कहते हैं कि तभी से यह एक ग़रीब मुल्क बनता जा रहा है. पश्चिमी मुल्कों ने आर्थिक सुधारों के नाम पर इसके पांव जकड़ दिए हैं. हैती को मज़बूर किया गया कि वह सामाजिक क्षेत्रों मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि आदि पर ख़र्चे में कटौती करे. सैनिक शासन और तानाशाही के बाद हैती में पहली लोकतांत्रिक सरकार 1991 में बनी. राष्ट्रपति जीन बेरट्रां अरिस्टीड के दो कार्यकाल तख्तापलट की कई वारदातों से भरे थे. उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति आए, सभी अपने दुश्मनों से साठगांठ कर सत्ता में बने रहे. वह भी संयुक्त राष्ट्र के 9 हजार शांति सैनिकों की मौजूदगी में.

हैती के लिए सुधार का मतलब है अमेरिकी व्यापार एवं निवेश के लिए दरवाज़े खोलना. इसे अमेरिकी लोगों के लिए अपने बाज़ार खोलने पर मजबूर किया गया. आज हैती इस गोलार्द्ध पर सबसे अधिक मुक्त व्यापारिक केंद्र है. उदाहरण के तौर पर अमेरिका इसका सबसे बड़ा सहयोगी है. अमेरिकी हितों को बढ़ावा देने और सुरक्षा के लिए हैती में ख़ूब सारा पैसा निवेश किया जा रहा है. लेकिन हैती के लोगों द्वारा विरोध किए जाने के कारण अमेरिका ने दंडस्वरूप दीर्घकालीन निवेश नहीं किया है. विकासशील मुल्कों के लिए हैती यह बताता है कि जो देश घरेलू खाद्य आत्मनिर्भरता के मामले में असफल होते हैं, उनका अंजाम यही होता है. यह आर्थिक नीतियों की असफलता की ओर इशारा करता है. इस तरह की नीतियां दूसरों पर निर्भरता पैदा करती है, विदेशी क़र्ज़ को बढ़ावा देती है और राष्ट्रीय विकास एवं आत्मनिर्भरता को कमज़ोर करती है. यह एक नए तरह के उपनिवेशवाद को बढ़ावा देती हैं, जिससे किसी मुल्क की दासता हमेशा के लिए सुनिश्चित हो जाए.

अमेरिका और पश्चिमी देशों के आर्थिक आदेशों को नकारने के लिए दक्षिण देशों में एकता विकसित हो रही है. इसी एकता के चलते क्यूबा, वेनेजुएला और हैती एक ऐसे समूह में परिवर्तित हो रहे हैं, जो पश्चिमी नीतियों का विरोध कर रहा है. यह समूह खेती की ज़मीन को बायो फ्यूल के लिए प्रयोग होने का विरोध कर रहा है. जब इस विरोध के चलते अमेरिका ने हैती को ईंधन दिए जाने पर रोक लगा दी तो उसके जवाब में पड़ोसी देश वेनेजुएला ने हैती को अगले सौ सालों तक ईंधन मुहैया कराने का समझौता कर लिया. आज हैती इस असमान युद्ध की अगुवाई करने की स्थिति में नहीं है. अपनी विषम आंतरिक परिस्थितियों, किडनैपिंग, राजनेताओं की निजी सेनाओं के बीच मारकाट, हर वक्त तख्तापलट का खतरा और आम आदमी के जीवनयापन के लिए जद्दोज़हद के चलते हैती हमेशा कगार पर खड़ा है. हैती उस विषम परिस्थिति को दर्शाता है कि किस तरह कोई विकासशील देश अपनी संप्रभुता को महज़ इसलिए खो देता है कि उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें, क्योंकि उसके स्थानीय खाद्य पदार्थ भूमंडलीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं.

(लेखिका मुंबई स्थित पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट हैं)

feedback@chauthiduniya.com

सभी फोटो-रूपा चिनाय

पोर्ट ओ प्रिंस के एक स्लम से लिया गया दृश्य.

जैकमेल का एक अस्पताल (ग्रामीण हैती में न दवा है और न ही डॉक्टर)

वहां खड़े सभी लोग उत्सुकता से इस पुकार का रहस्य जानने के लिए व्यग्र हो गए. तभी संन्यासी ने अपनी आंखें खोली और सबको साईराम कहा. मुझसे रहा न गया और मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आपकी इस पुकार का क्या रहस्य है?

दिल्ली, 8 फरवरी–14 फरवरी 2010
चौथी दुनिया

साईनाम परम हितकारी- ऊषा मंगेशकर

विकास कपूर

स्व. दीनानाथ मंगेशकर की चमत्कारी संतानों में सबसे छोटी ऊषा मंगेशकर को अपनी बड़ी बहनों की तरह शास्त्रीय संगीतकार पिता का मार्गदर्शन बहुत अधिक नहीं मिल पाया. जिस समय दीनानाथ जी का स्वर्गवास हुआ उस समय ऊषाजी बहुत छोटी थीं. अपनी बड़ी बहन लता ताई के साथ मुंबई आने के बाद ऊषा जी ने शास्त्रीय संगीत के उस्ताद अमानत अली ख़ान और उस्ताद अमन अली ख़ान की शार्गिदी में संगीत की बारीक़ियों को समझा. प्रारंभ में भारतीय शास्त्रीय संगीत से प्रभावित ऊषा जी की गायकी पर लता ताई की स्पष्ट छाप थी. लेकिन नियमित अभ्यास से ऊषाजी ने अपनी एक विशिष्ट और अलग शैली विकसित की. सन् 1953 में प्रख्यात संगीतकार सी. रामचंद्रन की फ़िल्म *सुबह का तारा* के लिए गाए ऊषाजी के गीत–*भाभी आई* ने उन्हें पहचान दी और फ़िल्म *इंकार* के गीत *मुंगड़ा–मुंगड़ा*, फ़िल्म *तराना* के गीत *सुल्ताना– सुल्ताना* के बाद सन् 1975 में आई फ़िल्म *जय संतोषी मां* के गीतों ने ऊषाजी को बुलंदियों के शिखर तक पहुंचा दिया. पिछले दिनों मुंबई के सुर–संगम स्टूडियो में विकास कपूर ने ऊषा जी से उनकी साईभक्ति पर बात–चीत की, जिसके कुछ अंश यहां प्रस्तुत हैं.

ॐ साई राम ऊषा ताई.

ॐ साई राम, जय साईराम, बाबा का प्रचार–प्रसार करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सच में आज हमारे देश और समाज को साईबाबा की शिक्षा और मार्गदर्शन की ज़रूरत है.

इस ज़रूरत को आप किस प्रकार से देखती हैं?

भारत एक विशाल देश है जहां अलग–अलग रहन–सहन है, अलग–अलग भाषाएं बोली जाती हैं, पर आज केवल अपने स्वार्थ के लिए लोग अपनी ढपली, अपना राग गा रहे हैं. यदि हम समाज को समझा पाएं कि तुम में और हममें कोई अंतर नहीं है, हम सबका मालिक एक है, जैसा कि स्वयं साईबाबा ने कहा था, तो हमारा देश कितना सुंदर, कितना प्यारा हो जाएगा. सब प्रेम से मिल–जुलकर रहेंगे.

महाराष्ट्र के अनजान से गांव शिरडी में अवतरित साईबाबा आज सारे भारत के अराध्यदेव बन गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?

अन्य बहुत सारे चमत्कारों की तरह यह भी देवा का एक चमत्कार है, फ़रियाद लेकर उनके दर पर जो भी जाते हैं, उनकी फ़रियाद देवा (साईबाबा) ज़रूर सुनते हैं. वे उन्हें अपनी कृपा का पात्र बनाते हैं, जिससे लोगों की आस्था, भक्ति और विश्वास बढ़ता है.

आप अपने जीवन में साईबाबा की कृपा को किस प्रकार देखती हैं?

मेरे जीवन का हर पल साईबाबा की परम कृपा से भरा है. विकासजी! साईनाम परम हितकारी, परम मंगलकारी और परम शुभ है. जो सच्चे मन से एकबार साईबाबा को पुकारता है, देवा उसकी मदद ज़रूर करते हैं. ॐ साईराम.

अगले अंक में
किशोरी शहाणे के साई अनुभव

पार्श्व गायिका ऊषा मंगेशकर

भक्ति की शक्ति

नई दिल्ली के आश्विन मलिक को हर सुबह अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैडमिंटन खेलना बहुत प्रिय था. सन् 1994 की एक सुबह जब वे दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रहे थे तभी उनके दोस्त परमिंदर का रैकेट आश्विन की आंख में लगा और आंख से ख़ून बहने लगा. दोस्त उन्हें पास के सर्जिसेंटर नर्सिंग होम लेकर भागे. नर्सिंग होम के आई स्पेशिलिस्ट डा. सूद ने काफ़ी कोशिश की पर आश्विन की आंख में कोई फ़ायदा नहीं हुआ. पांच दिन तक ट्रीटमेंट देने के बाद डा. सूद ने आंख के ऑपरेशन और एक आंख हमेशा के लिए हटा देने का फ़ैसला किया. आश्विन और उसकी पत्नी को एकमात्र साई पर भरोसा था. ऑपरेशन से एक रात पहले साईबाबा ने आश्विन को स्वप्न देकर कहा कोई तेरी आंख पर कैंची छुआ कर तो देखे और बाबा ने उसकी आंख पर अपना सटका छुआ दिया. सुबह जब आश्विन को ऑपरेशन थियेटर लाया गया तो उसकी पट्टी बंधी आंख में ज़ोर की खुजली हुई और पट्टी उतारने पर उन्हें सब–कुछ दिखाई दे रहा था, आंख की सूजन भी न जाने कहां ग़ायब हो गई थी. साईबाबा के इस चमत्कार के सामने नतमस्तक आश्विन और उसके परिवार के साथ डा. सूद ने भी साईबाबा की आंखों में यह सोचकर गुलाबजल डाला कि आश्विन का रोग बाबा ने ले लिया. गुलाबजल से उनकी आंखों को शीतलता मिलेगी. धन्य है साईबाबा जो केवल अपने भक्तों की ज़िक्र करते हैं.

साई सार्वभौम हैं

श्री साई सच्चरित्र के तीसरे अध्याय में रोहिला का प्रसंग बहुत ही प्रेरक है. उसी प्रसंग के अंत में दिया गया बाबा का अमृतोपदेश तो बहुत ही ध्यान देने और मनन करने योग्य है. एकदिन दोपहर आरती के बाद जब भक्तगण जाने लगे तो साईबाबा ने उन्हे रोककर कहा– तुम चाहे जहां कहीं भी रहो, तुम्हारी चाहे जो इच्छा हो, वह करो. लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो, वह सब मुझे ज्ञात है. मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु हूं और घट–घट में व्याप्त हूं. मेरे ही उदर में समस्त जड़–चेतन प्राणी समाए हुए हैं. मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रणकर्ता और संचालक हूं. मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहारकर्ता हूं. मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता. मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला, माया के पाश में फंस जाता है. समस्त जंतु, चींटियां तथा दृश्यमान, परिवर्त्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं.

feedback@chauthiduniya.com

ज्ञानोदय

सच्ची श्रद्धा और सबुरी ही सफलता का एकमात्र द्वार है. हृदय की गांठों का खुल जाना ही ज्ञान है और ज्ञान की प्राप्ति होने पर ही मुक्ति होती है.

–महोपनिषद

इस बात पर चिंतित न हो कि ईश्वर तुम्हारे पक्ष में है अथवा नहीं चिंतित इस बात पर हो कि तुम ईश्वर के पक्ष में हो कि नहीं.

–अब्राहम लिंकन

सत्य विचलित, विलंबित और व्याकुल हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता.

–स्व. मालती कपूर

हमारी भक्ति

साईबाबा के जीवन और आपकी अपनी भक्ति से संबंधित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साईभक्त के विचार उनके नाम सहित प्रकाशित किए जाएंगे.

पिछले सप्ताह का विषयः

साई अपने जीवन चरित्र से हम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते थे?

आपके जवाबः

1.

साईबाबा अपने जीवन चरित्र से हमें यही सिखाना चाहते थे कि जीवन में श्रद्धा की भावना रखने से कठिन से कठिन काम भी देवकृपा से आसान हो जाते हैं और बाबा द्वारा दी गयी सब्र (सबुरी) की शिक्षा हमसे कहती है कि हर रात के बाद सुबह ज़रुर आती है.

(कर्ण मेहरोत्रा)

2.

साईबाबा अपने भक्तों को ही नहीं सारे संसार को मिल-जुल कर प्रेम से रहने की शिक्षा देना चाहते थे. सबका मालिक एक है, कहकर उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच की दूरी को ख़त्म करने की कोशिश की थी.

(राजीव भनोत)

अगले सप्ताह का विषयः
क्या साईबाबा आडंबरों के विरोधी थे?

आप अपने विचार sai4world@gmail.com पर अपने नाम और पते के साथ मेल करें अथवा *शिरडी साईबाबा फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर–17517, मोतीलाल नगर नंबर–1, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई–58* के पते पर डाक द्वारा भेजें.

एक लगाओ तेईस पाओ

असीम खेत्रपाल

कुछ दिन पहले की बात है. मैं साईसंध्या कार्यक्रम के लिए मुंबई गया हुआ था. उस सुबह मेरी आंखें कुछ जल्दी खुल गई. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं. बस यूं ही मैं होटल से बाहर निकलकर पास के एक सार्वजनिक उद्यान की ओर जा रहा था. तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी– आओ...आओ, एक लगाओ तेईस पाओ. मुझे बड़ा अजीब लगा कि इसका आख़िर मतलब क्या हुआ. उस आवाज़ की ओर मैं आकर्षित हुआ था. सोचा, जहां से आवाज़ आई है क्यों न वहीं चल कर देखा जाए कि आख़िर क्या माज़रा है. जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी नज़र साई की मूर्ति की ओर गई. मूर्ति के गले में लाल ताज़े पुष्पों की माला उन्हें सुशोभित कर रही थी. वहां एक अलौकिकता का अहसास हो रहा था. मैंने श्रद्धा से बाबा की मूर्ति के आगे सिर झुकाया. वहां मैंने देखा कि मूर्ति के पास ही एक प्रौढ़ संन्यासी बैठे हैं. आकर्षक व्यक्तित्व और स्वस्थ शरीर के कारण वह बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे. मन ही मन शायद वह साईनाम का जप कर रहे थे. उनके पास काफ़ी भीड़ एकत्रित थी, लेकिन जप में लीन देखकर कोई उन्हें कुछ कह नहीं रहा था. मैं भी शांत भाव से वहां पर खड़ा हो गया. इस बार उस प्रौढ़ संन्यासी ने आंखें बंद किए हुए ही पुकार लगाई– आओ...आओ, एक लगाओ तेईस पाओ. उनकी इस पुकार से मैं ही नहीं, वहां खड़े सभी लोग उत्सुकता से इस पुकार का रहस्य जानने के लिए व्यग्र हो गए. तभी संन्यासी ने अपनी आंखें खोली और सबको साईराम कहा. मुझसे रहा न गया और मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आपकी इस पुकार का क्या रहस्य है? वह खिलखिलाकर हंस पड़े. फिर शांत स्वर में उन्होंने कहा– बेटा! साई अपने बच्चों का स्वस्थ जीवन चाहते हैं. वह नहीं चाहते कि उनके भक्तों की काया रोगी रहे. स्वयं साई अपने जीवन में व्यायाम को बहुत महत्व देते थे. कई बार तो शरीर को चुस्त–दुरुस्त रखने के लिए वे कुश्ती तक लड़ लिया करते थे. मैंने साई जीवन से इसी बात को सीखा है कि दिन के चौबीस घंटों में से अगर एक घंटा अपने ऊपर ख़र्च कर लो. अपने स्वास्थ्य और व्यायाम के लिए थोड़ा समय लगा दो तो बाक़ी तेईस घंटे तुम इतने प्रसन्नचित्त और स्वस्थ रहोगे कि तुम्हारे हर काम में निखार आएगा.

उस प्रौढ़ संन्यासी की ही बात आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि दिन में एक घंटा अपने ऊपर लगाओ. शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा. मन स्वस्थ होगा तो विचार स्वस्थ होंगे और विचार स्वस्थ होंगे तो सफलता तुम्हारे क़दम चूमेगी. ॐ साईराम

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि वे अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना (कार्यक्रम, प्रबंधक, तिथि, स्थान और समय सहित) विकास कपूर को sai4world@gmail.com पर मेल कर सकते हैं.

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!
Giriraj Sai Hills

Giriraj Sai Hills offers an innovative selection of Fully Furnished and Spacious Studio, One Bedroom, Two bedroom Apartments & Fully Furnished Villa
Starting From Rs. 9.65 lakhs*
AUM
Aum Infrastructure & Developers
Delhi Office : 156, Sant Nagar, Ground Floor, East of Kailash, New Delhi-110065
Phone No: +91 11 46594226 / 46594227

इस बार कुंभ में धूने सजाने की शुरुआत हुई है पंचदशनाम जूना अखाड़े से. जूना अखाड़े के पास संख्या बल अधिक है, क्योंकि अन्य छह संन्यासी अखाड़ों की तुलना में यह अखाड़ा संन्यास दीक्षा देने में अधिक उदार है.

प्रकृति के प्रति ख़तरनाक संवेदनहीनता

अनंत विजय

कुछ दिनों पहले की बात है, दिल्ली और आसपास के इलाक़े में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी. रात में कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. देर रात तक़रीबन एक बजे नोएडा स्थित अपने दफ़्तर से घर के लिए निकला तो घने कोहरे में रास्ता भी नहीं दिख रहा था. गाड़ी की सभी लाइटें जलाकर किसी तरह रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था. अचानक सड़क के किनारे पेड़ पर एक आदमी टंगा दिखाई दिया. हवा ख़राब हो गई, लगा कि कोई लाश लटक रही है. गाड़ी रोककर पास पहुंचा तो अचानक वह आदमी पेड़ से कूदकर सामने खड़ा हो गया. भूत-प्रेत में यक़ीन नहीं है, लेकिन माहौल ऐसा था कि लगा कहीं कोई भूत तो नहीं. कुछ सोच पाता, इसके पहले ही वह आदमी बोल पड़ा, सर, ठंड बहुत है, हाड़ कांप रहा है. इसलिए सोचा कि पेड़ से कोई टहनी तोड़कर आग तापकर ठंड से ख़ुद को बचा लूंगा. जब टहनी नीचे से नहीं टूटी तो पेड़ पर लटक गया. वह बोले जा रहा था और मैं सामान्य हो रहा था. ख़ैर उसकी बातें सुनीं, फिर घर की ओर चल पड़ा. गाड़ी ड्राइव करते हुए एक पुराना वाकया याद आ गया. लगभग दस साल पहले किसी काम से सागर जाना पड़ा था. कवि-आलोचक श्याम कश्यप उस वक़्त सागर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष थे. उनसे मिलने विश्वविद्यालय कैंपस जा पहुंचा. दफ़्तर में उनसे मिलकर तय हुआ कि वह हमारे साथ सागर शहर चलेंगे और वहां के स्थानीय साहित्यकारों से मिलेंगे. श्याम कश्यप जी फ्रेश होने के लिए अपने घर चले गए और मैं कैंपस में घूमने लगा. घूमते-घूमते एक मकान के सामने पहुंचा और वहां मौजूद एक माली से बातचीत करने लगा. उसने बताया कि जिस मकान के सामने हम लोग खड़े थे, उसमें किसी जमाने में प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि रहते थे. हिंदी के उस कवि के बारे में और जानने की जिज्ञासा में बातचीत को मैंने आगे बढ़ाया. उसे नहीं मालूम था कि हम लोग जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, वह हिंदी साहित्य की कितनी बड़ी शख्सियत है. बातों-बातों में उसने बताया कि कवि जी पेड़-पौधों को लेकर बड़े निर्दयी थे. ठंड के मौसम में अपने घर के अहाते में लगे पेड़ों को कटवा कर सुखा लेते थे और शाम होते ही अलाव जलाकर तापते थे. उस समय सुना और बात आई-गई हो गई. लेकिन, जब नोएडा में उक्त घटना घटी तो एक बार फिर से बातें जेहन में ताजा हो गईं. एक तरफ़ बिल्कुल गंवार चौकीदार, जो ठंड से बचने के लिए पेड़ से लटका था तो दूसरी तरफ़ हिंदी का शीर्ष कवि, जो ठंड से बचने के लिए पेड़ों की बलि ले रहा था.

सवाल इस बात का है कि हम और हमारा समाज पेड़-पौधों को लेकर कितने संवेदनहीन हैं. दुनिया के तमाम देश ग्लोबल वॉर्मिंग की समस्या से जूझ रहे हैं. हाल ही में कोपेनहेगन में तक़रीबन दो सौ देशों के प्रतिनिधियों ने हफ़्ते भर माथापच्ची की, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे. जब ग्लोबल वॉर्मिंग की चर्चा गर्म थी, उसी दौरान हमने यह भी देखा कि देश के कई इलाक़ों में दिसंबर में ही आम के पेड़ बौर से लद गए. फूलों के रंग बदल गए थे. कश्मीर में बिना बर्फबारी के ही सेब के पेड़ पर फूल खिल आए. वैज्ञानिकों ने हमें यह बताया था कि राजस्थान के रेगिस्तान का दायरा बढ़ रहा है. हिमालय के ग्लेशियर पिघलने की ख़बरें भी आईं. यह सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की वजह से घटित हो रहा था. इन सबसे बचने के लिए सरकारी स्तर पर भी कई योजनाओं का ऐलान हुआ, करोड़ों ख़र्च करके पर्यावरण को बचाने की कोशिशें तेज़ हो गईं. लेकिन, इस बात की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि भारत में इस समस्या की जड़ में क्या है. विश्व के विकसित देशों की तुलना में भारत में अब भी कार्बन उत्सर्जन बेहद कम है. दो हज़ार पांच में हुए फॉरेस्ट सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक़, हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग चौबीस फ़ीसदी हिस्सा जंगलों या पेड़-पौधों से ढका है. दरअसल, इस समस्या की जड़ में अशिक्षा है, लोगों के बीच पेड़-पौधों को लेकर उदासीनता है. देश की एक बड़ी आबादी को लगता है कि ये तो जलाने के लिए ही हैं. ऐसे वक़्त में हम सब पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यह है कि हम पेड़-पौधों को लेकर संवेदनशील बनें और देशवासियों को इनके नष्ट होने के ख़तरों से आगाह करें. इससे हमारा तो भला होगा ही, आने वाली पीढ़ी भी हमें गुनहगार के तौर पर याद नहीं करेगी.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश: मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

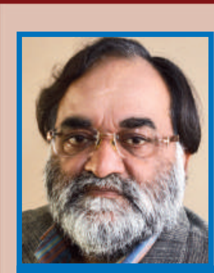

प्रदीप सौरभ

दंगे गुजरात की क़िस्मत बन गए थे. जगह जगह राहत शिविरों की फ़सल उग आई थी. राहत शिविरों में भी लोग महफ़ूज़ नहीं थे. दंगाई राहत शिविरों को भी निशाना बना रहे थे. जूहापुरा और गुप्ता नगर कालोनी के बीच बार्डर जैसा माहौल था. जूहापुरा अहमदाबाद के बड़े मुस्लिम बहुत इलाक़ों में था. जूहापुरा पाकिस्तान बन गया था और उसके सामने की गुप्ता कालोनी हिंदुस्तान. गुप्ता कालोनी में लोगों ने घरों में बड़ी संख्या में पत्थर जमा कर लिए थे. लोग पाषाण युग की तरफ़ लौटते दिख रहे थे. रात को एक साथ घरों में बर्तन बजने लगते थे. बर्तन का बजना संकेत होता था कि पत्थरबाजी शुरू करो. हमलावर आ गए हैं. बर्तन बजा बजा कर गुप्ता कालोनी के लोगों ने बर्तनों की शक्ल बदल दी थी.

आनंद के घर काम करने वाली कमला बेन भी गुप्ता कालोनी में रहती थी. एक दिन न आने पर आनंद ने कमला बेन से पूछा, कल क्यों नहीं आई?

बार्डर पर हमारी बारी थी ड्यूटी की, कमला बेन ने जवाब दिया. मतलब? आनंद भारती ने हैरान होते हुए पूछा.

जूहापुरा बॉर्डर है. मुसलमान हमारे ऊपर हमला न कर दें, इसलिए सबकी बारी बारी से रात को ड्यूटी लगती है. कमला ने इस अंदाज़ से जवाब दिया जैसे सचमुच देश की सीमा सुरक्षा की ड्यूटी पर तैनात हो.

कभी हमला किया क्या? आनंद भारती की जिज्ञासा बढ़ गई थी. अभी तक तो नहीं किया. धमाल चल रहा है. पता नहीं कब हमला बोल दें. कह कर कमला बेन काम में जुट गई.

कमला बेन की बात सुनने के बाद अचानक आनंद भारती को दिल्ली के अपने मित्र के.के. कोहली का विभाजन के समय का वह किस्सा याद आ गया...देश विभाजन के पहले कोहली का परिवार रावलपिंडी के गोलड़ा शरीफ गांव में रहता था. विभाजन की मांग को लेकर दंगे फसाद शुरू हो चुके थे. कोहली के घर के सामने वाली दीवार पर लिखा था-हाथ में बीड़ी, मुंह में पान, नहीं बनेगा पाकिस्तान. उस वक़्त उनकी उम्र सात साल की रही होगी. हॉफ पैंट पहनते थे. घर वाले दंगाइयों के डर से उनकी जेब में कुछ पैसे और ड्राइ फ्रूट भर देते थे, ताकि हमले के बाद परिवार बिखरे तो भूख मिटाई जा सके और पैसे से मदद हासिल की जाए. उस दौर में भी हिंदू पत्थर नहीं रखते थे. लेकिन गुजरात के बॉर्डर में पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए गए.

दंगों में मरने वालों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था.

साबरमती नदी के उजास हिस्से के मोटरा में संत आसाराम बापू का भी आश्रम है. वे वाणी के जादूगर संत हैं. लाखों की संख्या में उनके अनुयायी अहमदाबाद से लेकर देश के कोने कोने में हैं. दंगों को देख कर आसाराम बापू का दिल दहला. उन्होंने शांति मार्च निकालने का आह्वान किया. गुरु पूर्णिमा के दिन देश के हर हिस्से से अहमदाबाद की सड़कें भर जाती हैं. हर भक्त गुरु से आशीर्वाद लेना चाहता है. लेकिन शांति मार्च के मौक़े पर पांच सौ लोगों को इकट्ठा करना भी आसाराम बापू के लिए मुश्किल हो गया. आश्रम के लोगों को लेकर शांतिमार्च की रस्म अदायगी की गई. दंगों की आंच में भक्तों ने भी गुरु से किनारा कर लिया.

feedback@chauthiduniya.com

अब बन रहा है कुंभनगर में कुंभ का माहौल

डॉ.कमलकांत बुधकर

उत्तराखंड सरकार द्वारा घोषित 2010 के ग्यारह कुंभस्नानों में से चार स्नान जनवरी के अंत तक संपन्न हो चुके हैं. पर वास्तविकता यह है कि कुंभनगर में कुंभ की चहल-पहल अब जाकर शुरू हो सकी है. साधु-संन्यासियों के डेरे-तंबू अब कुंभनगर में पड़ने लगे हैं और गलियों-सड़कों पर भगवा चोला पहने जटाजूटधारी पहले की तुलना में अधिक दिखाई देने लगे हैं. विभिन्न अखाड़ों की छावनियों में धूने सजने लगे हैं और आसमान में यज्ञधूम दिखने लगा है.

इस बार कुंभ में धूने सजाने की शुरुआत हुई है पंचदशनाम जूना अखाड़े से. जूना अखाड़े के पास संख्या बल अधिक है, क्योंकि अन्य छह संन्यासी अखाड़ों की तुलना में यह अखाड़ा संन्यास दीक्षा देने में अधिक उदार है. इस अखाड़े में चारों वर्णों के लोगों को दीक्षित करने और अखाड़े में सम्मिलित करने की परंपरा है. इतना ही नहीं, संन्यासिनियों को भी इसी अखाड़े में अधिक प्रश्रय मिलता है. संख्या बल के चलते ही इन दिनों सभी तेरह अखाड़ों के संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद् में भी जूना अखाड़ा अपनी बात मनवाने और पद पाने में आगे रहता है. इसी अखाड़े के दिवंगत सचिव श्रीमहंत परमानंद सरस्वती की सक्रियता और उग्रता 1998 के हरिद्वार कुंभ से ही देश के अन्य कुंभ नगरों में भी मीडिया में और अन्यत्र भी सुपरिचित रही है. इस बार इसी जूना अखाड़े के श्रीमहंत हरिगिरि अखाड़ों के संगठन के महामंत्री हैं. वे भी दिवंगत परमानंद सरस्वती की परंपरा में अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराते हैं और शासन-प्रशासन पर अपनी पूरी पकड़ रखते हैं. पुराणचर्चित मायापुरी हरिद्वार की अधिष्ठात्री मायादेवी और श्री आनंद भैरव का मंदिर और सारा मंदिर परिसर जूना अखाड़े की परिसंपत्तियों में शुमार है. श्रीमहंत हरिगिरि के कार्यकाल में इस बार इस परिसर में अभूतपूर्व निर्माण कार्य हुए हैं. आधुनिक सुविधाओं से संपन्न आवासों का भव्य निर्माण कराया गया है. ऐसे ही निर्माण महानिर्वाणी अखाड़े के श्रीमहंत रवींद्रपुरी और बड़ा उदासीन अखाड़े के श्रीमहंत राजेंद्रदास की सक्रियता और कर्मठता के कारण पुरातन नगरी कनखल में भी संपन्न हुए हैं. अब इन नवनिर्माणों की छाया में साधुसमाज कुंभ की तैयारियां जोरशोर से कर रहा है, जिससे 2010 के कुंभ मेले के लिए अब माहौल बनना शुरू हो गया है.

चर्चा कुंभनगर की

फोटो : प्रभात पाण्डेय

कुंभ के अविभाज्य अंग के रूप में मेला आयोजन से जुड़े साधुसंतों के अखाड़ों के रमता पंचों का नगर में आगमन, अखाड़ों की धर्मध्वजाओं की स्थापना और फिर अखाड़ों की पेशवाइयां और अंतत: कुंभ के तीन शाही स्नान. इसी क्रम से संन्यासी अखाड़ों की कुंभस्नान परंपरा का निर्वाह होता है. पहला शाही स्नान जहां केवल सात संन्यासी अखाड़े करते हैं वहीं शेष दो शाही स्नान सभी अखाड़े अपने अपने क्रम से मुख्य स्नान-स्थल अमृतपावन हरकी पौड़ी पर करते हैं. कुंभ के मुख्य स्नान के बाद वैशाखी पूर्णिमा स्नान केवल बैरागी अखाड़ों द्वारा किए जाने की परंपरा है. ये तीनों बैरागी अखाड़े महाशिवरात्रि के प्रथम शाही स्नान के दिन वृंदावन में एकत्र होकर वहां कुंभ स्नान करते हैं.

इस क्रम में संन्यासियों के सात दशनामी अखाड़ों में से सर्वप्रथम पंचायती जूना अखाड़े के रमता पंचों ने हरिद्वार में आकर पांडेवाला में अपना डेरा जमाया. जूना अखाड़े द्वारा इससे पहले 108 फीट ऊंचे त्रिशूल की स्थापना भी मायादेवी मंदिर प्रांगण में की जा चुकी है.

इसके बाद आवाहन, महानिर्वाणी तथा अटल अखाड़ों के रमता पंचों ने हरिद्वार में डेरा जमाया. 26 जनवरी के दिन जूना, आवाहन और अग्नि अखाड़ों की बावन फीट लंबी धर्मध्वजाओं की स्थापना मायादेवी मंदिर के भीतरी और बाहरी परिसर में की गई. जबकि 27 जनवरी को महानिर्वाणी और अटल अखाड़ों की आकाश छूती धर्मध्वजाएं कनखल स्थित उनकी छावनियों में स्थापित की गईं. 28 जनवरी को पहले तपोनिधि श्री पंचायती श्रीनिरंजनी अखाड़ा तथा श्री आनंद अखाड़ों ने भी समारोह तथा पूजन-अर्चन के विधिविधान के अनुसार अपनी अपनी बावन फीट उंची धर्मध्वजाएं स्थापित कीं.

इन धर्मध्वजाओं की स्थापना के लिए विभिन्न स्थलों पर मंदिर-परिसरों में सुबह से ही धर्मध्वजाओं की स्थापनाओं की पूजा अर्चना आरंभ हो गई थी. बाद में तो सैकड़ों साधुओं और भक्तों तथा अन्य अखाड़ों के अभ्यागत साधुओं की साक्षी में मंगल अनुष्ठान संपन्न किए गए.

सर्वप्रथम मायादेवी मंदिर प्रांगण में मंदिर के ठीक सामने श्रीदत्तात्रय चरण पादुकाओं के साथ ही जूना अखाड़े ने दस फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें पूर्ण विधि-विधान और पूजा अर्चना के साथ बावन फीट के ध्वजदंड पर लहराती हुई धर्मध्वजा स्थापित कर दी गई. इस मौक़े पर चार मढ़ी, तेरह मढ़ी, चौदह मढ़ी तथा सोलह मढ़ी के संतों ने ध्वजदंड के चारों रस्से पकड़ कर पहले से लिटाई गई ध्वजा को आकाशोन्मुख खड़ा किया. ध्वजा के स्थापित होते ही सारा वातावरण हर हर महादेव और गुरु महाराज की जय की ध्वनि से गूंज गया. जूना अखाड़े की ध्वजा-स्थापना के बाद पंच आवाहन और अंत में पंच अग्नि अखाड़ों की धर्मध्वजाएं मंदिर परिसर में स्थापित कर दी गईं.

धर्मध्वजाओं की स्थापना के इस क्रम में महानिर्वाणी और अटल तथा निरंजनी और आनंद अखाड़ों ने भी हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष के बीच ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न किया. इन अवसरों पर कुंभ मेलाधिकारी आनंद बर्धन तथा मेला डीआईजी आलोक शर्मा भी अपने पूरे अमले के साथ उपस्थित रहे. 27 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की कुंभ परामर्शदात्री समिति द्वारा पूरी अखाड़ा परिषद् के सम्मान में कनखल के महानिर्वाणी अखाड़े में आयोजित मध्यान्ह भोज में तो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक भी शरीक रहे.

देश-विदेश के सैकड़ों मीडियाकर्मियों ने इन धार्मिक और ऐतिहासिक दृश्यों को अपने कलम और कैमरों में कैद किया. अनेक टीवी चैनल्स इस पूरे आयोजन को अपने दर्शकों को जीवंत दिखा रहे थे. अलबत्ता 27 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए साधुओं के भोज में मीडिया के साथ हुए दुर्व्यवहार के चलते पत्रकारों को मुख्यमंत्री और कुंभ प्रशासन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन और नारेबाज़ी तथा मुख्यमंत्री को क्षमायाचना भी करनी पड़ी.

ये पंक्तियां प्रकाशित होने तक सभी संन्यासी अखाड़ों की पेशवाइयां भी शहर में प्रवेश कर चुकी हैं. जब साधुओं की जमातें गाजे- बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ, ध्वज-निशान लिए चांदी सोने की अंबारियों और हौदों में अपने अपने आराध्य देवताओं, हाथी-घोड़ों और पालकियों में अपने आचार्यों और महामंडलेश्वरों के साथ कुंभनगर में आती हैं तो उन्हें पेशवाई कहते हैं. सातों संन्यासी अखाड़ों की ऐसी पेशवाइयों का नगर प्रवेश हो चुका है. जगह जगह साधु अलग अलग छावनियों में अपने धूने सजाने में जुट गए हैं. रंगबिरंगे झंडे-झंडियां लगाकर और टैंट-तंबुओं के नीचे बीच में धूना और मुख्य गद्दी के चारों ओर भक्तों के बैठने की व्यवस्था करके साधु-संन्यासी अपना ठीया मज़बूत करने में जुट गए हैं.

इधर कुंभ की सुरक्षा की भी तैयारियां जोरों पर हैं. पुलिस अधिकारी अपनी चुस्ती और फुर्ती कर स्वयं परीक्षा लेने के लिए बार बार अभ्यास ड्रिल का आयोजन करते हैं. झूठमूठ में कहीं कोई संदिग्ध वस्तु रखकर उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल को भिजवाते हैं और फिर देखते हैं कि पुलिस चुस्त दुरुस्त है या नहीं.

इसी बीच पुलिस को एक वास्तविक सफलता तब मिली जब उसने 25 जनवरी के दिन रुड़की में पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हिजबुल मुज़ाहिदीन के एक सदस्य को बीएसएम कॉलेज तिराहे पर पकड़ा. उसके पास से एक लिफाफ़ा बरामद हुआ, जिसे वह कूरियर करने जा रहा था. इस लिफाफ़े में भारतीय सेनाओं की विभिन्न छावनियों से संबंधित गोपनीय जानकारियों के काग़ज़ात तथा रुड़की छावनी का नक़्शा बरामद हुआ. उसके पास एक पॉकेट डायरी भी बरामद हुई जिसमें विभिन्न नंबरों के अलावा हरिद्वार के कुछ न्यायिक दंडाधिकारियों के नंबर भी प्राप्त हुए.

पकड़े गए इस व्यक्ति ने पहले अपना नाम असद अली, पुत्र बरकत अली निवासी 22 शाहपीर गेट, मेरठ बताया, पर बाद में अपना असली नाम- आबिद अली, पुत्र- बरकत अली निवासी- मोहल्ला हजरत बाबा हाजी शाह सलीम, ग्राम- हन्जरवाल, थाना ठोकर नियाज़बेग, डाकखाना मंसूरा, ज़िला लाहौर, पाकिस्तान स्वीकार किया. उसके अन्य नामों में असद अली उर्फ अबू बकर उर्फ अजीत सिंह भी है.

पुलिस ने आबिद के पास से एक लैपटाप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, दो मोबाईल फोन, असद के नाम से एक सिमकार्ड, गाजियाबाद आरपीओ से बना भारतीय पासपोर्ट, जाली ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आईसीआईसीआई एवं भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम कार्ड आदि बरामद हुए हैं. बताया गया है कि पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण प्राप्त आबिद उर्फ असद पिछले कई दिनों से मेरठ में रहकर जासूसी कर रहा था.

यानी कुल मिलाकर तैयारियां तीनों तरफ़ जारी हैं. मेला लगाने वाले भी तैयारी में हैं, मेले को सुरक्षा देने वाले भी चौकस हैं तो मेला उजाड़ने वाले भी पीछे नहीं हैं. लेकिन कुंभ के लिए कुंभ लगाने और सजाने वालों की प्रतिबद्धता ही उनका विश्वास है. गंगा मैया के प्रति भरोसा ही इस विश्वास की जड़ में है. मैया सब कुछ ठीक करेगी!

kk@budhkar.in

कंपनी ने भारत में एस-सीरीज़ वॉकमैन वीडियो एमपी-थ्री प्लेयर की रेंज में नए मॉडल एन डब्ल्यूजेड-एस543 बी वॉकमैन लांच किया है.

अक्षय कुमार बने ब्रांड एम्बेसडर

डॉलर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है. डॉलर तरह-तरह के इनरवियर बनाती है और देश के प्रमुख होजियरी ब्रांड्स में प्रमुख स्थान रखती है. पहले इसके लिए फ़िल्म स्टार सलमान ख़ान को लिए जाने की बात चल रही थी, लेकिन फ़िल्मों में अक्षय कुमार की सफलता और लोगों में लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी ने सलमान की जगह उन्हें ही अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है. डॉलर ब्रांड ने न केवल भारतीय बाज़ारों में, बल्कि खाड़ी देशों में भी अच्छी पैठ बना ली है. इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि भारतीय वस्त्र उत्पादकों की सर्वोच्च संस्था सीएमएआई ने डॉलर को पिछले तीन सालों से लगातार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ इनरवियर ब्रांड चुनती आ रही है.

डॉलर से अपने संबंध पर अक्षय कुमार का कहना है- निटेड इनरवियर सेगमेंट में मैं पहली बार डॉलर के विज्ञापन में नज़र आने वाला हूं. डॉलर से जुड़ कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह मेरे लिए परफेक्ट है. डॉलर भावी पीढ़ी का स्टाइल है और मैं नई पीढ़ी के लोगों का स्टाइल आईकन हूं. अक्षय कुमार को लेकर डॉलर के विज्ञापनों की शूटिंग विदेशी लोकेशन पर हुई है.

अक्षय कुमार से कंपनी के इस रिश्ते के बारे में डॉलर इंडस्ट्रीज़ के प्रबंध निदेशक श्री विनोद गुप्ता ने कहा कि कंपनी ने अक्षय को अगले दो सालों के लिए कंपनी का ब्रांड एंबेसेडर बनाया है. कंपनी का यह विश्वास है कि इस रिश्ते से ब्रांड डॉलर की लोगों में पहचान और बढ़ेगी.

डुअल सिमकार्ड का जलवा

मोबाइल फोन के बाज़ार में मोबाइल फोन कंपनी मोविल ने डुअल सिमकार्ड वाला सेलफोन मॉडल एमए-1 लांच किया है. शॉक प्रतिरोधी और वाटर रेसिसटेंट क्षमता इसकी ख़ासियत है. सिर्फ़ 17 मिलीमीटर चौड़ाई वाले इस फोन में डुअल सिमकार्ड ट्राईबैंड यानी दो जीएसएम सिमकार्ड लगाने की सुविधा दी गई है. दो सिमकार्ड का विकल्प आपको अपने बिजनेस समूह के दोस्तों और परिवार व निजी दोस्तों से अलग-अलग नंबर पर बिना किसी परेशानी के जुड़े रहने का विकल्प देती है. इसका 2.1 इंच स्क्रीन का 26-के कलर कैपेबल क्यूवीजीए डिसप्ले आंखों के लिए सुकूनदायक है. इसकी इंटरनल मेमोरी के साथ माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है. इस फोन की स्टोरेज क्षमता मेमोरी कार्ड के ज़रिए दो जीबी तक बढ़ाई जा सकती है. दो आकर्षक रंगों, ऑरेंज और ग्रीन में उपलब्ध मोविल एमए-1 सेलफोन में आसान यूजर इंटरफेस हैं. ख़ूबसूरत लम्हों को सहेजने के लिए इस फोन में 1.3 मेगापिक्सल फिक्स्ड-फोकस डिजिटल कैमरा दिया गया है जिसमें वीडियो रिकार्डिंग की भी सुविधा है. वीडियो को अपने हिसाब से बनाने के लिए इसमें इनबिल्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सुविधा दी गई है. बेहतरीन और शुद्ध आवाज़ के लिए मोविल के इस मॉडल में इंटीग्रेटेड डुअल स्पीकर दिए गए हैं. इसमें मौजूद जीपीआरएस फीचर के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है. डाटा ट्रांसफर और दूसरे कामों के लिए ब्लूटुथ भी इस फोन में है. इसके अलावा एज, एफएम रेडियो, डॉक्यूमेंट व्यूअर जैसे ख़ास फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं. इस फोन के साथ 17 दिनों के स्टैंडबाई टाईम के साथ सात घंटे की एक्सपेंडेबल टॉकटाइम देने वाली 1000 एमएएच रीचार्जेबल बैट्री दी गई है. एक साल की वारंटी के साथ मोविल एमए-मोबाइल फोन भारतीय बाज़ार में 4200 रुपये में उपलब्ध है.

नई तकनीक से युक्त वायरलेस रूटर

रूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को जोड़ने का काम करता है. यह ख़ासतौर से इंटरनेट को किसी तार या रेडियो सिग्नल से जोड़ने का काम करता है. नेटगियर कंपनी ने भारत में अब तक का सबसे सस्ता वायरलेस रूटर लांच किया है. डब्ल्यूएनआर1000 रेजमैक्स 150 सीरीज वायरलेस रूटर में इनबिल्ट फायरवॉल प्रोटेक्शन, एनएटी सपोर्ट, स्टैटफुल पैकेट इंस्पीरेशन, डॉस अटैक प्रीवेंशन, यूआरएल फिल्टरिंग, वाई-फाई प्रोटेक्टेड सेटअप टेक्नोलॉजी है. इसके अलावा इनबिल्ट 4 पोर्ट फुल ड्यूप्लेक्स 10/100/1000 गीगाबाइट एथरनेट स्विच मौजूद है, जिससे इस रूटर को इस्तेमाल करने में आसानी होती है. कंपनी यह दावा करती है कि डब्ल्यूएनआर1000 वायरलेस रूटर उसके द्वारा अबतक लांच किए गए सभी रूटर में सबसे बेहतर वायरलेस कवरेज़ वाला मॉडल है. यह बाक़ी पुराने वायरलेस जी रूटर्स से ज़्यादा बढ़िया परफॉरमेंस, लगातार वेब सर्फिंग, ई-मेल, बढ़िया संगीत, ऑनलाइन गेम्स खेलने की सुविधा और इंटरनेट फोन कॉल करने का विकल्प देता है. कंपनी ने इसे ख़ासतौर से घरों, छोटे दफ़्तरों और होम ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए बनाया है. इसमें स्मार्ट विज़र्ड फीचर और पुख्ता सुरक्षा के लिहाज़ से फायरवाल की दोहरी परत दी गई है. इससे उर्जा की भी बचत होती है. 339 ग्राम का यह रूटर कॉम्पेक्ट और एंटेना फ्री है. इसके ज़रिए 300 एमबीपीएस की स्पीड से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है. इसका डुअल बैंड सिस्टम 2.4 गीगाहर्ट्ज और पांच गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम घर के दूसरे यंत्रों की फ्रीक्वेंसी से प्रभावित हुए बिना आसानी से काम करता है. बेहतर कनेक्टिविटी परफॉरमेंस के लिए इसमें डीएसएसएस और ओएफडीएम की मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. दो साल की वारंटी के साथ इस रूटर की क़ीमत भारतीय बाज़ार में 2,950 रुपये रखी गई है.

संगीत प्रेमियों को तोहफ़ा

संगीत के दीवानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सोनी नियमित अंतराल पर कोई न कोई नई म्यूजिक प्लेइंग डिवाइस लांच करती ही रहती है. पिछले दिनों कंपनी ने भारत में एस-सीरीज वॉकमैन वीडियो एमपी-थ्री प्लेयर की रेंज में नए मॉडल एन डब्ल्यूजेड-एस543 बी वॉकमैन लांच किया है. युवाओं की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए लांच किए गए इस म्यूजिक डिवाइस में वीडियो देखने का भी विकल्प मौजूद है. इसके 2.4 इंच चौड़े स्क्रीन पर 240 गुणा 320 पिक्सल के रीजोल्यूशन की वीडियो क्वालिटी के साथ वाइड क्यूवीजीए एलसीडी डिस्प्ले सुविधा है. 68 ग्राम वजन के इस वॉकमैन में लगभग 1000 गाने सेव करने लायक 4 जीबी मेमोरी है. क्लियर बेस और स्पष्ट व साफ़ आवाज़ वाली स्टीरियो ऑडियो तकनीक के साथ इसमें 30 स्टेशनों

वाले इंटीग्रेटेड लाइव रिकार्डिंग एफएम रेडियो की सुविधा दी गई है. गाना सुनते हुए नींद के आगोश में समाने वाले संगीत प्रेमियों को सही वक़्त पर जगाने के लिए इसमें अलार्म की सुविधा भी दी गई है. मनपसंद आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए इसमें वॉयस रिकॉर्डिंग का विकल्प भी मौजूद है. आई-ट्यूंस, साइबरशॉट और कंप्यूटर से डाटा ट्रांसफर करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग जैसी आसान प्रक्रिया इसे यूजर्सफ्रेंडली बनाती है. इसकी इनबिल्ट ली आयन रीचार्जेबल बैट्री 42 घंटे की ऑडियो प्लेबैक और 6.5 घंटे की विडियो प्लेबैक का पावर देती है. कंपनी प्रोडक्ट के साथ कैरी केस और चार्जिंग डेस्क स्टैंड भी दे रही है. ब्लैक कलर में उपलब्ध इस स्टाइलिश वॉकमैन की क़ीमत 6990 रुपये है.

माइक्रो एसडी कार्ड का नया अवतार

मल्टीमीडिया और एक्सपैंडेबल मेमोरी वाले फोन के शौक़ीनों को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने नया तोहफ़ा देने का मन बनाया है. कंपनी ने ऐसे मोबाइल फोन के लिए विशेष 32 जीबी माइक्रो एसडी कार्ड लांच करने की घोषणा की है. अबतक मोबाइल फोन के लिए 16 जीबी स्टोरेज क्षमता वाले हाईडेंसिटी माइक्रो एसडी कार्ड बाज़ार में उपलब्ध थे, जो 40 एनएम-क्लास 16 जीबी एनएएनडी पर आधारित थे. सैमसंग का नया 32 जीबी क्षमता वाला माइक्रो एसडी कार्ड बाज़ार में पहले से उपलब्ध मेमोरी कार्ड्स से ज़्यादा एडवांस होगा. यह कार्ड इस मायने में ख़ास है कि आने वाले दिनों में नई और उन्नत तकनीक वाले मोबाइल और स्मार्ट फोनों की संचय क्षमता यानी स्टोरेज कैपसिटी इससे बढ़ाई जा सकेगी. इसे बनाने के लिए सैमसंग ने अपने ख़ुद के 30 एनएम क्लास 32 जीबी एनएएनडी मेमोरी तकनीक को आठ 32 जीबी एनएएनडी कम्पोनेंट के साथ मिलाकर बनाया है. इस ख़ास कम्पोनेंट के साथ, माइक्रो एसडी कार्ड की चौड़ाई एक मिलीमीटर है और कार्ड का वह हिस्सा जो मोबाइल के अंदर डाला जाता है, उसकी लंबाई सिर्फ़ 0.7 मिलीमीटर है. कंपनी इस माइक्रो एसडी कार्ड का उत्पादन इसी वर्ष फरवरी से करने की बात कह रही है, यानी मोबाइल धारकों तक इस माइक्रो एसडी कार्ड को पहुंचने में बस थोड़ा वक़्त और लगेगा. कंपनी का दावा है कि ग्राहक इस कार्ड को अपने पसंदीदा मोबाइल फोन के लिए ज़रूर पसंद करेंगे.

इंटरनेट से जुड़ने का नया विकल्प

रिलायंस, एयरटेल और टाटा इंडिकॉम के हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस मॉडम की तरह ही वर्जिन मोबाइल ने भारत में वी फ्लैश यूएसबी पर आधारित मॉडम लांच किया है. इस मॉडम को एक पोर्ट के ज़रिए अपने पीसी से जोड़ देने पर इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया की जानकारी आपके सामने रहती है. प्लग एंड प्ले यूएसबी पर आधारित यह मॉडम सीडीएमए नेटवर्क पर 3.1 केबीपीएस की स्पीड से इंटरनेट एक्सेस करता है. इसे मास स्टोरेज डिवाइस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी स्टोरेज क्षमता 8 जीबी है. इसकी ऑन डिमांड डाउनलोड सर्विस के ज़रिए मोबाइल रिंगटोन, मोबाइल फोन वॉलपेपर्स, हिंदी फ़िल्में, एमपी-थ्री गाने और म्यूजिक विडियो आदि डाउनलोड की जा सकती है. वी फ्लैश टीवी सर्विस

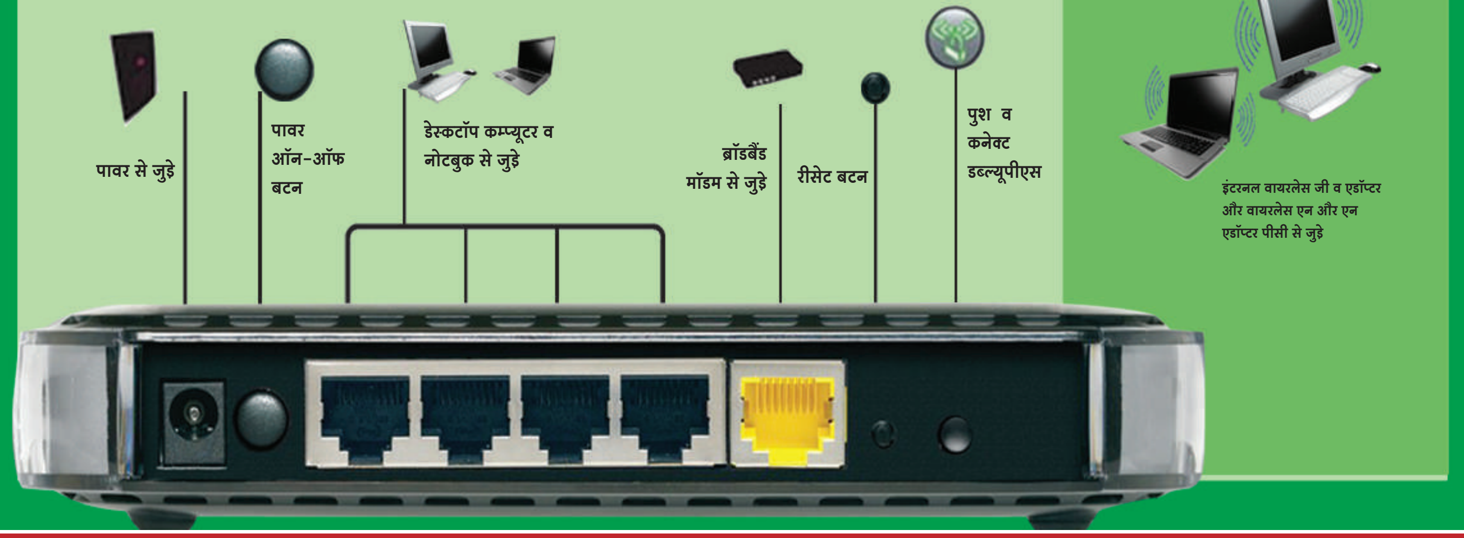

इसकी ख़ास फीचर है, जिसके ज़रिए 40 लोकप्रिय न्यूज़ और एंटरटेनमेंट टीवी चैनलों को देखा जा सकता है. वी फ्लैश यूएसबी मॉडम हार्डवेयर इंटरनेट एक्सेस और दूसरे सर्विसेस के साथ केवल 3,499 रुपये में बाज़ार में उपलब्ध है. इसके टैरिफ प्लान की क़ीमत 250 रुपये से 1,100 रुपये के बीच है. बाज़ार की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कंपनी बाज़ार में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जल्द ही विशेष नाइट प्लान और एनुअल रेंटल प्लान लांच करने का मन बना रही है. इसके अलावा कंपनी की ओर से ग्राहकों को लुभाने के लिए 30 दिनों की सीमित अवधि के लिए ज़ीरो रेंटल पर लाइव टीवी सर्विस और इंटरनेट एक्सेस सुविधा देने की योजना बनाई गई है. कंपनी ऑन डिमांड डाउनलोड सर्विस के लिए असीमित कंटेंट डाउनलोड का ऑफर भी इसी वर्ष मार्च महीने तक देने जा रही है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

भारतीय टीम पाकिस्तानी धुरंधरों का सामना करने मैदान पर उतरी, लेकिन दो विकेट से मात खा गई. पहली बार किसी भी क्रिकेट विश्वकप में पाकिस्तान से भारत को मुंह की खानी पड़ी.

यह दीवार टूटती क्यों नहीं है

फोटो : पीटीआई

क्रिकेट के इतिहास में राहुल द्रविड़ के लिए क्या जगह होगी? क्या उन्हें एक महान खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाएगा या फिर एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जिसकी सफलता हमेशा उसके समकालीन खिलाड़ियों की सफलता के तले दबी रही? इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि अपना पहला ही टेस्ट खेलते हुए द्रविड़ ने 95 रन बनाए. यह किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वह अपने पहले ही मैच में बेहतर प्रदर्शन करे. द्रविड़ ने यही किया, लेकिन उन्हें बधाई नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि उसी मैच में सौरव गांगुली ने 131 रन बनाए और गांगुली का भी वह पहला मैच था. यह कोई पहला उदाहरण नहीं है. द्रविड़ की क़िस्मत ही कुछ ऐसी रही है. ज़रा याद कीजिए जब भारत ने कोलकाता के ईडेन गार्डेन में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लगातार सोलह टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा था. उस टेस्ट में भी द्रविड़ के योगदान को कतई नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. उस टेस्ट में द्रविड़ ने 180 रन का आंकड़ा छुआ तो उन्हीं के साथ दूसरे छोर पर खड़े वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन की पारी खेली. द्रविड़ के साथ यह नाइंसाफ़ी किसी और ने नहीं, बल्कि ख़ुद उनकी तक़दीर ने ही की. जब कभी द्रविड़ ने सभी से जुदा प्रदर्शन किया, कोई दूसरा खिलाड़ी उनसे बेहतर खेल गया. वनडे मैच में जब उन्होंने पहली बार अपना सबसे बड़ा स्कोर 145 रन बनाया तो उसी पारी में सौरव गांगुली ने 183 रनों की पारी खेल उनकी चमक फीकी कर दी. एक बार फिर जब द्रविड़ ने अपना यह रिकॉर्ड तोड़ा और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 153 रनों की पारी खेली, लेकिन उसी पारी में सचिन तेंदुलकर ने नाबाद रहते हुए 186 रन बनाए. इससे यह अंदाज़ा लगाना आसान है कि द्रविड़ ग़लत दौर में पैदा हो गए. क्योंकि उन्हें सचिन तेंदुलकर और गांगुली जैसे खिलाड़ियों की छाया में खेलना पड़ा. लेकिन द्रविड़ ने हमेशा अपनी अहमियत साबित की. कई दफ़ा तो इन भारतीय दिग्गजों से बेहतर खेल दिखाए. जब भारतीय टीम के धुरंधर एक एक कर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाते हैं तो यही दीवार टीम इंडिया की बुनियाद मज़बूत करता है. श्रीलंका के ख़िलाफ़ अहमदाबाद में खेले गए टेस्ट में 32 रन पर सहवाग, तेंदुलकर, लक्ष्मण सहित भारत के चार दिग्गज खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे. पर दर्शकों की उम्मीदें बरक़रार थीं. इसलिए कि द्रविड़ क्रीज पर थे. उन्होंने दर्शकों को निराश भी नहीं किया और भारत को मज़बूत स्थिति में ले गए वह भी अपने बूते.

यह बेहद ही दिलचस्प है कि सौरव गांगुली को सबसे सफल कप्तान माना जाता है, लेकिन उनकी कप्तानी में भारत ने जिन 21 मैचों में जीत हासिल की उनमें टीम के कुल रनों में से 23 फ़ीसदी यानी लगभग एक चौथाई सिर्फ़ द्रविड़ ने बनाए थे. इस दौरान द्रविड़ का कुल औसत सचिन से भी आगे निकल गया. द्रविड़ ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो उस समय उन्हें ख़ारिज़ कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आलोचकों को चुप कर दिया. टेस्ट क्रिकेट द्रविड़ के मिजाज़ से मेल खाता है. ऐसे में यह कल्पना आसान है कि द्रविड़ का असली रूप खेल के इस संस्करण में ही नज़र आ सकता है. लेकिन एकदिवसीय क्रिकेट और अब युवाओं का खेल कहे जाने वाले आईपीएल में भी उनका बल्ला ख़ूब बोल रहा है. द्रविड़ आज अपनी आईपीएल टीम बेंगलुरू की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं.

करियर के शुरुआती और आख़िरी दौर में द्रविड़ जैसे खिलाड़ी के साथ जिस तरह बर्ताव किया गया, देखकर अजीब लगता है. इंग्लैंड के दौरे पर उनके लिए जो गड्ढा खोदा गया था, उससे बाहर निकलने में द्रविड़ को दो साल लग गए. इस सीरीज़ के बाद तो कुछ जूनियर खिलाड़ियों ने भी उनकी आलोचना की थी. यहां तक कहा कि 14 पारियों में वे कोई शतक नहीं बना सके. लगातार यह कहा जाने लगा कि यह अब उनके करियर का अवसान है. लेकिन द्रविड़ ने हार नहीं मानी. अपनी जंग वह लड़ते रहे. दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उनके शतक आलोचकों को शांत करने में असफल रहे. पर इसके बाद न्यूज़ीलैंड में भी जब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो सभी को सांप सूंघ गया. फिर अहमदाबाद और कानपुर की पारियों में उसी पुराने द्रविड़ की झलक दिखी. अभी हाल में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उसी द्रविड़ का हमें दीदार हुआ. लेकिन दूसरे टेस्ट में शतक जमाने के बाद वह चोटिल हो गए. लेकिन चोटिल होने के पहले वह टेस्ट करियर का 29वां शतक ठोक अपनी सफलता की तरकश में एक और तीर जोड़ चुके थे. इतनी सफलता हासिल करने के बाद भी यदि द्रविड़ वह मुक़ाम हासिल नहीं कर पाए, जितनी सफलता उनके समकालीन सचिन और गांगुली ने हासिल की तो बस यही कही जा सकता है कि क्रिकेट के इतिहास में द्रविड़ जैसे सितारा ने ग़लत समय पर अपनी चमक बिखेरने की कोशिश की. लेकिन वह दौर भी आएगा, जब क्रिकेट के इतिहासकार द्रविड़ की एक अलग ही गाथा लिखेंगे.

टेस्ट मैचों में 10,000 से अधिक रन बनाने वाले तीन भारतीय

बल्लेबाज़	रन
सचिन तेंदुलकर	13,234
सुनील गावस्कर	10,122
राहुल द्रविड़	11,395

- टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक बार शतकीय साझेदारी करने वाले बल्लेबाज़– 80 से अधिक बार (3 दिसंबर, 2009)
- गांगुली का कप्तानी में टीम इंडिया के 21टेस्ट मैचों की जीत में बनाए गए कुल रनों में द्रविड़ का योगदान 23 फ़ीसदी रन.
- टेस्ट इतिहास में किसी एक कप्तान के अंदर जिसने 20 से अधिक मैच जीते हों, उसमें किसी खिलाड़ी द्वारा यह सबसे अधिक योगदान है.
- भारत के बाहर सबसे अधिक रनों की साझेदारी करने वाले खिलाड़ी (410 रन पाकिस्तान के विरूद्ध सहवाग के साथ). पंकज रॉय और वीनू मांकड ने 413 बनाए थे न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ चेन्नई में.
- तेंदुलकर (7165) के बाद विदेशों में द्रविड़ (6430) ने सबसे ज़्यादा रन बनाए.
- नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी करते समय 8000 से भी अधिक रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज.

एक दिवसीय

10,000 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय और विश्व के छठे बल्लेबाज़

बल्लेबाज़	रन
सचिन तेंदुलकर	17,394
सनथ जयसूर्या	13,428
रिकी पॉन्टिंग	12,381
इंजमाम उल हक़	11,739
सौरव गांगुली	11,363
राहुल द्रविड़	10,765
जैक्स कैलिस	10,409
ब्रायन लारा	10,405

- किसी विश्वकप में तीन सौ रनों (गांगुली के साथ 1999 विश्वकप) की साझेदारी करने वाले पहले बल्लेबाज़
- एकदिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबी साझेदारी करने वाले बल्लेबाज (331 रन सचिन के साथ न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़)
- दक्षिण अफ्रीका को टेस्ट मैचों में उसी ज़मीन पर मात देने वाले पहले कप्तान.

अंडर-19 विश्वकप

पाकिस्तान से भारत के हारने की वजह

क्रिकेट का मैदान हो और भारत-पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने. ऐसे में खेल का रोमांच हमेशा अपने चरम पर होता है. और, बात जब क्रिकेट विश्वकप की हो तो दोनों टीमें जंगी सेना और क्रिकेट का मैदान रणभूमि में तब्दील हो जाता है. ऐसे में भला हारना कौन चाहेगा. जीत से कम के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता है. पिछले दिनों कुछ ऐसे ही हालात थे.

शृंखला-अंडर नाइनटीन क्रिकेट विश्वकप. आमने सामने दुनिया की दो कट्टर प्रतिद्वंद्वी टीमें भारत और पाकिस्तान. दोनों के बीच क्वार्टर फाइनल का मुक़ाबला. जीत से सेमीफाइनल में जगह तय होती तो हार से बाहर का रास्ता. भारतीय टीम पाकिस्तानी धुरंधरों का सामना करने मैदान पर उतरी. लेकिन भारतीय टीम दो विकेट से मात खा गई. पहली बार किसी भी क्रिकेट विश्वकप में पाकिस्तान से भारत को मुंह की खानी पड़ी.

फोटो : पीटीआई

लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आख़िर पाकिस्तान ने भारत को पटखनी कैसे दी. इसके पीछे दोनों देशों के क्रिकेट का इतिहास ज़िम्मेदार है. साल 2003 में भारत क्रिकेट विश्वकप के फाइनल में पहुंचा था और भारत ने ही पाकिस्तानी टीम को हरा कर विश्वकप से बाहर का रास्ता दिखाया था. दूसरी बार मौक़ा आया पहले टी-20 विश्वकप का. पाकिस्तान लीग मैच में भारत से हारने के बाद एकबार फिर फाइनल में भारत के सामने था. मैच बेहद ही रोमांचक दौर में था. लेकिन भारत ने एकबार फिर पाकिस्तान की हसरतों पर पानी फेर दिया. दूसरी शृंखलाओं में अक्सर भारत को मात देने वाली पाकिस्तानी टीम इसबार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी. अंडर नाइनटीन क्रिकेट विश्वकप में भारत को बाहर करने के लिए वह पूरी तरह तैयार थी. और जैसा कि होता है, दोनों टीमें जब आमने सामने होती हैं तो खिलाड़ियों पर जीत हासिल करने का दबाव भी अपने चरम पर होता है. जो टीम इस दबाव को झेलने में सफल हो जाती है, जीत का सेहरा भी उसी के सिर बंधता है. इस बार पाकिस्तानी कप्तान अज़ीम गुम्मन भारतीय कप्तान अशोक मनेरिया की अपेक्षा इस दबाव को बेहतर तरीक़े से झेल गए. नतीज़तन, जीत उनके हिस्से आई. और, आईपीएल के विवाद ने भी इस मैच में काफ़ी अहम रोल निभाया. जिस तरह आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपमानित किया गया, उसने भी आग में घी का काम किया. अब पाकिस्तान उस अपमान का बदला खेल के मैदान पर लेना चाहता था और उसने ऐसा कर दिखाया. यानी वाक़ई पाकिस्तान ने अंडर नाइनटीन विश्वकप में अति आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम को धूल चटाने में कामयाब हो गया.

खेलों की बर्बादी की वजह

सुरेश कलमाडी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं. कई वर्षों से इस पद पर उनका एकछत्र राज चल रहा है. वह राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के भी अध्यक्ष हैं. यह हक़ीक़त है. लेकिन एक हक़ीक़त यह भी है कि वह भारतीय खेलों के माफ़िया हैं. यह कहना है हॉकी टीम के पूर्व कप्तान परगट सिंह का. मुमकिन है पूर्व हॉकी कप्तान ने यह बातें दिन ब दिन हॉकी की बिगड़ती हालत और खिलाड़ियों की अनदेखी होने की वजह से कही हो. दरअसल राष्ट्रमंडल खेल भारत में इसी साल अक्टूबर में होने हैं. लेकिन जैसे-जैसे इसके आयोजन की तारीख़ क़रीब आ रही है, इससे जुड़े विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं. इसकी तैयारियों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक इतने विवाद हुए हैं कि यह राष्ट्रमंडल कम विवादमंडल खेल ज़्यादा नज़र आ रहा है.

भारत में खेलों के साथ विवाद किसी एक संघ या खेल से नहीं जुड़ा है. लगभग हर खेल संघ इन विवादों के चपेट में हैं. हर खेल संघ के कर्ताधर्ता वे लोग हैं, जिन्हें खेल से कम सत्ता की कुर्सी से ज़्यादा मतलब होता है. सरकार भी अपने क़रीबियों को ऐसे पदों पर बिठाने से बाज नहीं आती है. जो अधिकारी, नेता या मंत्री सत्तारूढ़ दल के ज़्यादा क़रीब होते हैं, उसे किसी न किसी तरह से पुरस्कृत किया जाता है, ताकि वह सत्ता की मलाई का स्वाद हमेशा लेते रहें. इसकी एक नहीं, कई मिसाल हैं. सबसे पहले बात करते हैं, इन

फोटो : प्रभात पाण्डेय

दिनों क्रिकेट से ज़्यादा सुर्ख़ियां बटोरने वाली खेल हॉकी की. पहले हॉकी के पुरुष खिलाड़ियों ने बग़ावत की, उसके बाद महिलाओं ने भी पुरुष खिलाड़ियों के नक्शेक़दम पर चलने का फ़ैसला लिया, वजह खिलाड़ियों के पैसे का भुगतान न होना. अब एक और मामला सामने आ गया है. वह यह कि हॉकी इंडिया के चुनाव जो लगातार लटक रहे थे, अभी भी उसका समाधान नहीं हो पाया है. इसका ख़ामियाज़ा यह हुआ कि एफआईएच को यह चेतावनी देनी पड़ी है कि यदि हॉकी इंडिया अपना चुनाव हॉकी विश्वकप के पहले नहीं कराती है तो मुमकिन है भारतीय टीम इसमें भाग न ले पाए. पूरा मामला अब कोर्ट में जा चुका है. यह है एक छोटी सी कहानी भारतीय राष्ट्रीय खेल की खस्ताहालत की.

इसके अलावा और भी कई खेल संघ हैं, जिनको उनके ज़िम्मे छोड़ दिया जाता है जिन्हें खेल की ज़रा भी समझ नहीं होती है. पंजाब को आतंकवाद की आग से निजात दिलाने में अहम किरदार निभाने वाले के पी एस गिल का खेलों से क्या लेना देना? लेकिन हॉकी इंडिया के अस्तित्व में आने से पहले भारतीय हॉकी संघ को लंबे अरसे तक उनके भरोसे छोड़ दिया गया. क्रिकेट की ही बात करें तो इसमें वैसे नेताओं का वर्चस्व काफ़ी है, जिन्हें क्रिकेट की सही समझ भी नहीं है. चाहे वह लालू यादव हों या नरेंद्र मोदी और सीपी जोशी. लेकिन ये सभी क्रिकेट संघों के अध्यक्ष हैं. फुटबॉल संघ के अध्यक्ष नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल हैं. रुचिका कांड से चर्चा में आए एस पी एस राठौर भी हरियाणा लॉन टेनिस संघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं. इस तरह एक नहीं कई उदाहरण हैं. इससे एक बात तो साफ़ है, जब तक खेलों को संवारने और विकसित करने की ज़िम्मेदारी इन पर होगी, खेल का विकास हो या न हो, इनका सितारा कभी गर्दिश में नहीं रहने वाला है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

ख़बर यह भी है कि कैटरीना सिर्फ़ फ़िल्मों के मामले में सावधान नहीं हुई हैं, बल्कि साथ काम करने वाले सह कलाकारों के मामले में भी वह चूज़ी हो गई हैं.

श्रेयस की नई फ़िल्म

पिछले कुछ वक़्त से बॉलीवुड में श्रेयस तलपड़े की एक अच्छे एक्टर के तौर पर पहचान बनी है. आनेवाले दिनों में वह फ़िल्म *द हैंगमैन* में नज़र आएंगे. अक्षर मीडिया प्रोडक्शंस की आने वाली अंग्रेजी फ़िल्म *द हैंगमैन* के निर्माता बिपिन पटेल हैं. इस फ़िल्म को निर्देशित किया है विशाल भंडारी ने. विशाल इस फ़िल्म से निर्देशन के क्षेत्र में क़दम रखने जा रहे हैं. *द हैंगमैन* वास्तविक कहानी से प्रेरित फ़िल्म है. इसमें श्रेयस के साथ ओम पुरी, गुलशन ग्रोवर, स्मिता जयकर, टॉम आल्टर और नाजनीन घनी आदि कलाकारों ने अभिनय किया है. फ़िल्म की कहानी के केंद्र में एक जल्लाद है. शिव नाम के इस जल्लाद की भूमिका ओम पुरी ने निभाई है. सैकड़ों अपराधियों को फ़ांसी पर लटका चुका शिव, परिवार की परंपरा का पालन करते हुए मजबूरी में इस पेशे को अपनाता है और इस कारण हमेशा अपराधबोध से ग्रसित रहता है. अपनी मजबूरियों का बोझ अपने बेटे गणेश (श्रेयस तलपड़े) पर नहीं लादते हुए सीधा सादा शिव उसे अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है. वह चाहता है कि उसका बेटा गणेश पुलिस ऑफिसर बनकर कोई अच्छा काम करे. उसके इस सपने को पूरा करने में एक जेलर उसकी मदद करता है. गणेश भी अपने पिता के सपने को साकार करना चाहता है, लेकिन शिव के इस सपने की उम्र बहुत छोटी होती है और पूरा होने से पहले ही वह टूट कर बिखर जाता है. शिव की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था. उसे अपने हाथों बेटे को फांसी पर लटकाने के दिन देखने पड़ते हैं.

दर्शील सुपरहीरो हैं

फ़िल्म *तारे ज़मीं पर* से धूम मचाने वाले दर्शील सफारी आनेवाले दिनों में सुपरब्वॉय की भूमिका में नज़र आनेवाले हैं. डिजनी एक नए कांसेप्ट के साथ बच्चों के लिए प्रेरणादायक फ़िल्म *जोकोमॉन* बना रही है. दर्शील इसमें मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म कुणाल नाम के एक अनाथ बच्चे की कहानी है. उसके अंकल उसे बहुत परेशान करते हैं. अपनी परेशानियों से तंग आकर वह अपनी मदद ख़ुद करने की ठान लेता है और अपने दम पर अपना जीवन चलाता है. ख़ुद को सक्षम बनाने की कोशिश में वह मन से डर हटाकर ख़ास शक्तियां हासिल करता है. इस फ़िल्म में एडवेंचर के साथ एक्शन भी है. अपनी फ़िल्म के बारे में लोगों को, ख़ासकर बच्चों को, बताने दिल्ली आए दर्शील दिल्ली को ख़ुद के लिए लकी मानते हैं. वह कहते हैं, *तारे ज़मीं पर* का पहला प्रीमियर यहीं हुआ था और यह ज़बर्दस्त हिट साबित हुई. *जोकोमॉन* का पहला प्रोमोशन भी यहीं हुआ. इस कनेक्शन से उन्हें फ़िल्म का भविष्य अच्छा होने की उम्मीद है. सुपरब्वॉय जोकोमॉन का किरदार अदा करने वाले दर्शील सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन से प्रभावित रहे हैं. फ़िल्म *जोकोमॉन* का उन्हें कौन सा डायलाग पसंद है, पूछने पर वह तपाक से एक डायलाग –*मन में है विश्वास तो हर डर है बकवास*– बोल लोगों का दिल जीत लेते हैं. वह कहते हैं इस डायलाग की बात पर वह अपनी ज़िंदगी में भी यक़ीन करते हैं. दर्शील कहते हैं फ़िल्म में सुपरहीरो का किरदार निभाने में सबसे मुश्किल था जोकोमॉन का कॉस्ट्यूम पहनना. इसे पहनने में उन्हें लगभग एक घंटे का समय लगता था. दर्शील को दिल्ली की हल्की सर्दी वाला मौसम भी बेहद पसंद है.

कैटरीना हुई चूज़ी

अगर आप कैटरीना कैफ के बारे में यह सोच रहे हैं कि वह सिर्फ़ ग्लैम डॉल बनकर रह जाएंगी तो आप ग़लत सोच रहे हैं. अपने ग्लोबल स्टेटस को देखते हुए वह एक गंभीर कलाकार के रूप में अपनी छवि सुधारने की हरसंभव कोशिश कर रही हैं. बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली यह अदाकारा वर्ष 2009 में गूगल पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही हैं. इसके अलावा वह विश्व के बाकी सभी श्रेणियों की सेलेब्रीटीज में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही हैं और भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल क्वेरी उनके बारे में ही की गई है. लंदन इस्टर्न आई ने उन्हें सबसे सेक्सी एक्ट्रेस का ख़िताब दिया तो याहू की ओर से उन्हें टॉप ऑनलाइन न्यूज़मेकर 2009 घोषित किया गया. लोगों की अपने प्रति बढ़ती दीवानगी को देखते हुए वह करियर के प्रति थोड़ी ज़िम्मेदार हो गई हैं. करियर के ऊपर ध्यान देने के लिए उन्हें वक़्त भी ख़ूब मिला है. ऐसा लगता है कि कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत बिगड़ने पर जो आराम करने का मौक़ा उन्हें मिला, उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया. *न्यू यॉर्क*, *दे दना दन*, *अजब प्रेम की गजब कहानी* के बाद वह फ़िल्मों के मामले में ज़रा चूज़ी हो गई हैं. इस साल वह फ़िल्म *राजनीति* में एक आम महिला की भूमिका में अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ती नज़र आएंगी जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बनती है. ख़बर यह भी है कि कैटरीना सिर्फ़ फिल्मों के मामले में सावधान नहीं हुई हैं, बल्कि साथ काम करने वाले सह कलाकारों के मामले में भी वह चूज़ी हो गई हैं. लाजवाब कैटरीना आपकी ब्यूटी विद ब्रेन बनने की तैयारी सराहनीय है.

युविका की बात पक्की

कुछ विज्ञापन फ़िल्मों, म्यूजिक विडियो और टीवी सीरियल में वाहवाही बटोरने के बाद युविका चौधरी ने फरहा ख़ान की फ़िल्म *ओम शांति ओम* से बॉलीवुड में क़दम रखा. इस फ़िल्म से उन्होंने लोगों का ध्यान तो खींचा पर राखी सावंत जैसी लोकप्रियता नहीं बटोर सकीं. राखी फरहा ख़ान की फ़िल्म *मैं हूं ना* से ही चर्चा में आईं और कमाल पर कमाल करती गईं. पर युविका इतना बेहतरीन प्लेटफार्म मिलने के बावजूद सफलता का सुख अबतक नहीं देख सकी हैं. *ओम शांति ओम* के बाद युविका, सिंकदर खेर के साथ फिल्म *समर 2007* में नज़र आईं पर न फ़िल्म चली न ही वह ख़ुद. उसके बाद तो वह जैसे रूपहले पर्दे से ग़ायब ही हो गई थीं. इनदिनों वह दक्षिण के सिनेमाघरों में ख़ूब छाई हुई हैं, दरअसल वह कन्नड फ़िल्म *मलयाली जोतेयाली* में मुख्य किरदार अंजली का रोल निभा रही हैं. 11 दिसंबर को रिलीज हुई यह फ़िल्म भी हिट है. लेकिन बॉलीवुड में अपनी मौजूदगी फिर से जताने के लिए वह तब्बू और शरमन जोशी के साथ रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म *तो बात पक्की* में नज़र आने वाली हैं. उनका बचपन उत्तर भारत के मेरठ शहर में गुज़रा है, जहां उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद दिल्ली आकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा किया. फिर ग्लैमर वर्ल्ड में क़दम रखने के लिए उन्होंने जी सिनेस्टार की खोज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और थोड़ी लोकप्रियता हासिल की. इसके बाद उन्होंने जी के ही एक टेली सीरियल *अस्तित्व* में आस्था का किरदार निभाया. इस किरदार ने इंडस्ट्री में बड़े लोगों के बीच उन्हें पहचान दिलाने में बड़ी मदद की.

रैंप पर समीरा

ख़ूबसूरत और बोल्ड फिगर रहने और बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन कलाकारों के साथ काम करने के बावजूद समीरा क़िस्मत की मारी ही कहलाएंगी. 20 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम करने के बावजूद समीरा रेड्डी को फ़िल्म इंडस्ट्री में वह पहचान नहीं मिल पाई है, जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी. अपनी पहचान बरक़रार रखने के लिए उन्होंने हिंदी फ़िल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलगू और बांग्ला फ़िल्मों में भी काम किया. पिछले दिनों फैशन शो में हिस्सा लेने दिल्ली आई समीरा ने अपनी पसंदीदा चीजों और फ़िल्मों के बारे में बातें कीं. उन्होंने कहा कि उन्हें नीता लुल्ला का आउटफिट उन्हें बेहद पसंद है, फैशनेबल कपड़ों और एक्सेसरीज, विशेषत: डिजायनर पार्टी एथनिक वियर के बारे में समीरा कहती हैं कि इनके ख़ास होने की वजह से इन्हें कैरी करने का मज़ा ही अलग होता है. ये डिजायनर वियर ख़ूबसूरत होने के साथ भारी भी होते हैं. इन्हें पहनना प्रिंसेस होने जैसा अहसास देता है. समीरा ने बताया कि उन्हें दिल्ली आना अच्छा लगता है, उन्हें यहां की सर्दी अच्छी लगती है. समीरा का पसंदीदा पेय सोया मिल्क है और उन्हें खाने में जापानी कुजीन का शुशी पसंद है. अपनी फ़िल्मों के बारे में वह बताती हैं कि 12 फरवरी को रिलीज होने वाली अजित की तेलगू फ़िल्म *असल* को लेकर वह काफ़ी उत्साहित हैं. इसमें उन्होंने ख़ुद स्टंट सीन किए हैं. समीरा कहती हैं कि नक्सलियों पर केंद्रित फिल्म *रेड अलर्ट* में अपने किरदार को लेकर वह काफ़ी संतुष्ट हैं. इसमें उन्हें अपने रूपरंग को आमलोगों जैसा सामान्य बनाना पड़ा जो उन्हें काफ़ी अच्छा और वास्तविक लगा. यह उनकी बाकी फ़िल्मों से अलग किरदार वाली कहानी है, जिसे उन्होंने ख़ूब एंजॉय किया.

फ़िल्म प्रीव्यू

तो बात पक्की

तो बात पक्की फन एंड फेमिली ड्रामा है. तब्बू को अरसे बाद किसी हिंदी फ़िल्म में देखा जा सकेगा. उनके अलावा इस फ़िल्म में और कोई बड़ा सितारा नहीं है जो बॉक्स ऑफिस पर भीड़ जुटा सके. तब्बू ने भी *हेराफेरी* के कई साल बाद कॉमेडी में हाथ आज़माया है. कहानी उन्हीं के द्वारा निभाए गए चरित्र राजेश्वरी के इर्दगिर्द घूमती है. राजेश्वरी शादीशुदा है और मिडिल क्लास मानसिकता से ग्रसित है. वह अपनी सोसाइटी को बेहतर दर्ज़े तक ले जाना चाहती है. इसके लिए वह अपनी बहन निशा (युविका चौधरी) की शादी अपनी कम्युनिटी के सक्सेना परिवार में करवाना चाहती है. इसीलिए वह राहुल (शरमन जोशी) को अपने घर में बतौर पेईंग गेस्ट रखती है ताकि निशा और राहुल नजदीक आ सकें. बात बनते ही राजेश्वरी दोनों की बात पक्की कर देती है तभी कहानी में यू टर्न आता है और युवराज(वत्सल सेठ) की एंट्री होती है. राजेश्वरी को युवराज, राहुल से भी बेहतर लगता है. अब उसको अपनी बहन के लिए युवराज चाहिए. इसके लिए वह फिर से नया जाल बिछाती है, पर उसे पता नहीं है कि इस बार राहुल भी निशा को पाने के लिए कई जुगत भिड़ा रहा है. इस तरह से घर में एक नई खिचड़ी पकने लगती है, जिसमें हास्य के मसालों का चटकारा भी है. टिप्स बैनर तले बन रही इस फ़िल्म का निर्देशन केदार शिंदे ने किया है. जबकि गीत लिखे हैं सैय्यद कादरी, मयूर पुरी और शब्बरी अहमद ने. संगीत है कंट्रोवर्सियल संगीतकार प्रीतम का. कोरियोग्राफी अहमद खान की है. फ़िल्म 19 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.

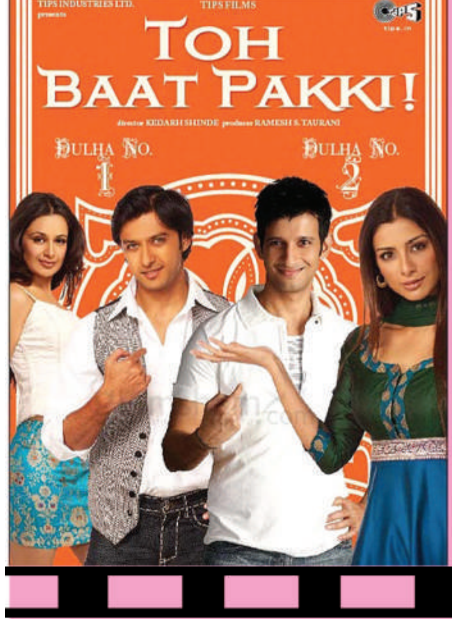

हाइड एंड सीक

हाइड एंड सीक भी 19 फरवरी को ही प्रदर्शित होने जा रही है. दोनों ही फिल्में छोटे बजट की हैं और पब्लिसिटी के लिहाज़ से कमज़ोर हैं. ख़ैर जब फ़िल्म कंप्लीट हो गई है तो थियेटर तक पहुंचेगी ही. *हाइड एंड सीक* में पूरव कोहली, अर्जन बाजवा, मृणालिनी शर्मा और समीर कोचर जैसे सितारे हैं. फ़िल्म का प्लॉट *बैड सेंटा* और *रेंडियर गेम्स* से काफ़ी मिलता जुलता है. कहानी ओम, अभि, जयदीप और गुनिका की है जो क्रिसमस की रात एक गेम खेलते हैं. उन्हें यह नहीं पता कि यही खेल उनकी ज़िंदगी बदल देगा. 12 साल बाद उस रात की कई ख़ौफ़नाक यादें हक़ीक़त बनकर उनके सामने आ जाती हैं. इस बार भी उन्हें वहीं पुराना गेम पूरा करना है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं. कोई और है जो इन सबको 12 साल बाद इस खेल को पूरा करवाने वापस लाया है. आख़िर वह कौन है जो उन्हें इस डेडली गेम में फंसाना चाहता है. यह फ़िल्म इसी राज को खोलती है. इडियट बॉक्स फ़िल्म और मोज़रबेयर के सहयोग से बनी इस फिल्म को शॉन अराहना ने निर्देशित किया है. स्क्रीन प्ले सुरेश नैयर और अपूर्व लाखिया का है, जबकि कहानी लिखी है अपूर्व ने. इस तरह की हॉरर संस्पेंस थ्रिलर फिल्म में बैकग्राउंड संगीत का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इसके लिए अमर मोहिले को चुना गया है. देखते हैं इस लुका छिपी के खेल में दर्शकों की कितनी भागीदारी रहती है.

ग्रेसी को दिल्ली की चाट पसंद

फ़िल्म *लगान* से अपना करियर शुरू करने वाली ग्रेसी सिंह जल्द ही फ़िल्म *असीमा* में नज़र आने वाली हैं. बेहद शांत स्वभाव की ग्रेसी के शौक़ भी बेहद निर्मल, सरल और बच्चों जैसे हैं. उन्हें खिलौने बेहद पसंद हैं. बार्बी डॉल, फेरी, मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, बग्स बनी, और सभी कॉमिक कैरेक्टर के सॉफ्ट टॉयज बेहद पसंद हैं. केवल पसंद ही नहीं, ग्रेसी इन खिलौनों को अपना दोस्त भी कहती हैं. उन्हें अपने घर को खिलौनों से सजाना बहुत अच्छा लगता है. इससे उन्हें अपना घर फेरीलैंड जितना प्यारा लगने लगता है. और क्या–क्या पसंद है दिल्ली की इस पंजाबी कुड़ी को, चलिए आपको बताते हैं. उन्हें दिल्ली की चाट बेहद पसंद है. मुंबई में रहना उन्हें पसंद तो है, पर वह दिल्ली की सड़कों पर बिकने वाली चाट और गोलगप्पों को बहुत मिस करती हैं. हालांकि दिल्ली आने पर वह एक बार चाट के मज़े तो ले ही लेती हैं, पर फिगर को मेंटेन करने के लिए उन्हें कई बार परहेज भी करना पड़ता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 8 फरवरी–14 फरवरी 2010

www.chauthiduniya.com

अनाथ बच्चों का दर्द

कोसी के क़हर से हर कोई वाक़िफ़ है. अब तक यह न जाने कितनी ज़िंदगियां लील चुकी है. न जाने कितने बच्चों के सिर से मां-बाप का साया उठ गया. किसी ने अपना पति खोया तो किसी ने पत्नी. किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने बहन. लेकिन कई बच्चे ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया. अगर अब भी उन अभागे बच्चों के पास कुछ बचा है तो उनका सिसकता बचपन. यह उनकी बदनसीबी अनाथ आश्रम में भी उनका साथ नहीं छोड़ रही है. वहां भी उन्हें दो वक़्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है. जिससे वे भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं. क्योंकि जिस अनाथ आश्रम में वे रह रहे हैं उसकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब है.

सभी फोटो–*एस सोनी*

सरोज सिंह

बुलबुल अनाथ हो गया. कोसी ने उसका सबकुछ छीन लिया. पिछले साल जब देश कोसी की प्रलयंकारी बाढ़ के कारण फैली तबाही के गम में डूबा था, उस समय बुलबुल के अलावा अठारह और अभागे बच्चे सिर से मां बाप का साया उठ जाने का मातम मना रहे थे. बाढ़ में इन बच्चों ने न केवल अपना परिवार खोया, बल्कि इनका बचपन भी कोसी की धार बहा ले गई. ये सभी बदनसीब बच्चे इस समय सहरसा के आकांक्षा अनाथ आश्रम में ज़िंदगी की कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं. यहां भी उन्हें जीने के लिए काफ़ी मशक़्क़त करनी पड़ रही है. आर्थिक तंगी के कारण अनाथालय की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि दो वक़्त का खाना भी इन अभागे बच्चों को नसीब नहीं हो रहा है. कंपकंपाती ठंड की रात वे पुआल पर सोकर गुज़ार रहे हैं. हद तो तब हो जाती है जब सरकारी एवं ग़ैरसरकारी संगठनों से कोई मदद न मिल पाने के कारण इन बच्चों को जीवन बचाने के लिए सड़कों पर निकलकर भीख तक मांगनी पड़ती है.

कोसी का तटबंध क्या टूटा आशा, हरिओम, सीता, बबिता, अभिनंदन, काजल, झुनियां, श्यामसुंदर, विजय, रेशम, इंद्राक्षी, अमरजीत, किरण, सूरज, बुलबुल, राजकमल, आरती और बमबम के सारे सपने टूट गए. जब ये अभागे बच्चे अनाथ हो जाने की सच्चाई से वाक़िफ़ हुए तो उनके सामने कोसी की तबाही के अलावा कुछ भी नहीं था. कोई सरकारी नुमाइंदा उस समय इन बच्चों की मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन दर-दर भटक रहे इन बच्चों को उस वक़्त आकांक्षा अनाथ आश्रम का सहारा मिला. तब उन्हें ऐसा लगा कि चलो अब जैसे-तैसे ज़िंदगी की गाड़ी वे आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य इन बच्चों का साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा. जैसे ही बाढ़ राहत और पुनर्वास का शोर-शराबा ठंडा पड़ा, अनाथालय का चूल्हा भी ठंडा पड़ गया. अब आलम यह है कि किसी तरह इन बच्चों को दो वक़्त का खाना मिल पा रहा है. खाना कैसा मिल रहा है, इस पर बात न ही की जाए तो अच्छा है. कभी-कभी तो नमक रोटी पर भी आफ़त आ जाती है. कभी एक पेट खाकर ही काम चलाना पड़ जाता है. मतलब सुबह हो गई तो शाम का पता नहीं और शाम हो गई तो सुबह का पता नहीं. इन बच्चों के पढ़ने-लिखने का सिलसिला भी टूट चुका है. कई बच्चे तो अपने मां-बाप का नाम और पता भी भूलने लगे हैं. तमाम परेशानियां झेल रहे इन बच्चों का कहना है कि वे अनाथालय में ही रहना चाहते हैं, लेकिन यहां उनके खाने और पढ़ने का इंतजाम तो कर दिया जाए. शारीरिक और मानसिक तौर पर लगातार कमज़ोर हो रहे ये बच्चे चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी किसी भी तरह पटरी पर आ जाए. कई बच्चे अपनी पीड़ा तक बयां नहीं कर पाए. उनकी आंखों में झांकने भर से उनका सारा गम, उनकी सारी पीड़ा नज़र आ जाती है. कोसी की मार उन्हें इस मुक़ाम पर लाकर खड़ा कर देगी, उन्होंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था. अब तो ये बच्चे रात-दिन इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि चलो आज का दिन तो निकल गया, लेकिन न जाने उनका अगला दिन कैसे गुज़रेगा.

ज़िंदगी बचाने की इसी जंग में ये अनाथ बच्चे भिक्षाटन रैली में भी शामिल हो चुके हैं. रैली में बच्चों ने इस सरकार एवं तथाकथित सभ्य समाज से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी. तख्ती लेकर शहर में निकले इन बच्चों ने यह जानना चाहा कि क्या उन्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक़ नहीं है! क्या राहत और पुनर्वास के नाम पर मिले लाखों-करोड़ों रुपयों में इनका कोई हिस्सा नहीं है? क्या बदल रहा बिहार उनके चेहरों को नहीं पढ़ पा रहा है! क्या सहरसा शहर एवं इस राज्य के लोगों की संवेदना इतनी मर चुकी है कि उनकी पीड़ा का उन्हें अहसास तक नहीं हो पा रहा है? शायद इन सारे सवालों का जवाब उन्हें न में ही मिले. नहीं तो आज इन उन्नीस अनाथ बच्चों को नमक रोटी खाकर और पूस की रात पुआल में सोकर नहीं बितानी पड़ती.

अनाथालय की देख-रेख कर रहे इंद्राक्षी एजुकेशनल सोसाइटी के डॉ. शिवेन्द्र कुमार का कहना है कि इन बच्चों के लिए समय-समय पर डीएम, सीएम एवं पीएम तक को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गईं. कुमार का कहना है कि किसी तरह इन बच्चों को रखा जा रहा है, लेकिन संस्था की भी अपनी सीमाएं हैं. हमारे बार-बार अपील के बावजूद बच्चों को मदद नहीं मिल पा रही है. संस्था से जुड़ी बबली का कहना है कि दर-दर भटकने के बावजूद बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है. मदद के लिए हाथ न उठने के कारण हमलोग भी लाचार हो रहे हैं. ख़ैर, उनकी लाचारी तो समझ में आती है, पर शासन चला रहे हाक़िमों और सरकार चला रहे नेताओं की लाचारी समझ से परे है. देश दुनिया से राहत के नाम पर आए पैसों में क्या इन बच्चों का हक़ नहीं है?

बाढ़ में अपना सबकुछ खो चुके इन अभागे बच्चों को दो वक़्त की रोटी और उनकी पढ़ाई का इंतजाम भी इन लोगों से नहीं हो पा रहा है. अगर लोगों के सीने में कहीं धड़कता हुआ दिल है तो अभी भी देर नहीं हुई, आगे बढ़कर इन बच्चों को थामने की कोई तो हिम्मत दिखाए. कम से कम इन नौनिहालों को भीख मांगने को विवश न होना पड़े, सभ्य समाज को इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

अनाथालय पर गाज गिर सकती है!

अगर सहरसा ज़िलाधिकारी आर लक्षणन की मानें तो आकांक्षा अनाथ आश्रम बंद ही होने वाला है. उसके बीस बच्चों को श्री लक्ष्मणन पटना के सरकारी चाइल्ड होम में भेजने वाले हैं. इस बीच ज़िलाधिकारी ने जूवेनाइल जस्टिस के तहत इस संस्था के कार्यकलापों की जांच का आदेश दे दिया है. इसकी जांच सहायक निदेशक, ज़िला सामाजिक सुरक्षा कोषांग करेंगे. ज़िलाधिकारी के मुताबिक़, जांच रिपोर्ट आने पर जुवेनाइल एक्ट के तहत इस संस्था के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. इस तरह से संस्था पर गाज गिरना तय माना जा रहा है. ग़ौरतलब है कि अनाथ बच्चों को रखने के लिए अनाथ आश्रम का पंजीकरण संबंधित विभाग से होना ज़रूरी है, लेकिन इस संस्था के पास ऐसा पंजीकरण नहीं है. इस बाबत अनाथ आश्रम के संचालक डॉ. शिवेंद्र कुमार बताते हैं कि संस्था चैरिटेबल सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत है. हालांकि लक्ष्मणन संस्था के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत करने की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं. उनके साफ़-सफ़ाई एवं खानपान का ध्यान रखा जाता है या नहीं. साथ ही वह यह भी देखेंगे कि संस्था को बच्चों को रखने से संबंधित अधिकार और व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं.

आर लक्ष्मणन, जिलाधिकारी सहरसा

मुज़फ़्फ़रपुर में एनडीए की राह आसान नहीं

मुज़फ़्फ़रपुर में विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से लोगों के बीच तरह-तरह के सवाल उठने लगे हैं. जैसे, क्या नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में लौट कर आएंगे? हालांकि लोग यह भी बेबाकी से कहते हैं कि सड़कें अच्छी हो गई हैं, स्कूल चकाचक हैं, अस्पतालों की हालत अच्छी है और अपराध कम हुए हैं. फिर भी यह पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश फिर से सत्ता में आएंगे या नहीं? हालांकि सवाल यह भी नहीं है कि नीतीश सत्ता में आएंगे या नहीं. असल सवाल तो यह है कि अगर नीतीश कुमार को सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचाने वाले फिर से विधानसभा में लौटकर नहीं आएंगे, तो नीतीश को कौन लाएगा? तमाम फीलगुड के बावजूद विधानसभा उपचुनाव में ज़िले के बोचहां (सुरक्षित) और औराई क्षेत्र में जदयू की क़रारी हार ने पार्टी कार्यकर्ताओं की नींद उड़ा दी है. उपचुनाव के परिणाम को आगामी विधानसभा चुनाव के ट्रेलर के रूप में देखा जाए तो चुनावी संभावनाओं की तराज़ू पर ज़िले के सभी 11 विधायकों को तौलने का सिलसिला शुरू हो गया है. कोई जाति के बटखरे से तौलता है तो कोई पार्टी के विधायकों की उपलब्धियों, विकास योजनाओं और सघन-नियमित जनसंपर्क के आधार पर. पिछले चुनाव में वजनदार नेता बनकर उभरे कई विधायक पांच साल पूरे होने से पहले ही हल्के होने लगे हैं. वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में ज़िले की 11 में से सात सीटों पर जदयू एवं एक सीट पर भाजपा ने क़ब्ज़ा जमाया था. मुज़फ़्फ़रपुर विधानसभा क्षेत्र से राजग समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई थी. राजद सिर्फ़ बोचहां (सु.) एवं गायघाट सीटों पर क़ब्ज़ा बरक़रार रख पाया था. वर्ष 2009 के उपचुनाव में राजद के सुरेंद्र राय ने जदयू से औराई सीट छीन ली और बोचहां (सु.) पर भी क़ब्ज़ा बरक़रार रखा. कहा तो यहां तक जा रहा है कि नीतीश कुमार की राह के रोड़े ख़ुद उनके विधायक हैं. अपनी उपलब्धियां गिनाकर जनता से इन विधायकों के लिए वोट मांगना नीतीश के लिए आसान नहीं होगा. जदयू नेताओं को उम्मीद है कि कुछ विधायकों के टिकट काटकर नीतीश नए चेहरों को आज़माएंगे. अब सवाल यह उठता है कि वह कितने विधायकों का टिकट काटने की हैसियत रखते हैं? टिकट काटने पर यही विधायक बाग़ी प्रत्याशी बनकर पार्टी की मिट्टी पलीद करेंगे. इसका संकेत विधानसभा उपचुनाव में भी मिला. जदयू एवं भाजपा विधायकों की जीत में जिन भूमिहार मतदाताओं के ध्रुवीकरण का बड़ा योगदान था, वही आज एनडीए विधायकों से नाराज़ हैं. रही सही कसर वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव ने पूरी कर दी. बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव में मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में पारू, साहेबगंज, बरूराज और कांटी के एनडीए विधायकों ने वैशाली के जदयू प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ़ मुन्ना शुक्ला का विरोध किया. कांटे की टक्कर में मुन्ना शुक्ला की हार ने भूमिहार वोटरों को आहत किया. नाराज़ वोटर विधानसभा चुनाव में हिसाब चुकता कर सकते हैं. इसके अलावा विधायकों द्वारा ठेकेदारी में अपना सिंडिकेट खड़ा करना भी महंगा पड़ सकता है. नीतीश कुमार के लिए कांटी का कांटा निकालना भी आसान नहीं होगा. राज्य मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद कांटी के विधायक अजीत कुमार खार खाए बैठे हैं. इसलिए नीतीश कुमार के बाद अजीत आज तक नीतीश की किसी सभा या बैठक में नज़र नहीं आए. कई अवसरों पर अख़बारों में उनके जो बयान आए, उनमें शासन-प्रशासन की विफलताओं के प्रति नाराज़गी झलकती रही. पिछले दिनों में लगातार बैठकें और जनसंपर्क कर रहे अजीत कुमार के राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के क़रीब पहुंचने की भी बात कही जा रही है. अगर उन्हें राजद से टिकट नहीं मिला तो वह पुराने घर कांग्रेस में भी लौट सकते हैं. टिकट वितरण में भी जदयू में ख़ासी खींचतान, बग़ावत एवं भीतरघात की पृष्ठभूमि बनेगी. पिछली बार जार्ज फर्नांडीस ने गायघाट में अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया, लेकिन टिकट से वंचित वीणा देवी ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके अशोक के रथ को रोक दिया. विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह के साथ उनकी पत्नी वीणा देवी एक बार फिर जदयू में शामिल हो चुकी हैं. दिनेश प्रसाद सिंह की मानें तो नेतृत्व ने वीणा देवी को इस बार गायघाट से मौक़ा देने का आश्वासन दिया है. अजय सिंह का नाम भी इस क्षेत्र से चर्चा में है. गत लोकसभा चुनाव में जार्ज फर्नांडीस की खुली मदद करने के कारण जदयू से निष्कासित अशोक सिंह जार्ज के सांसद बनने के बाद पार्टी में आ गए हैं और नेतृत्व से अपने रिश्ते सामान्य करने के साथ-साथ गांव-गांव में पकड़ मज़बूत करने में जुटे हैं. रमई राम भले ही बोचहां क्षेत्र से उपचुनाव में हार गए, लेकिन जदयू एक बार फिर उन्हें ही आजमाएगा. सर्वाधिक संकट में मुज़फ़्फ़रपुर के निर्दलीय विधायक विजेंद्र चौधरी हैं. लोकसभा चुनाव में तो उन्हें मात्र 10 हज़ार वोट मिले. अब वह राजद, जदयू, कांग्रेस या लोजपा में से किसी एक नाव पर बैठने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं. मगर, हर जगह उनके नाम पर विरोध है. विधानसभा उपचुनाव में ज़िले की दोनों सीटों पर क़ब्ज़ा जमाने के बाद राजद का आत्मविश्वास बढ़ा है. राजद एक बार फिर अपने गढ़ पर कब्ज़ा ज़माने की ताक में है. लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ने वैशाली सीट पर क़ब्ज़ा जमाया और ज़िले के कई विधानसभा क्षेत्रों में राजद ने बढ़त बना ली. फ़िलहाल राजद का गायघाट, बोचहां एवं औराई सीटों पर क़ब्ज़ा है. उसे पारू, साहेबगंज, कुढ़नी और कांटी भी आसान टारगेट नज़र आते हैं. राजद के रणनीतिकार कुछ सीटों पर राजपूत-भूमिहार प्रत्याशी खड़ा कर एनडीए की गणित बिगाड़ने की वक़ालत कर रहे हैं. कुढ़नी में वर्ष 2005 के दोनों चुनावों में लोजपा प्रत्याशी शाह आलम सब्बू ने मुस्लिम वोट काटकर राजद के लिए संकट खड़ा कर दिया था. जेल में बंद मनोज कुशवाहा को वोटरों की सहानुभूति भी मिली. लेकिन चार सालों में सहानुभूति समाप्त हो गई. मनोज से नाराज़ समुदायों में कई जातियां शामिल होती चली गईं. पूर्व मंत्री बसावन प्रसाद भगत कुढ़नी से जदयू के टिकट के प्रबल दावेदार हैं, परंतु बाहरी प्रत्याशी पर कुढ़नी के वोटर दोबारा शायद ही विश्वास करेंगे. कुढ़नी से वर्ष 1995 एवं 2000 का चुनाव जीत चुके बसावन भगत की राजनीति अगड़ा विरोधी रही है. ऐसे में जदयू का टिकट पाने पर भी उन्हें अगड़ों का समर्थन मिलने में संदेह है. सकरा में पिछली बार राजद के लालबाबू राम बहुत कम मतों से पराजित हुए थे, लेकिन इन चार सालों में यादव वोटरों से उनकी दूरी बढ़ती चली गई. वोटर जदयू विधायक विलट पासवान से भी बेहद नाराज़ हैं और प्रत्याशी बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. साहेबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह नाराज़ वोटरों को मनाने में जुटे हैं. वहां राजद द्वारा पूर्व विधायक रामविचार राय को प्रत्याशी बनाया गया तो राजू सिंह को फ़ायदा हो सकता है. वह जनता से पश्चिमी दियारा में दोबारा आतंकराज क़ायम न होने देने का आह्वान करेंगे. राजद एवं लोजपा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंस सकता है. लोजपा कुढ़नी, कांटी, सकरा सहित कुछ अन्य सीटों की मांग करेगी, परंतु उसके पास कद्दावर प्रत्याशियों का अभाव है. लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुज़फ़्फ़रपुर सीट ले ली, लेकिन राजद से प्रत्याशी उधार लेना पड़ा. राजद नेता डॉ. भगवान लाल सहनी लोजपा प्रत्याशी बने, मगर लोजपा में नेटवर्क की कमी के कारण जदयू के कमज़ोर प्रत्याशी कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद अंतत: मज़बूत हो गए.

ज़िले में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है. राजद, जदयू एवं भाजपा के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस बार कांग्रेस को अच्छे वोट मिलेंगे. उपचुनाव में औराई एवं बोचहां में दस-दस हज़ार वोट बटोर चुकी कांग्रेस कई सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है. राहुल गांधी के अभियान और प्रत्येक ज़िले की कमान एक-एक कांग्रेसी सांसद को सौंपे जाने की ख़बर से गांव-गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ख़ासा उत्साह है. सदस्यता अभियान से कांग्रेस कार्यालय की रौनक बढ़ी है. प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष विनीता विजय, विधान पार्षद महाचंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री उषा सिन्हा के पुत्र अनुभव सिंह सहित दो दर्जन से अधिक लोग पार्टी टिकट के प्रबल दावेदार हैं, जिनके समर्थन एवं अन्य संसाधनों की बदौलत कांग्रेस सभी 11 सीटों पर चुनौती देने की तैयारी में है. कांग्रेस की सक्रियता एनडीए के साथ-साथ राजद को महंगी पड़ेगी. राजद को मुस्लिम और एनडीए को अगड़ी जाति के मतों के बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ सकता है.

अजीत कुमार

सुरेंद्र राय

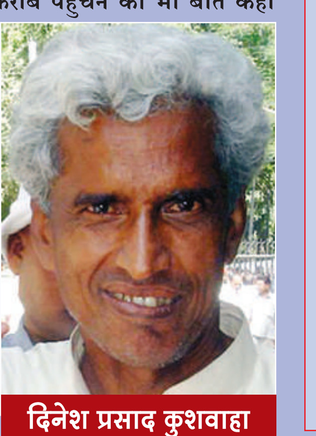
दिनेश प्रसाद कुशवाहा

अशोक कुमार

विजेंद्र चौधरी

मनोज कुशवाहा

विलट पासवान

राजू सिंह

विधानसभा क्षेत्रों की दलगत स्थिति

क्षेत्र	विधायक	दल
पारू	अशोक सिंह	भाजपा
साहेबगंज	राजू कुमार सिंह	जद-यू
बरूराज	शशि कुमार राय	जद-यू
कांटी	अजीत कुमार	जद-यू
मुज़फ़्फ़रपुर	विजेन्द्र चौधरी	निर्दलीय
कुढ़नी	मनोज कुशवाहा	जद-यू
मीनापुर	दिनेश प्रसाद कुशवाहा	जद-यू
औराई	सुरेन्द्र राय	राजद
गायघाट	महेश्वर प्रसाद यादव	राजद
बोचहां (सु.)	मुसाफिर पासवान	राजद
सकरा (सु.)	विलट पासवानफ	जद-यू

संगीता
feedback@chauthiduniya.com

तस्करों का नया अड्डा

भारत-नेपाल को विभाजित करने वाली 1850 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा इन दिनों अतिक्रमण का शिकार होकर देश विरोधी तत्वों की शरणस्थली एवं तस्करों का एक प्रमुख अड्डा बन गई है. मालूम हो कि दोनों देशों के मध्य स्थित विभाजक रेखा को आम बोलचाल में नो मेंस लैंड कहा जाता है. लोगों ने यहां इस क़दर अतिक्रमण कर लिया है कि देखने से पता ही नहीं चलता कि यह नो मेंस लैंड एरिया है. आलम यह है कि इस प्रतिबंधित इलाक़े में निवास करने वाले परिवारों की संख्या सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में है. नो मेंस लैंड के लिए 1850 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में छोड़ी गई 20 गज चौड़ी पट्टी पर लोगों ने झोपड़ी से लेकर पक्के मकान तक बना लिए हैं. जगह-जगह घास-फूस समेत खेती-बाड़ी का काम यहां बेरोकटोक किया जा रहा है. दोनों देशों की सेना एवं पुलिस के प्रभाव से मुक्त माने जाने वाले नो मेंस लैंड क्षेत्र में जहां देश विरोधी तत्व आराम फरमाते हैं, वहीं अंतरराष्ट्रीय तस्कर इस क्षेत्र का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं.

इस क्षेत्र में अतिक्रमण और 60 फीट चौड़ी पट्टी के सिकुड़ जाने के कारण भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कड़ी चौकसी का उच्चस्तरीय सरकारी आदेश धरातल पर दम तोड़ता नज़र आता है. सीमांचल इलाक़े में व्याप्त भीषण ग़रीबी एवं अत्यंत पिछड़े समाज में आवासीय भूमि का अभाव नो मेंस लैंड में अतिक्रमण का एक प्रमुख कारण माना जाता है. जिन्हें कहीं भी ठिकाना नहीं मिलता, वे आराम से यहां आशियाना बना लेते हैं. इनमें ग़रीब, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं. नो मेंस लैंड के खंभा संख्या 269/8, जो भारत के अकौन्हा गांव से सटा हुआ है, के पास दर्ज़नों झोपड़ीनुमा घर बने हुए हैं. कुछ ऐसा ही हाल खंभा संख्या 270/9 और 268/6 का है. कहीं पचकौड़ी सदाय झोपड़ी बनाकर रहते हैं, तो कहीं मोहम्मद सुलेमान पक्के मकान में. नो मेंस लैंड क्षेत्र में अतिक्रमण दोनों देशों के नागरिकों द्वारा किया गया है. भारतीय भू-भाग की तुलना में नेपाली भू-भाग में अतिक्रमण अधिक है. इलाक़े में रहने वाले हज़ारों लोगों की अपनी समस्याएं हैं. उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलती है. अधिकांश लोगों के फोटो पहचान पत्र तक नहीं बन पाए हैं. क्षेत्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सटीक बैठती है, जो जितना दबंग है, वह उतने ही बड़े भू-भाग पर क़ाबिज़ है. इन्हीं ग़रीब, अनपढ़ एवं पिछड़े लोगों को प्रलोभन देकर देश विरोधी तत्व यहां शरण पाते हैं. जानकारों का मानना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से से नेपाल पहुंच कर राष्ट्र विरोधी तत्व नो मेंस लैंड में पहले शरण पाते हैं, फिर चुपके से भारत में प्रवेश कर जाते हैं. सीमा क्षेत्र की बनावट ऐसी है कि लगातार चौकसी बरत रहे एसएसबी के जवानों को इसकी हवा तक नहीं लग पाती. तस्कर इस भूमि का उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं. तस्करी का सामान पहले यहां इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे मौक़ा मिलते ही सीमा पार भेज दिया जाता है.

देर से ही सही, मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार का ध्यान इस ओर गया है. नेपाल से सटे बिहार के मधुबनी ज़िले की 74 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात अर्द्धसैनिक बल एसएसबी की 14वीं बटालियन के समादेष्टा बंदन सक्सेना ने नो मेंस लैंड में अतिक्रमण की बात स्वीकार करते हुए बताया कि इस बाबत पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है. बीते दिनों जानकी नगर बीओपी में हुई भारत-नेपाल के अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक में भी नो मेंस लैंड क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श किया गया. इस दौरान चिन्हित स्थलों के नक़्शों का आदान-प्रदान भी किया गया. सर्वेक्षण में पाया गया कि कई स्थानों पर नो मेंस लैंड का खंभा आंगन (चाहरदीवारी के भीतर) तक में है. यदि शीघ्र ही इलाक़े को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो स्थिति और विकट हो सकती है.

भारतीय भू-भाग की तुलना में नेपाली भू-भाग में अतिक्रमण अधिक है. इलाक़े में रहने वाले हज़ारों लोगों की अपनी समस्याएं हैं. उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलती है. अधिकांश लोगों के फोटो पहचान पत्र तक नहीं बन पाए हैं. क्षेत्र में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सटीक बैठती है.

नो मैन्स लैंड एरिया में बना मकान.

भारत-नेपाल सीमा को निर्धारित करने वाला खंभा.

नित्यानंद झा
feedback@chauthiduniya.com

करमापा विवाद की गुत्थी और उलझी

बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच धर्मगुरुओं के प्रति अथाह आस्था के कारण ही बौद्धों के कई पंथों के धर्मगुरुओं को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद होता आ रहा है. कुछ वर्ष पूर्व जापान के एक पंथ के धर्मगुरु द्वारा ख़ुद को भगवान बुद्ध घोषित किए जाने पर विवाद हो गया था. इसी प्रकार बौद्धों एवं तिब्बतियों के पंथ काग्यू कर्मा के धर्मगुरु 17वें करमापा को लेकर पिछले एक दशक से विवाद चरम पर है. यह मामला विभिन्न स्तरों से होते हुए न्यायालय में भी पहुंच चुका है. 17वें करमापा इग्येन थाये दोरजे को दलाईलामा का समर्थन प्राप्त है, दूसरे 17वें करमापा त्रिनले थाये दोरजे को नेपाल, भूटान, भारत एवं तिब्बत समेत अन्य बौद्ध धर्मावलंबियों का समर्थन हासिल है. काग्यू कर्मा पंथ के सोलहवें करमापा द्वारा सिक्किम के रूमटेक बौद्ध मठ में छोड़ी गई अपार संपत्ति पर क़ब्ज़े को लेकर दोनों करमापा के बीच विवाद और बढ़ गया है. 15 दिसंबर 1999 को चीन के त्सुंफु से भागकर नेपाल स्थित पोखरा के रास्ते होते हुए भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला पहुंचने पर भारत सरकार ने इग्येन थाये दोरजे को संरक्षण दिया, जिन्हें 17वें करमापा के रूप में जाना जाता था. इग्येन को दलाई लामा ने चीन से भागकर आने के कारण अपना समर्थन दिया, क्योंकि बताया जाता है कि 17वें करमापा की पहचान इग्येन थाये दोरजे के रूप में किए जाने के बाद चीन सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया था. भारत आने पर अप्रैल 2000 में चंडीगढ़ के पीजीआई में इग्येन थाये दोरजे की 23 दिनों तक चली जांच के बाद वहां के निदेशक डॉ. एस के शर्मा की जो जांच रिपोर्ट आई, उसमें इग्येन की शारीरिक बनावट समेत अन्य कई पहलुओं को उजागर किया गया, जिससे उनके 17वें करमापा इग्येन थाये दोरजे होने के सवाल पर ही संदेह खड़ा हो गया. इग्येन थाये दोरजे का जन्म 26 जुलाई 1985 को हुआ है, लेकिन जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इग्येन थाये दोरजे के रूप में जिस व्यक्ति की जांच की गई है, वह पंद्रह नहीं, बल्कि सत्ताइस-अट्ठाइस वर्ष का है. इस रिपोर्ट ने बौद्धों के बीच 17वें करमापा इग्येन को लेकर विवाद बढ़ा दिया. इसके बाद एक बौद्ध लामा श्रीनारायण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला दायर किया, जिसमें वर्तमान 17वें करमापा इग्येन थाये दोरजे के बारे में सवाल खड़ा करते हुए कहा गया कि क्या यह वही व्यक्ति है, जिसे चीन के त्सुंफु में करमापा की गद्दी दी गई थी? उसकी वास्तविक उम्र क्या है? वह कहीं इग्येन थाये दोरजे से मिलते-जुलते रूप वाला कोई दूसरा व्यक्ति तो नही है? कहीं चीन सरकार ने उसे किसी मिशन पर तो नहीं भेजा है? अगर ये सब बातें नहीं हैं तो दलाईलामा के बाद उसे क्यों अधिक तरजीह दी जा रही है? यह मुक़दमा कई वर्षों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हाल में ख़ारिज़ कर दिया गया. हालांकि बौद्धों के बीच इस बात की अधिक चर्चा है कि सिक्किम के रूमटेक बौद्ध मठ की अपार संपत्ति पर कई लोगों की टेढ़ी नज़र है. इस मठ पर करमापा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से क़ब्ज़े को लेकर ज़िला जज गंगटोक के न्यायालय में 40/96 के तहत एक मामला दर्ज़ कराया गया था, जो अभी तक लंबित है. ट्रस्ट का कहना है कि मठ की संपत्ति उसकी है, इसलिए उसे लौटा दी जाए. जबकि इस रूमटेक मठ की देखरेख करने वाला धर्मचक्र ट्रस्ट अपना दावा जताता है. इस विवाद के बाद सिक्किम हाईकोर्ट के आदेश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर को रूमटेक मठ की संपत्ति की सूची बनाने के लिए आयुक्त नियुक्त किया गया. सिक्किम सरकार की ओर से उस समय वरिष्ठ आईएएस एन दोरजे प्रतिनिधि थे. फ़िलहाल रूमटेक मठ की सारी संपत्ति सील है और मामला न्यायालय में है. इन्हीं सब बातों को देखते हुए भारत सरकार ने इग्येन थाये दोरजे को 17वां करमापा न मानते हुए उन्हें दी गई सारी सुविधाएं वापस ले ली. गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को फैक्स भेजकर इस बात से अवगत भी कराया. फैक्स में कहा गया है कि भारत सरकार उन्हें 17वां करमापा नहीं मानती है. अत: प्रवास के दौरान उन्हें कोई सरकारी सुविधा न दी जाए, जिसके चलते इग्येन थाये दोरजे से जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस लेकर सिर्फ़ एक्स श्रेणी की सुरक्षा दी गई. संदेह के घेरे में आने के कारण भारत सरकार इग्येन थाये दोरजे को यूरोप एवं अन्य पश्चिमी देशों में जाने की अनुमति नहीं दे रही है. 2008 में सिर्फ़ दो सप्ताह के लिए भारत सरकार ने इग्येन को यूएसए जाने का वीजा दिया था.

इसके बाद से बौद्धों का पवित्र स्थल बोधगया दोनों 17वें करमापा का प्रदर्शन स्थल बन गया. हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच दोनों अपने-अपने समर्थकों के साथ विश्व शांति के लिए करमा काग्यु मोनलम पूजा करते हैं. बताया जाता है कि त्रिनले थाये दोरजे के विश्व के विभिन्न देशों में 655 धर्मकेंद्र और बौद्ध मठ हैं, जहां वह धर्म का प्रचार करते हैं. त्रिनले थाये दोरजे तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत और दूसरे देशों के लोगों का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि इग्येन थाये दोरजे भारत में ही घूमकर तिब्बत की आज़ादी के लिए दूसरे देशों से समर्थन मांगते हैं. त्रिनले थाये दोरजे 17वें करमापा के साथ-साथ भूटान के राजगुरु भी हैं और उन्हें भूटान की नागरिकता हासिल है. उनके मूल मठ दार्जिलिंग के पास कलिंगपोंग एवं दिल्ली में करमापा इंटरनेशनल बुद्धिष्ट इंस्टीट्यूट हैं. करमापा के पवित्र पद को लेकर विवाद के बाद से दुनिया के बौद्धों के बीच वैमनस्य और ईर्ष्या में बढ़ोतरी हुई है. ऐसा ख़ुद बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है.

इग्येन थाये दोरजे.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

मज़दूरों की रोज़ी-रोटी छीनी

कहते हैं, पेट की भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है. इसी के चलते कुछ लोग वतन बदर होकर परदेश में रोज़ी-रोटी की तलाश करते हैं. घर छोड़ अपनों से दूर रहकर कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और झमाझम बरसात के मौसम में उन्हें पेट की ख़ातिर सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करना होता है. कुछ ऐसी ही व्यथा है झारखंड राज्य के पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा आदि ज़िलों से बिहार के रोहतास, कैमूर एवं भोजपुर में मज़दूरी करने आने वाले प्रवासी मज़दूरों की. चाहे धान काटने का मौसम हो या गेहूं की कटाई या फिर धान की रोपनी का वक़्त, विकट बरसात के मौसम में भी ये मज़दूर अपने पूरे परिवार के साथ जिसमें दुधमुंहे बच्चे भी शामिल होते हैं, इन ज़िलों में आ जाते हैं. यहां मज़दूरी करने की यह परंपरा कई दशक पूर्व शुरू हुई थी. कहा जाता है कि जब सोन कैनाल से रोहतास एवं उसके आसपास के ज़िलों को पानी मिलना शुरू हुआ और उपज दिन दूनी-रात चौगुनी बढ़ी तो बगल में बसे आदिवासी परिवारों के भूखे नौजवान बरबस ही इस हरे-भरे इलाक़े में चले आए. लेकिन, अब परिस्थितियां धीरे-धीरे बदल रही हैं, जिसके कारण खेतों में बड़े-बड़े दैत्याकार हार्वेस्टर चलने लगे. इनके चलने से मज़दूरों के पेट पर पड़ी लात की चोट और गंभीर होती गई. पलामू ज़िले के विश्रामपुर थानान्तर्गत रजदिरिया से रोहतास के पिपरी गांव में धनकटनी करने पहुंचे मज़दूर मगु चेरो की बात मानें तो मात्र पांच साल पहले उसके गांव से इस इलाक़े में 200 से ज़्यादा मज़दूर आते थे, लेकिन अब यह संख्या 50 से 60 के बीच सिमट कर रह गई है. इसके पीछे केवल मज़दूरी ही मूल कारण है. पहले एक मज़दूर को 5 से 8 क्विंटल मज़दूरी मिलती थी, अब यह घटकर 4 से 6 क्विंटल के आसपास हो गई है. अब इतनी कम मज़दूरी में पेट कैसे भरे, यह एक यक्ष प्रश्न है.

धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास की धरती पर सरपट दौड़ते हार्वेस्टरों ने इन मज़दूरों के हाथों से एक महीने की मज़दूरी छीन ली है. इस एक महीने में इतनी कमाई हो जाती थी, जिससे पूरे परिवार को दाल-भात मिल जाता था. यही नहीं, यहां की पत्थर खदानों में भी लगभग 5 हज़ार प्रवासी मज़दूर काम करते हैं, जिनकी मासिक कमाई 5 से 6 हज़ार रुपये प्रतिमाह है. अब इन जगहों पर भी जेसीबी एवं हिटैची जैसी बड़ी मशीनें काम करने लगी हैं, जिससे पत्थर व्यवसाइयों की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन प्रवासी मज़दूरों की परेशानी बढ़ती गई. नावा बाज़ार निवासी राजबली भुइया कहते हैं कि अब हम लोग यहां धान काटने के लिए कभी नहीं आएंगे, क्योंकि यहां उतनी मज़दूरी भी नहीं मिल पाती, जितनी हम जंगलों से लकड़ी चुनकर बाज़ारों में बेचकर प्राप्त कर लेते हैं. एक अनुमान के मुताबिक़, रोहतास में निकटवर्ती झारखंड राज्य से प्रति साल आने वाले प्रवासी मज़दूरों की संख्या 50 हज़ार से लेकर एक लाख के बीच होती है. प्रवासी मज़दूरों की घटती संख्या आने वाले दिनों के लिए कोई बेहतर संकेत नहीं है, क्योंकि ख़राब मौसम में जब फ़सल ज़मीन पर गिर जाती है और खेत गीले होते हैं तो मज़दूरों की ही ज़रूरत पड़ती है. अगर वे नहीं पहुंच पाए तो समझो कि धान के कटोरे में उपज का बेड़ा गर्क होने वाला है. यही नहीं, हार्वेस्टरों के प्रचलन से पशुओं के चारे पर भी आफ़त के आसार दिख रहे हैं.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

विकलांग रोहित विदेशियों को सैर करा आया

लोग विकलांगता को अभिशाप बताते हैं, लेकिन अगर आप में विकलांगता से लड़ने का जोश, ज़ज़्बा और जुनून है तो फिर यह अभिशाप नहीं रह जाता है. उसके बाद तो सारा आकाश आपकी पहुंच के अंदर होता है. कुछ इसी तरह का जोश और ज़ज़्बा दिखाया है रोहित ने. उनकी ख़राब आर्थिक दशा भी उनके उत्साह को नहीं डिगा पा रही.

ऐसा कहा जाता है कि बचपन में दोनों पांव गंवाने के बाद इंसान अपनी ही ज़िंदगी से नफ़रत करने लगता है. इतना ही नहीं वह सही तरीक़े से ज़िंदगी जीने की तमन्ना भी छोड़ देता है, लेकिन एक उक्ति है – असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो! क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो! इस पंक्ति ने रोहित के आत्मबल को कुछ इस तरह मज़बूत किया कि वह ख़ुद तो बैशाखी के सहारे चलता रहा, लेकिन कई विदेशी सैलानियों को भारत की सैर करा आया. बिहार के खगड़िया जैसे अत्यंत पिछड़े ज़िले के एक बेहद ग़रीब परिवार में जन्मे रोहित को ज़िला प्रशासन की तरफ़ से कभी भी ट्राईसाइकिल या फिर बैसाखी नहीं मिली, लेकिन इससे उसके भ्रमण की लालसा पर कोई असर नहीं पड़ा. उसे कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि वह विकलांग है और अपने पांव पर चलकर दुनिया देखने की लालसा पूरी नहीं कर सकता है. हालांकि उसे इस बात का मलाल है कि कई विदेशियों को भारत का सैर कराने के कारण लोग उसे टूरिस्ट गाइड तो कहने लगे, लेकिन लाचारी ने उसे वहीं का वहीं छोड़ दिया. विदेशियों को भारत की सैर कराते-कराते रोहित कब फ्रेंच एवं अंग्रेज़ी भाषा जानने और बोलने लगा, इसका पता उसे भी नहीं चला. इस होनहार युवक की बदक़िस्मती उसे वापस खगड़िया ले आया. वैसे रोहित कहता है कि स्नातकोत्तर करने की इच्छा थी इसलिए वह वापस खगड़िया लौटा था, लेकिन जब सरकारी स्तर पर उसे कोई मदद नहीं मिली तो वह निराश हो गया. वह फिर से टूरिस्ट गाइड का काम करना चाहता है. रोहित अपने बीते दिनों की याद ताज़ा कर कहता है कि लगभग दो वर्ष की उम्र में ही वह पोलियो का शिकार हो गया. घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि चाहकर भी उसके पिता हेमचंद्र सहनी और माता उर्मिला उसे एक अदद बैसाखी नहीं दे पाए. हालांकि अभी भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है. पिता रिक्शा चलाकर किसी तरह बच्चों का पेट भरते हैं. सरकारी योजना के तहत उसे कोई घर उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए वह अभी भी सड़क किनारे किसी तरह तंबू गाड़कर रहने को विवश है. रोहित कहता है कि बचपन में जब उसे वैसाखी नहीं मिल पा रही थी तब किसी की कही बातों पर भरोसा कर वह वैसाखी पाने की चाहत लिए जयपुर स्थित भगवान महावीर विकलांग संस्थान पहुंच गया. जब वापस लौटा तो उसके पास वैसाखी तो थी, लेकिन जीने की चाह आसान नहीं दिख रही थी. इसी बीच वैसाखी के साथ वापस घर लौटने के क्रम में उसकी मुलाकात जयपुर स्टेशन पर जनकल्याण साहित्य नामक एक संस्था के कुछ सदस्यों से हो गई. रोहित को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी लेते हुए संस्था के सदस्यों ने उसका नामांकन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानसरोवर में करा दिया. उसके बाद रोहित ने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी. रोहित ने दसवी में 69.5 और बारहवीं में 65.38 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. इस दौरान रोहित ने टूरिस्ट गाइड का भी काम कर कॉपी-किताब के ख़र्चे निकालने शुरू कर दिए. जयपुर आने वाले टूरिस्ट को घूमाने के क्रम में रोहित ने फ्रेंच, अंग्रेजी आदि भी बोलना सीख लिया. बारहवीं पास करने के बाद संस्था के सचिव ने कहा कि 18 वर्ष का हो जाने के कारण अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए संस्था कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकती है. उसके बाद रोहित को याद आई कि घूमने-घुमाने के क्रम में कैलिफोर्निया के स्कॉट हर्मिसन ने उसे मदद का भरोसा दिलाया था. इसी बात को याद करते हुए उसने कैलिफोर्निया के स्काट हर्मिसन से मदद की गुहार लगाई. रोहित के गुहार के बाद स्कॉट हर्मिसन ने उसकी मदद की. अपनी पढ़ाई के साथ-साथ उसने अपने छोटे भाई को भी 9वीं से 12वीं तक की तालीम दिलाई. इस दौरान पार्ट टाइम जॉब के रूप में रोहित ने हेल्प लाइन में नौकरी और गाइड के रूप में टूरिस्टों को घुमाने का कार्य जारी रखा, लेकिन स्नातक की पढ़ाई समाप्त होते-होते अंग्रेज दोस्त ने भी मदद रोक ली. भाई और अपनी पढ़ाई का ख़र्च वहन नहीं करने के कारण रोहित वापस खगड़िया लौट आया, लेकिन यहां भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई. विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए चार सौ रुपये की मांग कर्मचारी द्वारा की गई. बाद में एक छात्र संगठन की पहल पर उसे विकलांग प्रमाण-पत्र तो मिल गया, मगर कोई सरकारी सहायता नहीं मिली. रोहित फ़िलहाल एक कंप्यूटर संस्थान में बच्चों को कंप्यूटर के गुर सिखा रहा है. वहीं घर पर ग़रीब छात्रों को नि:शुल्क शिक्षा देने के अभियान में जुटा हुआ है. वह अंग्रेज़ी से पीजी और पीएचडी करना चाहता है. रोहित ने बताया कि उसकी मां कहती है कि जिस दिन एक साक्षर दो निरक्षरों को पढ़ाना शुरू कर देगा, उस दिन पूरा देश साक्षर हो जाएगा. इसलिए वह प्रोफेसर बनकर समाज के हर युवा को साक्षर करना चाहता है. बहरहाल, रोहित का कहना है कि राज्य या केंद्र सरकार अगर सही मायने में विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने की सोच रखती है तो उसे हवाई बातों को छोड़ वास्तव कुछ सार्थक पहल करनी होगी. तभी समाज के लिए विकलांगता अभिशाप नहीं कहा जाएगा, वैसे विकलांगों को भी यह चाहिए कि उसे अभिशाप नहीं मानें, बल्कि एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करें और समाज के लिए प्रेरणा बनने की मुहिम में जुटे रहें.

राजेश सिन्हा
feedback@chauthiduniya.com

ज्ञान भारती आवासीय परिसर
मैनिया, बोधगया
फोन-0631-2200510, 641053,/2, 3201645, 9334743810
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा +2 स्तर सम्बद्धता प्राप्त (Affiliation No. 330012)

Admission Notice-Session 2010-11
DATE OF ADMISSION TEST-21 Feb.2010 (Sunday)
from 10:30 A.M. To 12:30 P.M. at School Premisses.
- Registration going on for Nursery to IX.
- Registration form can be obtained on a payment of Rs. 300/- from the office.
- Prospectus available free of cost.

भगवान बुद्ध की जन्मस्थली बोधगया स्थित ज्ञान भारती आवासीय परिसर स्थापना के मात्र कुछ ही वर्षों में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक उत्कृष्ट सह शिक्षा केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। यहां के छात्र-छात्राओं ने अनुभवी शिक्षकों के कुशल नेतृत्व में देश के अति प्रतिष्ठित आईटीआई, ऑल इंडिया मेडिकल एक्जामिनेशन, आईआईएम, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, आईएसएम, लॉ कॉलेज हैदराबाद तथा राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम तथा शिक्षकों का स्वाभिमान बढ़ाया है। इस विद्यालय के विशाल परिसर में अपना भव्य भवन, क्रीड़ा स्थल, पुस्तकालय, विकसित प्रयोगशाला, लघु तरणताल तथा कम्प्यूटर रूम है।

इस विद्यालय के प्रांगण में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम ए.आर. किदवई, महामहिम आर.एस.गवई, सेवानिवृत जनरल एस.के. सिन्हा, सेना सेवा कोर (उत्तर) के कमान्डेण्ट बिगेडियर तरसेम सिंह, पटना विश्वविद्यालय के आचार्य व मानस मर्मज्ञ राम तवक्या शर्मा, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति अभिमन्यू सिंह तथा अन्य गणमान्य शिक्षाविद पधार कर अपना आर्शिवाद दिया है।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. अनिल कुमार तथा मगध रेंज के तत्कालीन डी.आई.जी. अरविन्द कुमार पाण्डेय का आगमन भी छात्र-छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। इस विद्यालय के सर्वांगीण विकास का श्रेय अनुभवी शिक्षकों तथा माननीय प्रशासक श्री अरविन्द कुमार की कार्यकुशलता को जाता है।

अरविन्द कुमार
प्रशासक

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

वर्तमान में जिन तालाबों में मछली का उत्पादन किया जा रहा है, इन तालाबों से जुड़े किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ भी नहीं मिल पा रहा है.

रानी चटर्जी का हॉट अवतार

अभी कुछ दिनों से रानी चटर्जी की चर्चा ज़ोरों पर है. वही रानी चटर्जी, जो भोजपुरी फ़िल्मों की चर्चित तारिका हैं, जिनके बारे में हमेशा कुछ खट्टी-मीठी बातें सुनने को मिल ही जाती है. अभी ज़्यादा दिन नहीं गुज़रे हैं, जब रानी रवि किशन के साथ फ़िल्म *हम बाहुबली* में देसी ठुमके लगाती नज़र आईं थीं. और अब सामने है उनका नया ग्लैम अवतार.

दशकों से अपने सशक्त अभिनय और बिंदास अंदाज़ के लिए मशहूर रही रानी पहली बार भोजपुरिया परदे पर हॉट अवतार में नज़र आने वाली हैं. रानी त्रिषि इंटरनेशनल और एके मीडिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी भोजपुरी फ़िल्म *जब केहू दिल में समा जाला* में पहली बार हॉट एंड हिट अवतार में नज़र आएंगी. रानी इस फ़िल्म में एक मॉडल की भूमिका में हैं, जो काफ़ी ख़ूबसूरत और सेक्सी है. अगर रानी फ़िल्म सुपर मॉडल के अंदाज़ में होंगी तो ज़ाहिर है कि उनका मेकओवर तो होगा ही. इसी मेकओवर का नतीजा है उनका यह नया अवतार. जब रानी से इस मेकओवर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी भूमिका ही सुपरमॉडल की है तो ऐसे में साड़ी पहनना तो मुमकिन नहीं है. लिहाज़ा ग्लैमरस तो दिखना ही पड़ेगा. अशोक गुप्ता द्वारा निर्मित और मिथिलेश- अविनाश निर्देशित इस फ़िल्म में भोजपुरिया सुपरस्टार पवन सिंह, रानी चटर्जी के प्रेमी की भूमिका में हैं. यह फ़िल्म फरवरी में रिलीज होन जा रही है. इस फिल्म के सह-निर्माता हरीश गुप्ता एवं कार्यकारी निर्माता केडी जायसवाल हैं. बहरहाल, अब देखना यह है कि भोजपुरिया दर्शकों पर रानी चटर्जी का यह हॉट अवतार और मेकओवर क्या कमाल दिखा पाता है.

मछली को तरसे मिथिलावासी

मिथिला क्षेत्र में पान, मखान और मछली का विशेष स्थान है. यहां तक कि शादी-ब्याह के रीति-रिवाज भी ऐसे हैं जिसमें इन चीज़ों की लेनदेन की जाती है. इस वजह से इसकी खपत मिथिला क्षेत्र में काफ़ी अधिक होती है. लेकिन ग़ौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि खपत की तुलना में उत्पादन काफ़ी कम होता है. जिसके चलते आंध्रप्रदेश और देश अन्य भागों से मछलियां मंगवानी पड़ती है. अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो बिहार के मिथिला क्षेत्र और दूसरे भागों में ही मछली का उत्पादन बढ़ सकता है.

मछली उत्पादन के मामले में पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखने वाला मिथिलांचल और उसके आसपास का क्षेत्र अपने इलाक़े के उपभोक्ताओं की ज़रूरतें पूरी कर पाने में असक्षम हो गया है. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मछली की आपूर्ति करने वाला यह क्षेत्र फ़िलहाल अपने ही लोगों के लिए आंध्रप्रदेश समेत देश के अन्य प्रदेशों की मछलियों पर आश्रित हो गया है.

इस प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर ज़िले में हाल के वर्षों में हुए मछली उत्पादन की दर को देखा जाए तो इन जगहों पर क्षमता का लगभग आधा ही उत्पादन हुआ है. अगर यह प्रक्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त भी कर लेता है, तो भी मिथिलांचल का यह प्रक्षेत्र मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा. मछली खाने वालों की संख्या में हो रही लगातार वृद्धि के सापेक्ष मछली उत्पादन हेतु निर्धारित नीतियों का अभाव सर्वाधिक महसूस किया जा रहा है. न तो खपत के अनुकूल राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और न ही नए तालाबों के अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.

वर्तमान में जिन तालाबों में मछली का उत्पादन किया जा रहा है, इन तालाबों से जुड़े किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ भी नहीं मिल पा रहा है. किसानों के सामने तालाबों की सफ़ाई, मछली फ़सल बीमा का अभाव, उत्पादन की नई तकनीक को अनुप्रयोग में नहीं लाया जाना, बाढ़ व सुखाड़ जैसी समस्याएं चुनौती बन कर खड़ी हैं. इन्हीं कारणों से मछली उत्पादन के प्रति किसानों की उदासीनता बढ़ी है और किसान परंपरागत तकनीक से मछली का उत्पादन करने के लिए विवश हैं. फलस्वरूप अनुमानित लक्ष्य का सिर्फ़ 70 प्रतिशत ही उत्पादन हो पा रहा है, जो कि लगभग 58 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम है. यूं तो मछली के बीज के उत्पादन के मामले में दरभंगा प्रक्षेत्र ने उत्तर बिहार को आत्मनिर्भर बना दिया है, लेकिन मछली उत्पादन के मामले में राज्य सरकार की नीति ही तय करेगी कि प्रदेश कब तक आत्मनिर्भर हो सकेगा. दरभंगा प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मधुबनी,

क्र.	ज़िला का नाम	तालाबों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (हज़ार मीट्रिक टन में)
1	मधुबनी	3554	1910.15	11.75
2.	दरभंगा	1640	3054.75	13.50
3.	समस्तीपुर	1247	2477.4	07.90

मछली उत्पादन के मामले में पूरे प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता रखने वाला मिथिलांचल और उसके आसपास का क्षेत्र अपने इलाक़े के उपभोक्ताओं की ज़रूरतें पूरी कर पाने में अक्षम हो गया है.

दरभंगा और समस्तीपुर ज़िले में मत्स्य पालन केंद्रों की संख्या पच्चीस के क़रीब है, जिससे 128 मिलियन फ्राई (मछली बीज) का उत्पादन होता है.

हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, दरभंगा प्रक्षेत्र के अतंर्गत लगभग बीस हज़ार तालाब हैं. इनमें अन्य तालाबों की तरह रेहु, कतला, निर्गल (नैनी), कॉमन कॉर्प, ग्रास कॉर्प व सिल्वर कॉर्प जैसी मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है. अगर इन तालाबों का अधिग्रहण मछली उत्पादन के लिए किया जाता है, तो निश्चित रूप से प्रदेश मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा. फ़िलहाल इस प्रक्षेत्र के सिर्फ़ 6441 तालाबों में ही मछली का उत्पादन किया जा रहा है. 7442.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इन तालाबों से 33.15 हज़ार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 46.24 हज़ार मीट्रिक टन है. उत्पादकता की दृष्टि से इन तालाबों की उत्पादन क्षमता लगभग 60.5 हज़ार मीट्रिक टन है. इस क्षेत्र में लगभग 56 हज़ार मीट्रिक टन मछली की खपत होती है.

ऐसे में यह अनुमान लगाना सहज है कि उत्पादकता के अनुकूल मछली का उत्पादन कर कम से कम इस क्षेत्र की खपत को तो नियंत्रित किया ही जा सकता है. निर्धारित लक्ष्य के अनुकूल मछली का उत्पादन नहीं होने के संबंध में दरभंगा प्रक्षेत्र के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी भारतेंदु जयसवाल ने बताया कि क्षेत्र के किसान अर्ध सघन अथवा सघन उत्पादन की पद्धति को अपनाने के बजाए परंपरागत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. फलस्वरूप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली है. वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर ही पूर्ण लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

भारतेंद्र
feedback@chauthiduniya.com

नक्सल विरोधी अभियान का भंवरजाल

झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट को लेकर अजीबोग़रीब स्थिति बनी हुई है. देश केअन्य राज्यों में नवंबर 2009 से ही इसकी शुरुआत हो गई है. इसके लिए पारा मिलिट्री फोर्स केपचास हज़ार जवान लगाए गए हैं. माओवादियों का रेड कॉरिडोर इसका मुख्य निशाना है. ग़ौरतलब है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के कारण इस अभियान को रोका गया था. चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन की सरकार बन गई. उन्हें नक्सलियों का समर्थक माना जाता है. वह उन्हें भाई-बंधु कहते रहे हैं. चुनाव में भी उन्होंने चार नक्सलियों को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था. उन्हीं के समर्थन से गुरुजी 18 सीटें निकाल पाने में सफल रहे. इसलिए उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान को रोककर उनसे वार्ता के ज़रिए हल निकालने की कोशिश की, लेकिन अभी तक सत्ता और नक्सलियों के बीच सही ढंग से मध्यस्थता नहीं कर पाए हैं. अब उन पर ऑपरेशन को रोकेरखने का आरोप लगने लगा. बाद में उन्होंने नक्सलियों को 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है. 28 जनवरी को उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम से मिलकर वस्तु-स्थिति पर चर्चा की. वे कार्रवाई केविरोध में नहीं, लेकिन वार्ता के ज़रिए हल निकालने के पक्ष में हैं.

माओवादी नेता किशन जी एक बार फिर अपनी शर्तों पर वार्ता के लिए सहमति जता चुके हैं. उनकी शर्तें केंद्र सरकार को मान्य होंगी या नहीं अथवा कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, इस मसले पर अभी तक केंद्र सरकार ने अपना मंतव्य ज़ाहिर नहीं किया है.

माओवादी नेता किशन जी एक बार फिर अपनी शर्तों पर वार्ता के लिए सहमति जता चुके हैं. उनकी शर्तें केंद्र सरकार को मान्य होंगी या नहीं अथवा कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, इस मसले पर अभी तक केंद्र सरकार ने अपना मंतव्य ज़ाहिर नहीं किया है. सरकार चाहती है कि वे पराजित योद्धा की तरह पहले सरकार की घोषित नीति के तहत आत्मसमर्पण करे फिर वार्ता करे. माओवादी सम्मानजनक तरीक़े से वार्ता पर राजी हो सकते हैं. सरकारी नीति उन्हें मान्य नहीं है. शिबू सोरेन मध्यस्थता कर रास्ता निकालने केप्रयास में लगे हैं, लेकिन इस समस्या को वह सिर्फ़ झारखंड के संदर्भ में देख रहे हैं, जबकि यह राष्ट्रीय समस्या है और वार्ता केंद्र सरकार के स्तर पर ही हो सकती है.

पुलिस के नए मुखिया नेयाज अहमद और गृह सचिव जेबी तुविद का कहना है कि ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसा कुछ नहीं है, लेकिन झारखंड में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान की तैयारी लगभग साल भर से चल रही है. इस दिशा में उन्होंने 75 प्रतिशत कार्य पूरा होने का दावा किया. यह भी कहा चुनाव के कारण रुकी तैयारी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने मुख्यमंत्री के नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने और अनावश्यक हिंसा से परहेज करने के आह्वान को जायज़ ठहराया.

नेयाज अहमद निगरानी विभाग के मुखिया हैं. डीजीपी पद की उन्हें हाल में ही ज़िम्मेदारी मिली है. पूर्व डीजीपी वीडी राम एस एस फंड घोटाले के आरोपी रहे हैं. शिबू सोरेन की पिछली पारी और राष्ट्रपति शासन काल तक वे अपना बचाव करने में सफल रहे, लेकिन इस बार शिबू सरकार बनने के बाद उन पर गाज गिरी. उनकी जगह नेयाज अहमद डीजीपी बन गए, लेकिन नेयाज साहब के सिर पर उन्होंने कांटों का ताज़ रखा है. एस एस फंड का मुख़बिरों के बीच वितरण नहीं होने के कारण उनकेकार्यकाल में झारखंड पुलिस का सूचना तंत्र छिन्न-भिन्न हो चुका है. इसे नए सिरे से समायोजित और विकसित करना नेयाज साहब केलिए गंभीर चुनौती है. मजबूत सूचना तंत्र केबिना नक्सलियों को नियंत्रित करना संभव नहीं है. ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत पड़ी तो सही सूचनाओं केअभाव में आम ग्रामीणों पर क़हर टूटेगा. इससे समस्या और जटिल होगी.

नवल किशोर सिंह
feedback@chauthiduniya.com